चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 30 अक्टूबर– 05 नवंबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

नॉर्थ कोरिया-अमेरिका विवादः साउथ चाइना सी से संतोष भारतीय की ग्राउंड रिपोर्ट

तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो भारत भी सुरक्षित नहीं

मैं उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच झगड़े को लेकर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर और चीन के लोगों के मन की बात जानने की कोशिश कर रहा था. मैं ये सारी बातें साउथ चाइना सी से लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे उत्तर कोरिया जाने की इजाजत नहीं मिली. इस दौरान मेरी उन देशों के नागरिकों से कई मौकों पर बातचीत हुई. उन लोगों ने मुझे जो बताया, वो बातें मेरी लिए काफी आश्चर्यजनक थीं. मेरी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, सिंगापुर और जापान के लोगों और डिफेन्स एक्सपर्ट से भी बातचीत हुई. मै साउथ चाइना सी तक गया. इसी बातचीत और यात्रा के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है.

संतोष भारतीय

साउथ कोरिया के लोगों ने कहा कि वे शांति चाहते हैं. वे नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो. ये बात उन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर बताई. उनका कहना है कि हम अपने जीवन के इन क्षणों को, इन लम्हों को जीना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद में पड़ें. वहां के आदमियों और औरतों दोनों की एक ही मानसिक स्थिति है कि वो शांति चाहते हैं, वो युद्ध नहीं चाहते. हालांकि वे अमेरिका के राष्ट्रपति से गुस्सा हैं, क्रोधित हैं, लेकिन वे इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं. उनका कहना है कि जब तक जिंदगी है, तब तक खुल कर और खुश होकर जीयो. जब मैंने पूछा कि उत्तर कोरिया के लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे, तो उन्होंने कहा कि 60 साल पहले हम एक-दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन अब 60 वर्षों से हम अलग हैं. हमारे नौजवान बच्चे जब कभी विदेश जाते हैं, तो कभी आपस में उनकी मुलाकात हो जाती है, पर उनका अब कोई बहुत दिली लगाव नहीं है. लेकिन वो यह नहीं मानते कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कोई बहुत जुनूनी आदमी हैं. उनका मानना है कि उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है और जापान उन्हें बहुत परेशान कर रहा है.

साउथ चाइना सी बनेगा युद्ध का अखाड़ा

जापान के लोगों से भी बातचीत हुई. वे यह कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया उनके देश के लिए एक बड़ा खतरा बनकर खड़ा है. अगर उत्तर कोरिया को कंट्रोल नहीं किया गया, तो उनका देश कभी भी रसातल में जा सकता है. चीन के लोग इस मसले पर सिर्फ मुस्कराते हैं. हालांकि वो जानते हैं कि जब युद्ध हुआ तो जापान और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के साथ-साथ वे भी लड़ाई के दायरे में आ सकते हैं. अगर बम चले, युद्ध हुआ तो जिसे हम इंडियन ओसन कहते हैं या जिसको साउथ चाइना सी कहते हैं, ये युद्ध के बड़े अखाड़े होंगे. यहां पर मिसाइल भी दागी जाएंगी, युद्धपोत भी आएंगे, लेकिन कोई भी युद्ध नहीं चाहता है.

आग कौन भड़का रहा है

उत्तर कोरिया के सिर्फ एक आदमी से बड़ी मुश्किल से बात हो पाई. उसने बात की, पर पहले कहा कि आप कागज और कलम हाथ में नहीं लीजिएगा. उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन कोई है, जो आग भड़का रहा है. आग कौन भड़का रहा है, यह पूछे जाने पर उसने स्पष्ट कहा कि अमेरिका. सबसे बड़ी बात, जो उसने कही कि हमारे यहां लोग साउथ कोरिया के लोगों जैसे सुखी नहीं हैं, लेकिन हम भूखे नहीं मर रहे हैं. हमारे यहां परेशानियां हैं, लेकिन हम भूखे नहीं हैं. हमारे राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन खोज में लगे वैज्ञानिकों की खूब मदद करते हैं. देश की सुरक्षा के लिए हथियारों की खोज में लगे वैज्ञानिकों के लिए यहां सभी साधन मौजूद हैं. लेकिन उनके मन में ये बात जरूर है कि किसी भी तरह उनके देश का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा हो सके. यहां के लोगों को ये भी नहीं लगता कि युद्ध होगा. उन्हें ये भी लगता है कि युद्ध होगा, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो सामान्य नागरिक हैं. युद्ध अगर रोकना है तो वो अमेरिका और किम जोंग उन के हाथ में है. साउथ कोरिया

के हाथ में भी नहीं है. हालांकि साउथ कोरिया और जापान इसके पहले शिकार होने वाला हैं.

जब युद्ध होगा, तब देखा जाएगा

राष्ट्रपति ट्रम्प का कोई ठिकाना नहीं है कि वे कब, क्या कर बैठें? हो सकता है, फैसला भी ले लें कि उत्तर कोरिया के ऊपर बमबारी नहीं करनी है. पर मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया को कहीं न कहीं अमेरिका से जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ये करेगा और उसके पहले ही एक बम जापान के ऊपर और एक बम दक्षिण कोरिया के ऊपर डाल देगा. मैं सूत्र नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ऊपर की बातचीत से ये छाप पड़ी है. इस क्षेत्र के लोग, जो अब धमकियों से ऐसा चुके हैं, का कहना है कि जब युद्ध होगा, तब देखा जाएगा. अभी तो जीयो, खाओ और जमकर शैंपेन पीओ. मेरा ख्याल है कि यह पूरा नॉनवेज इलाका है और सीफूड इनका प्रिय भोजन है. ये लोग इस समय खाने-पीने और जीने में लगे हुए हैं.

द. कोरिया सेना की कमांड अमेरिकी हाथों में

एक नई चीज पता चली कि साउथ कोरिया की पूरी सेनाओं का कमांड अमेरिका के पास है. साउथ कोरिया में बहुत हलचल मच रही है कि ये कमांड उनके पास क्यों है? सांग मू यंग वहां के रक्षा मंत्री हैं. उन्होंने ये कहा है कि आप निश्चिंत रहिए. हम यूनीफाइड कमांड, जिसके अंतर्गत साउथ कोरिया की सेनाएं हैं, जिसे ओपीसीओएन कहते हैं, उनसे वार टाइम ऑपरेशन कंट्रोल जल्द लेने वाले हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रेसिडेंट मून जो-इन लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा. अब ये जो नई चीज पता चली है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो रिश्ते हैं, उसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया से डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन का ऑप्शन छीन लिया है. डिप्लोमैटिक ऑप्शन छीन जाने से अब ये लड़ाई साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच न होकर, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच हो गई है.

मेरी एक नॉर्थ ईस्टर्न एशियन डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि अब यह अमेरिका की सुरक्षा का मसला बन गया है, इसलिए अमेरिका ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है. मौजूदा प्रेसिडेंट ट्रम्प इन चीजों को हाथ में लेकर अपने दिमाग से इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन साउथ कोरिया की जनता लड़ाई नहीं चाहती है और इसके लिए वहां प्रेशर बनाए हुए है. इसीलिए शायद प्रेसिडेंट मून जो-इन कोशिश कर रहे हैं कि उनके कमांड की सेना उनके हाथ आ जाए. दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल और शक्तिशाली बम हैं. लेकिन अभी तक अमेरिका और साउथ कोरिया को यह पता नहीं है कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है, वह युद्धक बम या हाइड्रोजन बम को अमेरिका तक ले जाने में सक्षम है या नहीं. अमेरिका को ये डर है कि नॉर्थ कोरिया ने अगर किसी दिन उन पर हमला शुरू कर दिया, तब क्या करेंगे? दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका के टॉप ट्वन्टी बिजनेसमैन में से रह चुके हैं, तो वे कभी भी इस हद तक नहीं जाएंगे कि दोनों में वार हो जाए.

इसके लिए उन्होंने मुझे एक उदाहरण भी दिया, उनका कहना है कि साउथ कोरिया की दो बड़ी कंपनियां एलजी और सैमसंग हैं. इनका अमेरिकी ऑपरेशन बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं कि अमेरिका में उनका ऑपरेशन और बढ़े. इसीलिए उन्होंने दबाव डाला कि होम अप्लायंस और सफाई की मशीनों पर एलजी 250 मिलियन और सैमसंग 300 मिलियन डॉलर वहां इनवेस्ट करे. इसके तहत सैमसंग इतना पैसा खर्च कर अमेरिका में करीब 950 नौकरियां और एलजी 600 नए जॉब क्रिएट करेगा. प्रेसिडेंट ट्रम्प यह दबाव डाल रहे हैं कि दोनों कंपनियां अपने देश साउथ कोरिया पर दबाव डालें कि वो नॉर्थ कोरिया मसले को लेकर अमेरिकी रणनीति के ऊपर चलें.

मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग कर रहे ट्रम्प

अमेरिका ने एक और खतरनाक काम किया. बी1बी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स हैं. बी1बी बॉम्बर्स कई बार रात में उड़े और एक बार तो खुलेआम तैनात किए गए. जब ये बॉम्बर्स रात में उड़े, तब व्हाइट हाउस में बैठकर उनकी मॉनिटरिंग खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे थे कि वो कैसे उड़ते हैं, कहां जाते हैं और कैसे बम गिराएंगे? नॉर्थ कोरिया की सीमा को टच करके वो बॉम्बर्स लौट गए. इस बीच उन्होंने दूरी का आकलन कर लिया. ये चीजें इस क्षेत्र के लोगों और खासकर नॉर्थ ईस्टर्न एशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स को खतरनाक लग रही हैं. वे अंदाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन के पूर्व जो मॉक ड्रिल हुआ था, उसकी निगरानी व्हाइट हाउस में बैठकर खुद तत्कालीन प्रेसिडेंट ओबामा कर रहे थे. जब वे खुद मुतमईन हो गए, तब जाकर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था. इसके बाद नेवी सील्स भेजे गए, जो पाकिस्तान में लादेन को मारकर डेड बॉडी के साथ वापस आ गए थे. ठीक वैसा ही काम अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं. वे व्हाइट हाउस में बैठकर बी1बी बॉम्बर्स के एक्सरसाइज को देख

(शेष पृष्ठ 2 पर)

तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो भारत भी सुरक्षित नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

रहे हैं. एक सेकेंड में ये बॉम्बर्स कितनी दूरी पर और कितना बम गिराते हैं, इसे कैलकुलेट कर रहे हैं. ये अभी तक बहुत खुला हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है.

भारत भी सुरक्षित नहीं

जनता तो अपने अंदाज में मस्त है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स और पीस लवर्स हैं, वे बहुत चिंतित हैं. उनका ये कहना है कि अगर लड़ाई हुई तो समुद्र के जीव-जन्तु खत्म हो जाएंगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, देश खत्म हो जाएंगे. इसका असर सिर्फ चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या जापान तक ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर चीन के पड़ोसी देशों बर्मा, भारत और पाकिस्तान पर भी पड़ेगा. अगर इनके ऊपर असर पड़ता है, तो हम हिन्दुस्तानियों के पास तो कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं है. हमारे लोगों को तो यह तक पता नहीं है कि प्रदूषित हवा को हम अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? यहां तो परमाणु अस्त्रों से निकले विषैले प्रभाव को रोकने की बात है. यह मानवता के ऊपर सबसे करारा हमला होगा, इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि खुद ट्रंप बिजनेस मैन हैं, इसलिए वे इतनी दूर तक नहीं जाएंगे. लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो निक्सन हो या ट्रम्प, सिर्फ अमेरिकी हितों को देखता है. जो ताकतवर होता है, जिम्मेदारी तो उसी की होती है. जो कमजोर है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है. कमजोर को तो लोग कहते हैं कि ये हमको उकसा रहा है, पर सचमुच वो कितना उकसा रहा है, कौन जानता है. चूंकि आरोप आपको लगाना है, तो आप किसी के ऊपर लगा दें. जैसे आपने सद्दाम के ऊपर आरोप लगा दिया था, लेकिन वहां तो कोई रासायनिक हथियार या मास डिस्ट्रक्शन वैपन्स नहीं मिले.

अब तो लोग कह रहे हैं कि साउथ कोरिया के हाथ से राजनीतिक हल निकालने का मसला दूर चला गया है. अब तो लोग ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के, जो सबसे अच्छे और समझदार महासचिव बान की मून थे, अगर उनके हाथ में भी यह मसला दे दिया जाता, तो वे कुछ नहीं कर सकते थे. अब सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प के हाथ में है. अगर ट्रम्प मानवता के बारे में कुछ सोचेंगे, तभी शायद स्थिति सामान्य हो सकती है, अन्यथा साउथ कोरिया और जापान के लोग काफी चिंतित हैं. साउथ कोरिया के लोग, जिनके रिश्तेदार नॉर्थ कोरिया में हैं, उनको तो दोनों तरफ से मरना है. इसीलिए प्रेसिडेंट मून जो-इन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साउथ कोरिया के सेना की कमान वे अमेरिका के हाथों से अपने हाथ में ले लें, देखें ये हो पाता है या नहीं.

उ. कोरिया के उकसावे का जवाब है युद्धाभ्यास

साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जो-इन वियतनाम और इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं. वे शायद नॉर्थ कोरिया के सवाल पर इन राष्ट्राध्यक्षों का अपने लिए समर्थन हासिल करने जा रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प जापान और साउथ कोरिया आ रहे हैं. वे साउथ कोरिया

इसलिए आ रहे हैं, ताकि फाइनल ट्यू ले सकें कि क्या करना है? लेकिन उनके आने से पहले बहुत कुछ शुरू हो गया है. न्यूक्लियर वैपन से लैस वारशिप यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ कोरिया की समुद्री सीमा में पहुंच गया है. यह पांच दिनों के लिए होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा. अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर पांच दिनों का युद्धाभ्यास ईस्ट और वैलो सी में कर रहे हैं. नॉर्थ कोरिया के उकसावे का जवाब देने के लिए यह एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन यह एक्सरसाइज नहीं है. यह दरअसल नॉर्थ कोरिया के खिलाफ समुद्री लड़ाई का प्रैक्टिकल या पूर्वाभ्यास है. नॉर्थ कोरिया को अगर दबाना हो या उस पर हमला करना हो, तो कैसे किया जाए, उसकी रणनीति इस अभ्यास में बनेगी.

यूएसएस रोनाल्ड रीगन साउथ कोरिया की समुद्री सीमा में पहुंच गया है. इस ड्रिल का नाम है मैरी टाइम काउंटर स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्स या एमसीएसओएफ. रोनाल्ड रीगन 1092 फीट लंबा है. इसकी वाटर लाइन बीम 134 फीट है और फ्लाई डेक 252 फीट चौड़ी है. यह 60 फाइटर्स हवाई जहाज को कैरी कर सकता है और इस यूएसएस रोनाल्ड रीगन पर पांच हजार क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं. यूएसएस मिशीगन एक पनडुब्बी है, जो ओहियो क्लास गाइडेड मिसाइल से लैस है. ये भी एमसीएसओएफ ड्रिल में हिस्सा लेने पहुंच चुकी है. ये भी 170.6 मीटर लंबी और 12.8 मीटर चौड़ी है. इसका मतलब 560 फीट लंबी और 42 फीट चौड़ी है. इसपर 150 टॉम हॉक क्रूज मिसाइल लदे हुए हैं, जो 1240 मील तक मार कर सकते हैं. दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने इस पनडुब्बी की सैर की और ये भी कहा कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंग योंग को ये उनका जवाब है. नॉर्थ कोरिया इस ड्रिल का विरोध कर रहा है. नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की कार्रवाई इसलिए हो रही है, ताकि वो उन तत्वों को बढ़ावा दे सकें, जो नॉर्थ कोरिया में सत्ता पलटना चाहते हैं. किम जोंग उन को डर है कि इस एक्सरसाइज से उन लोगों को बल मिलेगा, जो उनके खिलाफ हैं. ये उसे अपनी सत्ता से हटाने का अभियान मानते हैं. ये भी पता चला है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सभी मालवाहक जहाजों को मिसाइल लॉन्चर में तब्दील कर दिया है.

ट्रम्प की धमकी

शायद नॉर्थ कोरिया फिर मिसाइल टेस्ट करे. वो इसलिए कि चीन की पीपुल्स पार्टी की 10वीं पार्टी कांग्रेस में प्रेसिडेंट जिन पिंग को अगले पांच साल के लिए फिर प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा. इसलिए अंदाज है कि शायद उसी दिन नॉर्थ कोरिया फिर से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करेगा. इस टेस्ट को अमेरिका उकसावे की कार्रवाई मानेगा और इसके बाद शायद नॉर्थ कोरिया के ऊपर वो और कार्रवाई करे. ट्रम्प ने एक बात कही कि जब हम किसी से समझौते की बात करते हैं, तो उसका कोई न कोई नतीजा जरूर निकलता है और अगर वो नतीजा न निकले तो हम फिर वो करते हैं, जो कभी हुआ ही नहीं है. ये ट्रम्प के शब्द याद रखिए. इसका मतलब आप निकाल सकते हैं. पहले अंदाज था कि 10 अक्टूबर को ये टेस्ट होगा, क्योंकि उस दिन प्योंग योंग में वर्कर्स पार्टी का 72 वीं स्थापना दिन मनाया गया था. रूल करने वाली वर्कर्स पार्टी किम जोंग उन की फादर की पार्टी है. 10 अक्टूबर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद थी कि चीन की दसवीं कांग्रेस की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग या उसका परीक्षण करेगा. अब वे पांच या दस दिन में टारगेट अटैक रडार सिस्टम पर होगा. नॉर्थ कोरिया के रडार सिस्टम को टारगेट करके ये अभ्यास शुरू होगा. यूएस आर्मी और एअर फोर्स का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है. नॉर्थ कोरिया के टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेशली रडार को कैसे जाम करना है, कैसे ध्वस्त करना है. अब वहां पर क्या-क्या पहुंच गया है, वो भी आपको बता दें. एफ 202 रॉप्लेट, ए 10 थंडर वोल्ट टू, सी 17 ग्लोब मास्टर थर्ड, सी130 जे हरकलिस, बी1बी लेंसर, केसी 135 स्टैटो टैंकर, इ 3 सेंट्री, यू 2 ड्रैगन लेडी, आरक्यू 4 ग्रोवल हॉक, इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे. किसको, कौन, कहां से, कैसे हमले करेगा और नॉर्थ कोरिया को कैसे जाम करना है, कैसे घुसना है, उसकी रणनीति बनेगी. एयरफोर्स का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एफ 35ए लाइट टू भी इसमें शामिल है, जो न्यूक्लियर वैपन ले जाने वाले मिसाइल से लैस है.

अमेरिका देगा न्यूक्लियर अम्ब्रेला का प्रोटेक्शन

दरअसल प्रेसिडेंट ट्रम्प जापान और साउथ कोरिया को ये आश्वासन देने आ रहे हैं कि लड़ाई की स्थिति में वे दोनों देशों को न्यूक्लियर अम्ब्रेला का प्रोटेक्शन देंगे. जापान बहुत डरा हुआ है. जापान के पास अपनी सेना नहीं है, जो लड़ाई कर सके. साउथ कोरिया के पास भी नॉर्थ कोरिया का सख्ती से मुकाबला करने के लिए सेना नहीं है. नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली है. जैसा मैंने बताया था कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जो-इन नहीं चाहते कि लड़ाई हो. इसलिए वो अपनी सेना का कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं. उनके रक्षामंत्री इस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं. वे युनाइटेड स्टेट आर्मी के साथ और खासकर उनकी जो मिसाइलों से लैस नई पनडुब्बी आई है, जो 1240 मील तक की मार कर सकती है, को देखकर आए हैं. अब ये सारी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है. ये स्थिति लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत है क्योंकि लोगों की इच्छा एक तरफ होती है और सत्ता की मर्जी बिल्कुल दूसरी होती है.

नॉर्थ कोरिया से बौखलाया अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं या उनके एलाइज, सभी सारी दुनिया में अपनी धमक दिखाना चाहते हैं. एक छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया उनके सामने तनकर खड़ा है. हो सकता है नॉर्थ कोरिया की सारी गलती हो, उसने इतनी चिकोटी काटी हो कि अमेरिका को लग रहा होगा कि इसे अभी दबाना आवश्यक है, लेकिन ये मनोविज्ञान ठीक वैसा ही है कि गांव या शहर के किसी ताकतवर नेता को किसी साधारण वर्कर की सभा में अच्छा भाषण देना भी पसंद नहीं आता है. ये सामान्य मनोविज्ञान है. अगर किसी पार्टी के अध्यक्ष को ये लगे कि उनकी

साउथ चाइना सी में चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय

पार्टी में ये नेता धीरे-धीरे उभर रहा है, तो वो सबसे पहले उसकी राजनीतिक हत्या करता है. इसी तरह अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन है. वो देश जो सारी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है और ट्रम्प इस मौके को अपने ताकतवर होने का एहसास सारी दुनिया को दिलाना चाहते हैं कि वो ताकतवर भी हैं और जल्द फैसले भी ले सकते हैं. अब भी बहुतों को विश्वास है कि चूंकि ट्रम्प बिजनेसमैन हैं, इसलिए ऐसा कोई फैसला शायद न लें. लेकिन जो ट्रम्प का मनोविज्ञान जानते हैं, जो उनके बयानों को देखते हैं, जिस तरह से ट्रम्प लोगों की इज्जत या बेइज्जती करते हैं, वो सारी चीजें बताती थीं कि ट्रम्प ये सब कर सकते हैं. ट्रम्प ओबामा या अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति से बेहतर हैं या नहीं, ये तो इतिहास बताएगा. लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प अपने को इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे समझदार और सबसे होशियार राष्ट्रपति साबित करने पर तुले हैं.

नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच का तनाव टॉप पर है और शायद कुछ भी हो सकता है. नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि न्यूक्लियर वार में ब्रेक आउट एट ऐनी मूवमेंट हो सकता है और ये दुनिया में इस समय चिंता का विषय बना हुआ है. पर मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ कोरिया जल्द नई बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सप्लोजन कर सकता है या टेस्ट कर सकता है. इसी समय यूएसएस रोनॉल्ड रीगन भी समुद्र में है, पर इससे पहले अभी की बातचीत सुन लीजिए. अमेरिका के सिक्युरिटी एडवाइजर जनरल एचआर मैकमास्टर ने कहा है कि हम वार के आप्शन पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ कोरिया की धमकी

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रैक्स टिलरसन ने कहा है कि पहला बम गिरने तक हम बातचीत करते रहेंगे और पॉलिटिकल सॉल्यूशन तलाशते रहेंगे. पर पूरे सेंटेन्स का कंस्ट्रक्शन देखिए. पहला बम गिरने तक ये खतरनाक सोच अमेरिका की है. ऑस्ट्रेलिया ने ट्रम्प का साथ देने का फैसला किया है. इसे लेकर नॉर्थ कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत धमकाया है कि आप अगर ये करते हैं तो आप भी हमारे दुश्मन माने जाएंगे. एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि ट्रम्प हैनरी किसिंजर से मिले और लंबी बातचीत की. साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जो-इन भी हैनरी किसिंजर से मिलना चाहते हैं. इस बीच नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने साउथ कोरिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज कंपनी वितुंब के 30 हजार यूजर्स रिकॉर्ड हैक कर लिए हैं. साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जो-इन ने 1994 में सिएटल में साउथ-नॉर्थ कोरिया विवाद के अमेरिकी चीफ निगोशिएटर गैल्युसी जे चीफ से भी मुलाकात की है. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस शुरू हुई, उसी समय साउथ कोरिया और यूएसके मैरी टाइम ड्रिल भी शुरू हुई. यूएसएस रोनॉल्ड रीगन और यूएसएस के बहुत सारे खतरनाक जहाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो उनके रडार सिस्टम को डैमेज करना चाहते हैं. एफ 202, ए10 थंडर वोल्ट 2, ये सब हवाई जहाज के नाम हैं. सी 17 ग्रुप मास्टर्स थर्ड, सी 130 जे हरकुलिस, बी1बी लैंसर, केसी 135 स्टैटो टैंकर, ई थ्री सैंट्री, यू 2 ड्रैगन लेडी, आर क्यू फोर ग्लोबल हॉक, इसमें हिस्सा ले रहे हैं. सबसे बड़ी चीज कि जो सबमैरीन है, जिसके ऊपर लगभग यूएसएस मिशीगन पनडुब्बी है, जो ओहयो क्लास गाइडेड मिसाइल लिए हुए है, ये भी इस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं. यह 170.6 मीटर लंबी और 12.8 मीटर चौड़ी है. इसमें लगभग 150 टॉक हॉक क्रूज मिसाइल हैं और 60 हवाई जहाज हैं, जो 1240 मील तक मार कर सकते हैं. इस बीच सियोल में दुनिया भर के 39 शहरों के मेयरों की क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत हुई.

अपने देश पर क़ब्ज़ा करने की साज़िश मान रहा नॉर्थ कोरिया

हमें पहले लग रहा था कि अमेरिका युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अंदर ही अंदर पूरी तैयारी कर रखी है. उसने अपनी सारी विध्वंसक शक्ति वैलो सी में इकट्ठी कर ली है. नॉर्थ कोरिया के हर स्ट्रैटजिक प्वाइंट इस समय उनकी जद में हैं. दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम इसे अपने देश पर कब्जा करने की साजिश मानेंगे और इसका जवाब देंगे. अमेरिका एक और नया काम कर रहा है. अमेरिका ईरान के साथ भी टेंशन ले रहा है. इस समय चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक नया ध्रुव बनता जा रहा है और शायद रूस भी इनके साथ शामिल हो जाए. क्योंकि अभी तक रूस का ऑफिशियल स्टैंड, न्यूट्रियल स्टैंड तो है लेकिन बहुत न्यूट्रियल नहीं है. ये दुनिया के लिए एक ऐसी तनाव भरी स्थिति होगी जिसमें चीन के साथ-साथ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसकी जद में आ जाएंगे. अगर ईरान के साथ अमेरिका ने ज्यादा टेंशन लिया, तो ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है. ऐसा लगता है कि सचमुच तीसरे विश्व युद्ध का समय आ रहा है. हम यही प्रार्थना करेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध न हो. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 35
30 अक्टूबर- 05 नवंबर 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नीतीश के 'सुशासन' में सम्पत्तियों से बेदख़ल किए जा रहे ईसाई समुदाय के लोग

ईसाई वोट बैंक थोड़े ही हैं!

राजेन्द्र कमल

राजनेता-प्रशासन-भूमाफिया (बिल्डर) और मिशन-माफिया के गठजोड़ से बिहार में ईसाई अल्पसंख्यकों की परिसम्पतियां धड़ल्ले से लूटी जा रही हैं, उन्हें बेघर-बेदखल किया जा रहा है, लेकिन 'न्याय के साथ विकास' और 'सबका साथ - सबका विकास' की जुमलेबाजी कर सरकारें अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आ रही हैं. उच्च न्यायालयों के न्यायादेश रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और नेता-प्रशासन के संरक्षण में बिल्डर अपने गुंडों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध मिनी कंधमाल कांड को बखूबी अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचक रहे. गत 19 दिसम्बर 2015 को राजधानी पटना के बाकरगंज स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी परिसर में जो घटना घटी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावे पर कलंक साबित हुआ है. करीब डेढ़ दर्जन ईसाई परिवार बेघर कर दिए गए और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. राज्य के गृह (विशेष) विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया. अल्पसंख्यक हित का दावा करने वाली नीतीश सरकार तथ्यों के आलोक में खुद कटघरे में खड़ी हो गई है.

घटना 2015 की है, लेकिन इसके तार काफी पहले से और अभी तक कड़ीबद्ध हैं. दरअसल, व्यवहार में दलों और सरकारों के लिए अल्पसंख्यक का मतलब केवल एक समुदाय ही रहता आया है जो बड़ा वोट बैंक है. ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक तो हाशिए पर हैं. न तो इनकी कोई राजनीतिक हस्ती है और न ये आर्थिक रूप से मजबूत हैं. यह दीगर बात है कि विभिन्न ईसाई मिशनों के पास देशभर में सरकारों से भी अधिक परिसम्पतियां हैं जिनपर नेताओं और भू-माफिया की गिद्ध नजर रहती है. इन परिसम्पतियों की रक्षा के लिए सरकारों ने न तो वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास जैसी संस्थाएं बनाने की जहमत उठाई और न जमीन के धंधे की परत खुलने पर भी कोई कारगर कार्रवाई ही की जाती है. नतीजतन अदालती स्थगन आदेशों के बावजूद मिशन-भूमि का धंधा खुलेआम चल रहा है और ईसाई समुदाय परिसम्पतियों से वंचित होता जा रहा है. कितने स्कूल, छात्रावास, चर्च आदि पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया. पूरे देश में अब तक अरबों रुपए का यह धंधा हो चुका है. बिहार तो एक छोटा-सा नमूना है. पलवल, दिल्ली, आगरा, कोलकाता आदि स्थानों में खूब धंधा हुआ है.

यह गोरखधंधा समझने के लिए कालचक्र को थोड़ा उल्टा घुमाना जरूरी है. मुगलों के शासनकाल में विदेशी मिशनरी भारत आने लगे थे. ब्रिटेन में 1792 में निबंधित बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी (बीएमएस) के मिशनरी इसमें प्रमुख है. 1793 में प्रथम बीएमएस मिशनरी विलियम कैरी ने तत्कालीन कलकता से अपना कार्य आरंभ किया. ईस्ट इंडिया कम्पनी भी तब अपने पांव भारत में जमा रही थी. कालांतर में 1857 में कम्पनी स्वतंत्रता संग्राम को विफल कर भारत का कर्णधार बन गई. तब कम्पनी सरकार होती थी बाद में ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत आ गया. इसके बाद तो बीएमएस मिशनरियों की बन आई. भारतीय राजा-महाराजों, नवाबों, जमींदारों आदि ने खुशामद में बीएमएस मिशनरियों को चर्च छात्रावास, अस्पताल, वृद्धाश्रम आदि के लिए काफी भूमि दान में दी. ब्रिटिश सरकार ने भी कोताही नहीं बरती, बीएमएस को सरकारी जमीनें भी मिलीं- बहुत सी जमीन धर्मांतरित भारतीय ईसाईयों के दान से खरीदी गईं. जर्मनी, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि की मिशन संस्थाओं ने भी यहां पांव पसारने की कोशिश की लेकिन बीएमएस पर ब्रिटिश सरकार की कृपा बनी रही. इसके बाद मेथोडिस्ट और एजी मिशन ने भी अपनी पहचान बनाई. लेकिन बीएमएस मिशन की सीधी पहुंच राजसत्ता तक थी. फलतः अविभाजित भारत में इसकी तूती बोलती थी. लिहाजा उत्तर पूर्व के नगालैंड, असम, बंगाल, ओड़ीशा, बिहार वर्तमान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब आदि में बीएमएस के पास अकूत परिसम्पत्ति हो गई. तब इसके प्रबंधन के लिए बीएमएस ने 1888 में बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी कारपोरेशन (बीएमएससी) नाम से एक ट्रस्ट ब्रिटेन में निबंधित करा लिया. यह कहने को अलग संस्था थी लेकिन वास्तव में यह बीएमएस की छाया संस्था के रूप में काम रही थी और कर रही है.

इधर देश में स्वतंत्रता आन्दोलन तेज होने लगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन नये आयाम पर पहुंचा. अन्तरराष्ट्रीय स्थितियां भी बदलीं, दूसरे विश्वयुद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी. भारत पर ज्यादा समय तक काबिज नहीं रहा जा सकता इसका एहसास अंग्रेजों को होने लगा था. बीएमएस के मिशनरियों को भी भारत में अपने नाम अकूत परिसम्पतियों की चिंता होने लगी. अचल परिसम्पति वे ब्रिटेन नहीं ले जा सकते थे इसलिए परोक्ष रूप से काबिज रहने के लिए कुछ भारतीयों को साथ लेकर 1932 में बैपटिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन (बीसीटीए) का गठन कर इंडियन कम्पनीज ऐक्ट 1913 के तहत निबंधित कराया लेकिन इसके निबंधित आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में बीएमएस के सात सदस्यीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखकर लगाम अपने हाथ में रख ली. बीसीटीए तो बन गया लेकिन 1955 तक यह कागजी ही रहा, बिना किसी परिसम्पत्ति के बीएमएस और बीएमएससी ने 1956 से 1958 के बीच अपने नाम की अधिकतर परिसम्पतियां बीसीटीए के नाम ट्रांसफर कीं, लेकिन इनमें से अधिकांश का दाखिल खारिज भी बीसीटीए के नाम नहीं हुआ है. गिनती की कुछ सम्पत्तियों का हुआ भी तो बिल्डरों के हाथों. शेष अभी भी इन्हीं दोनों विदेशी संस्थाओं के नाम पर हैं.

गौरतलब यह है कि बीसीटीए वस्तुतः 1959 से ही अवैध और अनियमित संस्था है क्योंकि बीएमएस-बीएमएससी के निदेश पर इसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पूरा सेट ही दिनांक 10.11.1959 को बदल दिया जबकि कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी. कम्पनी रजिस्ट्रार, कोलकाता ने 1959 के इस संशोधन को अनुमोदित नहीं किया. इसके बाद 12.06.1984, 23.03.1991, 31.10.1998 तथा 28.09.2002 को भी संशोधन पारित किया जिनमें से कोई भी संशोधन अनुमोदित नहीं है, बल्कि रद्द घोषित किए जा चुके हैं. लेकिन बीसीटीए उक्त रद्द संशोधनों पर ही गठित होता है, निर्णय लिए जाते हैं और जमीन के धंधे का प्रस्ताव पारित कर भू-माफिया से एग्रीमेंट किए जाते हैं. भू-माफिया नेता और प्रशासन को पटा कर भूमि पर कब्जा जमाते हैं. बाकरगंज में यही खेल खेला गया. रिट संख्या 3048/06 में दिनांक 22.02.11 को पारित आदेश के आलोक में कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार ने बीसीटीए के क्रियाकलापों की जांच कराई. जांच रिपोर्ट में सारी अनियमितताएं स्पष्ट हैं. कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली ने जांच रिपोर्ट (ठजउ/24261 दिनांक 15.01.2013) द्वारा मुख्य सचिव बिहार, पटना को कारवाई के लिए भेजा. जांच रिपोर्ट फाइलों में पड़ी रही, कारवाई नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध गैर-बैपटिस्ट बीसीटीए प्रबंधन पर काबिज रहते आए और विदेशी बीएमएस के निदेश पर जमीन का धंधा होता आ रहा है. कम्पनी अधिनियम के विरुद्ध हुए संशोधनों पर कम्पनी कार्य विभाग लाइसेंस रद्द करने का कागजी तीर छोड़ता रहा लेकिन इस अवैध संस्था (कम्पनी) का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया. पटना हाईकोर्ट ने रिट याचिका (3048/06) में दिए आदेश में बीसीटीए में हुए संशोधनों और गैर-बैपटिस्टों द्वारा भूमि का धंधा करने की जांच करने का आदेश प्रादेशिक कम्पनी निदेशक उ.क्षे. भारत सरकार नोएडा को देते हुए आरोप सही पाए जाने पर तीन माह में परिसम्पतियों की वापसी और कम्पनी के विरुद्ध कारवाई का आदेश दे रखा है. इसी आलोक में कम्पनी रजिस्ट्रार उ.क्षे. दिल्ली ने जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए कारवाई के लिए मुख्य सचिव, बिहार को पत्र लिखा जिस पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई, उल्टे क्रिश्चियन कॉलोनी से ईसाई परिवार बेघर-बेदखल करा दिए गए. पूरा प्रशासन भू-माफिया के तलवे चाटने में लगा रहा. बिल्डर ने भी तथ्य छिपाकर निचली अदालत से दखलदहानी का आदेश प्राप्त कर लिया. रजिस्ट्रार कम्पनी की जांच रिपोर्ट पर अमल करने के बदले प्रशासन ने बिल्डर को भारी पुलिसबल भी मुहैया कर दिया. पटना हाईकोर्ट के उक्त आदेश और सूट नं. 416/96 में दिल्ली हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को तरजीह नहीं देकर सिविल कोर्ट पटना के दखलदहानी आदेश के सामने प्रशासन नतमस्तक रहा. सिविल कोर्ट के स्टेटस को आदेश को भी नहीं माना गया. दखलदहानी कराने आए डीएसपी कैलाश प्रसाद तो दूसरे पक्ष से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सपाट उत्तर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बिहार में मान्य नहीं है. ऐसा लिखित मांगने पर विदक कर वे ईसाईयों को धमकाने लगे.

गंभीर बात यह है कि पटना के लोदीपुर स्थित सौ वर्ष पुराने एंगस शिक्षण संस्थान को भी मिशन माफिया ने फेरा-फेमा अधिनियम का उल्लंघन कर 2008 में उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड (जयपुर में निबंधित) को महज पांच करोड़ में बेच डाला. बिकी हुई करीब साढ़े सात एकड़ जमीन की कीमत अभी के बाजार भाव से करीब तीन सौ करोड़ है. इस डीलिंग में परदे के पीछे तत्कालीन नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी की भूमिका और जदयू के उस समय प्रदेश के सर्वोच्च पदाधिकारी की संलग्नता काफी चर्चा में रही. इनकी भूमिका को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि ईसाईयों की गुहार प्रशासन के किसी स्तर पर नहीं सुनी गई. इस कुकृत्य का विरोध करने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर दिनदहाड़े गोलियां चलवाई गईं. वे बुरी तरह जख्मी हुए और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची. राजनेताओं के दबाव पर इस गोलीकांड की भी पुलिस ने लीपापोती कर दी. विधान परिषद में मामला उठने पर सरकार ने गलती स्वीकारी, कारवाई का आश्वासन दिया जो आज तक अमलीजामा नहीं पहन सका. दोनों नेता नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर आसीन हैं, अब तो न्याय की और कोई उम्मीद नहीं है. जो नेता एक परिवार विशेष की सम्पतियों को लेकर रोज शिगूफा छोड़ता हो, जांच होने पर उसके खुद की संलिप्तता आधिकारिक तौर पर उजागर होने की पूरी संभावना है. सता का प्रभाव इतना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के सूट नं. 416/96 में स्थगन आदेश के बावजूद एंगस परिसर की जमीन उत्कर्ष स्फटिक के नाम बिकी, सत्रह मंजिला भवन निर्माण का नक्शा पारित हुआ, पटना हाईकोर्ट के आदेश से नक्शा रद्द भी हुआ. फिर आरएफए नं-132/15 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी रखने आदेश दिया लेकिन इसे ताक पर रख कर निर्माण कार्य जारी रखा गया.

बिहार में ईसाईयों के साथ हो रहे अन्याय की सुनवाई होती नहीं दिखती. भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस का दावा ईसाईयों के मामले में जीरो ही साबित हो रहा है. आरा में सरकार प्रदत्त मेथोडिस्ट मिशन की जमीन (कभी प्रसिद्ध सावटेल मेमोरियल गर्ल्स स्कूल) की बंदरबांट का बड़ा खुलासा हुआ है. बक्सर में भी मेथोडिस्ट मिशन की जमीन का धंधा हुआ. जो स्थिति है उसमें तो यही लगता है कि सुशासन के दावों को प्रशासन ही ठेंगा दिखा रहा है. तभी अदालती आदेश गृह विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया और ईसाई परिवार बेदखल हो गए. नेताओं का संरक्षण और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार रास्ते की रुकावट है. केंद्र सरकार भी कान में तेल डाले पड़ी है जबकि उसे बीसीटीए का लाइसेंस रद्द घोषित करते हुए परिसम्पति वापसी की कारवाई करनी चाहिए. लेकिन ईसाईयों की सुनता ही कौन है, वह वोट बैंक थोड़े ही है! ■

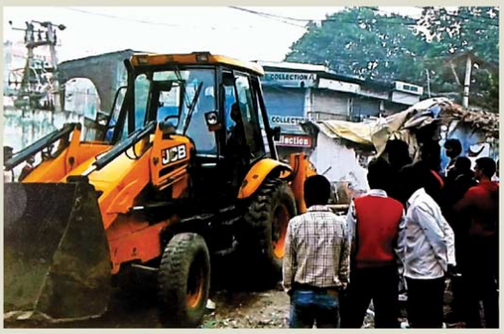

बिहार में ईसाईयों के साथ हो रहे अन्याय की सुनवाई होती नहीं दिखती. भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीरो टॉलरेंस का दावा ईसाईयों के मामले में जीरो ही साबित हो रहा है. आरा में सरकार प्रदत्त मेथोडिस्ट मिशन की जमीन (कभी प्रसिद्ध सावटेल मेमोरियल गर्ल्स स्कूल) की बंदरबांट का बड़ा खुलासा हुआ है. बक्सर में भी मेथोडिस्ट मिशन की जमीन का धंधा हुआ. जो स्थिति है उसमें तो यही लगता है कि सुशासन के दावों को प्रशासन ही ठेंगा दिखा रहा है. तभी अदालती आदेश गृह विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया और ईसाई परिवार बेदखल हो गए.

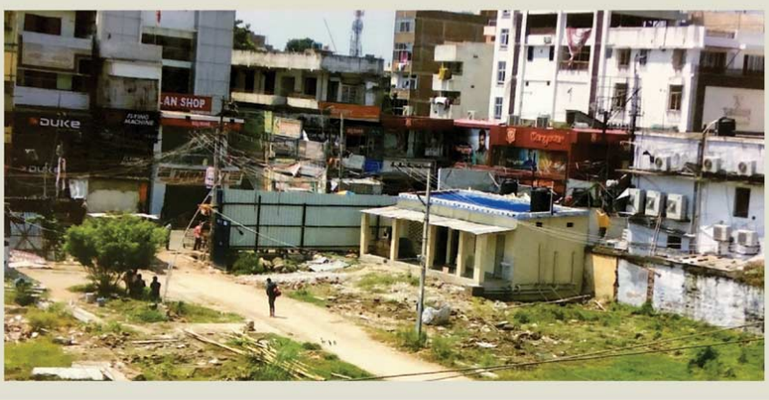

feedback@chauthiduniya.com

हंगर इंडेक्स

भूखे और कुपोषित लोगों से कैसे बनेगा न्यू इंडिया

शशि शेखर

हंगर इंडेक्स क्या है? इसका आसान अर्थ ये है कि अगर किसी देश का हंगर इंडेक्स अधिक है, तो इसका मतलब है कि उस देश में भूख की समस्या भी अधिक है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स को चार पैमाने पर नापा जाता है. ये पैमाने हैं, कुपोषण, बच्चों में कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर. साल 2017 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है. 119 देशों की सूची में भारत 100वें नंबर पर है (नेपाल, बर्मा से भी नीचे). 2014 में भारत का स्थान 55वें नंबर पर था. पिछले तीन सालों में भारत 45 सीढ़ी लुढ़कते हुए 100 पर आ गया है. ये रिपोर्ट ये नहीं बताती है कि किसी आदमी को खाना मिलता है या नहीं. ये रिपोर्ट ये बताती है कि पोषक खाना मिलता है या नहीं. बच्चों को खाने में पोषकता मिलती है या नहीं. इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के बच्चों को पोषक खाना नहीं मिलता. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक, भारत में 5 साल से कम उम्र का तीन में से एक बच्चा अंडरवेट है. तीन में से एक बच्चा नाटा है, 5 में से एक बच्चा काफी कमजोर है. आंकड़ों की बाजीगरी को यहीं तक रहने दीजिए और ये देखिए कि कैसे मिड डे मिल, मनरेगा जैसे कार्यक्रम की वजह से किसी तरह भारत का ग्रामीण हिस्सा अपना भूख शांत करता है. अन्त्योदय का चावल, मनरेगा से मिले कुछ रुपए करोड़ों घरों में चूल्हा जला देते हैं. लोग कुछ भी खा कर पेट भर लेते हैं, बिना ये चिंता किए कि उनके बच्चे के बोन डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम और विटामिन डी मिल रहा है या नहीं.

2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में भारत 100वें पायदान पर है. एशिया में भारत सिर्फ अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से आगे है. नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल कुपोषण ने इस बुरी स्थिति को और बदतर बना दिया है. दुख की बात ये है कि एक तरफ देश में सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे तेज ट्रेन यानि बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी की जा रही है, वहीं भारत की एक बड़ी जनसंख्या को ठीक से दो जून का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है. सवाल यह है कि क्या ऐसे ही भूखे और कुपोषित लोगों की फौज से न्यू इंडिया बनेगा? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पांच साल तक की उम्र के बच्चों की कुल आबादी का 20 फीसदी अपने कद के मुकाबले बहुत कमजोर है. तीन में से एक बच्चा अंडरवाइट यानि उसका विकास ठीक से नहीं हुआ है. देश के भीतर के सरकारी आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं. 2017 के अप्रैल में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने संसद में बताया था कि देश में 93 लाख से ज़्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं. उन्होंने बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, देश में कुल 93.4 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं. इसमें से 10 प्रतिशत को चिकित्सा संबंधी जटिलताओं की वजह से एनआरसी में भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है. एक आंकड़े के मुताबिक आज भारत में 21 फीसदी से अधिक बच्चे कुपोषित हैं. दुनिया भर में सिर्फ तीन ही देश, जिबूती, श्रीलंका और दक्षिण सूडान, ऐसे हैं, जहां 20 फीसदी से अधिक बच्चे कुपोषित हैं. जाहिर है, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर सरकार की सारी योजनाएं इस मामले में असफल साबित हो रही हैं.

सरकार ने बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में कुपोषण के मसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं बनाईं. आईसीडीएस परियोजनाओं के अलावा, किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी कार्यक्रम (एनपीएजी), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम), पेयजल एवं

2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में भारत 100वें पायदान पर है. एशिया में भारत सिर्फ अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान से आगे है. नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल कुपोषण ने इस बुरी स्थिति को और बदतर बना दिया है. दुख की बात ये है कि एक तरफ देश में सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे तेज ट्रेन यानि बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी की जा रही है, वहीं भारत की एक बड़ी जनसंख्या को ठीक से दो जून का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है.

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमएनआरईजीएस) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी योजनाएं भी हैं. आईसीडीएस योजना में छह सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है- पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं. इनमें से तीन सेवाएं (टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं. केंद्र सरकार ने बच्चों में कुपोषण की पहचान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रस्तावित मानकों को 15 अगस्त 2008 को स्वीकार किया था. 1993 की राष्ट्रीय पोषण नीति और 1995 की राष्ट्रीय पोषण कार्ययोजना में राज्यों में राज्य पोषण परिषदों की स्थापना की परिकल्पना की गई. ऐसे कितने परिषद स्थापित किए गए हैं, इसकी जानकारी न मीडिया को है, न आम आदमी को. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट है. सरकार की ओर से कुपोषण का मुकाबला करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर योजनाएं चलाई जाती हैं. लेकिन, अगर हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में हम साल दर साल नीचे गिरते जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये योजनाएं अपने मकसद में असफल साबित हो रही हैं.

इन तमाम योजनाओं के बाद भी ग्रामीण भारत को आवश्यक पोषण नहीं मिलता. 1975-79 की तुलना में आज औसतन ग्रामीण भारतीय को 500 कैलोरी, 13 ग्राम प्रोटीन, पांच मिलीग्राम आयरन, 250 मिलीग्राम कैल्शियम व करीब 500 मिलीग्राम विटामिन-ए कम मिल रहा है. तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चे, प्रतिदिन 300 मिलीलीटर दूध की बजाय 80 मिलीलीटर दूध ही ले पाते हैं. यही वजह है कि 35 फीसदी ग्रामीण पुरुष और महिलाएं कुपोषित और 42 फीसदी बच्चे कम वजन के हैं. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है और जैसे हालात हैं, उससे 2030 तक भुखमरी मिटाने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य शायद ही पूरा हो पाए. भारत के सन्दर्भ में बात करें तो एक दिलचस्प आंकड़ा और भी है. जहां भारत के लोग भूख से पीड़ित हैं, वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 40 फ़ीसदी खाना बर्बाद हो जाता है. अगर, इस आंकड़े पर विश्वास न हो तो एक बार किसी शादी, होटल, किसी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रमों में जा कर देखें कि हम जितना खाना कूड़े में फेंकते हैं, उतना भी करोड़ों लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजा ड्राफ्ट, दो माह में मांगा जवाब

अब ट्यूबवेल लगाने पर भरिए फीस

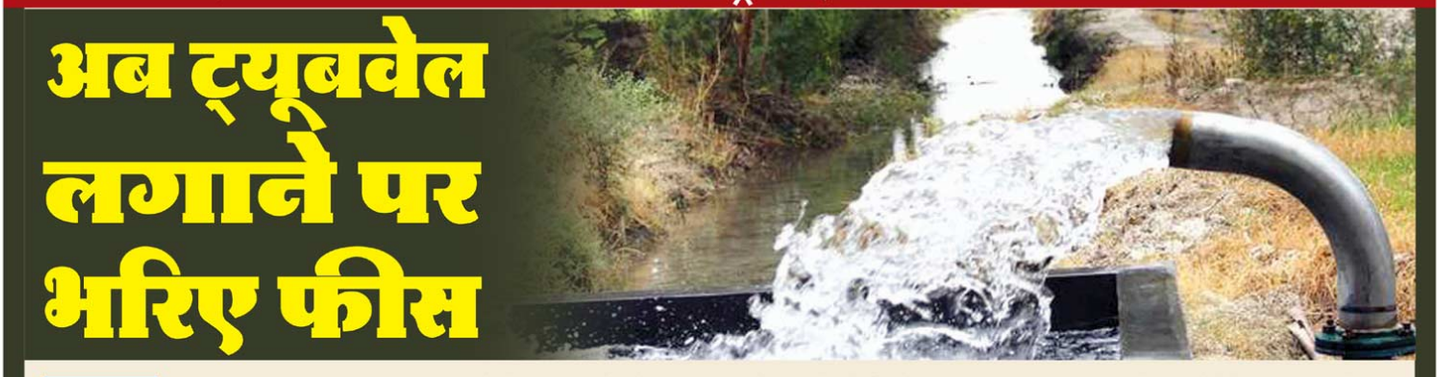

चौथी दुनिया ब्यूरो

भूजल पर अब आम लोगों का अधिकार नहीं होगा. सरकार अब भूजल के दोहन पर टैक्स लगाने की तैयारी में है. भूजल दोहन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार जल संरक्षण फीस वसूलने जा रही है. इस संबंध में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं. जलसंरक्षण मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट सभी राज्य सरकारों को भेजकर दो महीने में फीडबैक मांगा है. केंद्र इस मामले में गंभीर है और राज्य सरकारों से जवाब मिलने के बाद इस गाइडलाइंस को तुरंत लागू किया जा सकता है. इसके तहत व्यक्ति, आवासीय कॉलोनियों, टाउनशिप, अपार्टमेंट्स, औद्योगिक इकाइयों और क्लबों से यह फीस पानी के बिल के साथ ही वसूली जाएगी. अनुमान है कि भूजल के प्रयोग व ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसार यह फीस 1 रुपए से लेकर 6 रुपए प्रति हजार लीटर तक हो सकती है. कह सकते हैं कि जमीन के नीचे के पानी का जो इकाई जितना अधिक इस्तेमाल करेगी, उसी के हिसाब से जल संरक्षण फीस भी वसूली जाएगी, यानी आप फीस भरिए और भूजल का अंधाधुंध दोहन कीजिए.

पर्यावरणविदों को आशंका है कि सरकार के इस फैसले से बड़ी औद्योगिक इकाइयों, शीतलपेय और खनन कंपनियों को अंधाधुंध भूजल दोहन की छूट मिल जाएगी. जल संरक्षण से जुड़े संगठनों का मानना है कि सरकार जल संरक्षण फीस वसूल कर कुछ हद तक ही भूजल के इस्तेमाल को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जल संरक्षण के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिचार्ज की सुविधा पर जोर देना चाहिए था. इस दिशानिर्देश में औद्योगिक इकाइयों को बोरवेल की खुदाई से पहले सक्षम अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है. सिर्फ किसानों को एनओसी नहीं लेने की छूट मिलेगी.

पानी के बाजारीकरण का खेल 1990 के दौर से ही शुरू हो गया था. नवउदारीकरण के दौर में केंद्र और राज्य की सरकारें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एजेंट की तरह काम करने लगीं. आंध्रप्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने अपने यहां भूजल पर टैक्स लगाने की शुरुआत की. इसके बाद नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में भूजल के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने से संबंधित विधेयक पास करा लिया था. यह भी सच है कि जमीन के नीचे बह रहे पानी पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है. यह पानी जमीन के नीचे सैकड़ों किलोमीटर दूर से बहकर आता है. अब अगर कोई औद्योगिक इकाई इस पानी का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करे, तो उसे इसका भुगतान जरूर करना चाहिए. अभी तक हो यह रहा है कि एक ट्यूबवेल लगाने पर आ रहे खर्चे के बाद औद्योगिक इकाइयों को भूजल मुफ्त में मिलने लगता है. अगर भूजल पर टैक्स लगाया जाए, तो स्वाभाविक है कि औद्योगिक इकाइयां पानी का कम दोहन करेंगी. वे इस्तेमाल भर का पानी ही जमीन से निकालेंगी और बाकी छोड़ देंगी और भूजल संरक्षण के उपायों पर भी जोर देंगी. लेकिन अभी तक होता यह है कि अगर तीन सौ मीटर पर पानी नहीं निकल रहा, तो अन्य औद्योगिक इकाइयां चार सौ मीटर जमीन की खुदाई कर

पानी के बाजारीकरण का खेल 1990 के दौर से ही शुरू हो गया था. नवउदारीकरण के दौर में केंद्र और राज्य की सरकारें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एजेंट की तरह काम करने लगीं. आंध्रप्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने अपने यहां भूजल पर टैक्स लगाने की शुरुआत की. इसके बाद नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में भूजल के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने से संबंधित विधेयक पास करा लिया था.

ट्यूबवेल लगा लेती हैं, जिससे कम गहराई वाले सभी ट्यूबवेल बेकार हो जाते हैं. फिर अगर कोई पांच सौ मीटर गहराई वाला ट्यूबवेल लगा लेता है, तो इलाके के अन्य सभी ट्यूबवेल सूख जाते हैं. औद्योगिक इकाइयों की इस प्रतियोगिता में नुकसान भूजल का होता है, जिसपर सभी लोगों का हक है.

आंकड़ों के अनुसार देश भर में 6,607 विकासखंड, मंडल, तालुका और जिलों में से 1,071 में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है. इनमें से 900 इलाके डेंजर जोन में पहुंच गए हैं. इस पर रोक लगाने के लिए देशभर में भूजल दोहन को लेकर एकसमान नीतियां बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी. इसे ध्यान में रखकर उद्योगों द्वारा पानी की बर्बादी को लेकर जल संसाधन मंत्रालय एवं नीति आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इसके अलावा उद्योगों द्वारा पानी के कम इस्तेमाल पर टैक्स में छूट देने की योजना पर भी विचार हो रहा है. पानी के अंधाधुंध प्रयोग पर रोक लगाने का एक उपाय यह भी है कि नए ट्यूबवेल लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जाए. पर्यावरणविदों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, वहां ट्यूबवेल पर रोक लगा दी जानी चाहिए.

गुजरात में भूमिगत पानी को 2000 फुट की गहराई से निकाला जा रहा है. पंजाब और हरियाणा में भी भूजल स्तर 70 प्रतिशत तक नीचे पहुंच चुका है. महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी स्थिति अच्छी नहीं है. भूमिगत पानी की मात्रा सीमित है और उसे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. ऐसे में जाहिर है कि पानी का अंधाधुंध दोहन कर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं. इसका एकमात्र उपाय यही है कि औद्योगिक इकाइयों और खनन व शीतल पेय कंपनियों से पानी का उचित मूल्य वसूला जाए. पानी पर कर लगाने का सुझाव गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जीआरबीएमपी) के पूर्व संयोजक प्रो. विनोद तारे ने दिया था. उनका मानना था कि नदियों के पानी और भूजल के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उद्योगों पर जल उपकर लगाया जाए.

झारखंड के पठारी क्षेत्रों में पथरीली चट्टानों के ऊपर 150 फीट तक मिट्टी की परत जमी है. भूवैज्ञानिक इसे वेदर जोन कहते हैं. बोरवेल या डीप बोरिंग से वेदर जोन के साथ नीचे की चट्टानें भी खोखली हो जाती हैं. इसके परिणामस्वरूप वेदर जोन में संरक्षित पानी भी नीचे के चट्टानों में चला जाता है. अगर इस भूजल के गिरते स्तर को कम करना है, तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देना होगा. अभी बिहार के सीतामढ़ी जिले में भूजल के गिरते स्तर से निपटने के लिए सोक पिट्स बनाए गए हैं. जल संरक्षण के इस प्रयास के तहत हैंडपंप के समीप एक साथ दो हजार से अधिक सोक पिट्स बनाए गए. इसके जरिए हैंडपंप का बहता पानी फिर से जमीन के जल स्तर तक पहुंचना संभव हो सका. इसके जरिए लगभग 26 करोड़ लीटर पानी का संचयन किया जा सकेगा. वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कुछ गांवों में भी सोक पिट्स के सफल प्रयोग किए गए हैं.

भूजल स्तर में तेजी से गिरावट के बावजूद हमने जल संरक्षण की कोई प्रणाली विकसित नहीं की है. अरबों घनमीटर वर्षा का जल हर साल बेकार चला जाता है. प्रति व्यक्ति सालाना जल की उपलब्धता के मामले में भारत चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से बहुत पीछे है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत जल सप्ताह में कहा था कि भारत में दुनिया की एक प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन यहां जल उपलब्धता केवल चार प्रतिशत ही है.

अभी खबर आई है कि मनरेगा के तहत 80 फीसद जल संरक्षण, सिंचाई और भूमि विकास से जुड़े कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया है. ज्यादातर कार्य उन राज्यों में पूरे नहीं किए गए, जिन जिलों को तीन साल के भीतर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है. महाराष्ट्र में, जहां सूखे की वजह से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, यहां सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित 40 प्रतिशत काम पूरे नहीं किए गए. अगर ये काम समय पर पूरे नहीं हुए, तब जल संरक्षण की यह नीति भी अधूरी रह जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

अमित शाह के गुणगान की वजह क्या है

जब मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के फैसले का निपटारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, तो संकेत स्पष्ट है कि राजनीति में बाहुबली सिर्फ मोदी नहीं हैं, बल्कि अमित शाह भी हैं. दरअसल, मोदी लहर से पूर्व भाजपा में रमन सिंह का कद काफी मज़बूत था. पार्टी में राजपूत लॉबी उनके साथ होने के कारण उनकी स्थिति मजबूत थी. उनकी ताजपोशी में अहम भूमिका तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह की रही. राजनाथ सिंह ने हर मुश्किल वक्त में रमन सिंह की मदद की. उन्हें बचाया. चूंकि उस वक्त पार्टी में अटल और आडवाणी की चलती थी और राजनाथ दोनों ही नेताओं के चहेते थे.

रूपेश गुप्ता

आजकल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जगह-जगह 'बोनस तिहार' को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं. वे जहां भी जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि किसानों को धान का यह बोनस पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सहयोग से मिला है. लेकिन बीजेपी के इन दोनों शीर्ष नेताओं की बेवजह तारीफ के सियासी मायने क्या हो सकते हैं?

पीएम मोदी तक बात समझ में आती है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की तारीफों के पीछे क्या वजह है? इसे लेकर कई तरह की बातें राजनीतिक फिज़ाओं में तैर रही है. पहली बात ये है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ही राज्यों से जुड़े मसलों को देख रहे हैं. अगर ऐसा है तो क्या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या इनकी तरह अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं. ऐसा दिखता नहीं है. तो फिर क्यों रमन सिंह बार-बार अमित शाह का ज़िक्र कर रहे हैं. क्या वाकई में धान का बोनस दिलाने में अमित शाह की अहम भूमिका रही है या वजह कुछ और भी है.

छत्तीसगढ़ में हर छह महीने में यह हवा बनती है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह बदले जाएंगे. यह ख़बर कांग्रेस और रमन सिंह विरोधियों के चेहरों पर मुस्कान ला देती है. लेकिन कुछ समय बाद सबके चेहरे मुरझाने लगते हैं और रमन सिंह फिर मुस्कुराते नजर आते हैं. पिछले दिनों उनके मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से विवाद के बाद राज्य में हालात बेहद बिगड़ गए थे. दोनों का मामला शाह

दरबार में पहुंचा. जहां दोनों नेताओं को समझा-बुझाकर शांत किया गया.

जब मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के फैसले का निपटारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें, तो संकेत स्पष्ट है कि राजनीति में बाहुबली सिर्फ मोदी नहीं हैं, बल्कि अमित शाह भी हैं. दरअसल, मोदी लहर से पूर्व भाजपा में रमन सिंह का कद काफी मज़बूत था. पार्टी में राजपूत लॉबी उनके साथ होने के कारण उनकी स्थिति मजबूत थी. उनकी ताजपोशी में अहम भूमिका तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह की रही. राजनाथ सिंह ने हर मुश्किल वक्त में रमन सिंह की मदद की. उन्हें बचाया. चूंकि उस वक्त पार्टी में अटल और आडवाणी की चलती थी और राजनाथ दोनों ही नेताओं के चहेते थे. इसलिए जब-जब रमन को हटवाने की मुहिम उनके विरोधियों ने की, राजनाथ सिंह के चलते उन्हें मुंह की खानी पड़ी. रमन सिंह के दूसरे तारणहार राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह रहे. वे रमन सिंह की लॉबिंग और उनकी ब्रान्डिंग का काम दिल्ली में करते रहे. इन दोनों के रहते रमन सिंह काफी सुरक्षित रहे.

लेकिन अटल और आडवाणी के राजनीति में पार्श्व में जाने के बाद से पार्टी के अंदरखाने के समीकरण बदल गए. सत्ता और संगठन में मोदी और शाह ही सर्वेसर्वा हो गए. उनकी मर्जी के आगे सब बेबस हो गए. राजनाथ सिंह की हैसियत किसी से छिपी नहीं है. सौदान सिंह संघ से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें ओड़ीशा की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर वहां फंसा दिया गया है. अब रमन सिंह की मजबूरी है कि शाह और मोदी को साधे रखें, क्योंकि दोनों ठाकुर नेताओं के दरकिनार होने के बाद केंद्र में रमन सिंह की स्थिति पहले जैसी मज़बूत नहीं रही.

रमन सिंह की शाह की जयकारे की दूसरी वजह जो बताई जा रही है, वो भी कम दिलचस्प नहीं है. कहा जा रहा है कि रमन सिंह की नज़र बीजेपी संसदीय बोर्ड के 12वें सदस्य पर है. अब तक इस पद पर उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू काबिज़ थे. लेकिन उनके उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस पद के कई दावेदार सामने आ गए हैं. संसदीय बोर्ड पार्टी का निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था होती है. इसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं. बोर्ड में पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते हुई थी. बाद में संसदीय बोर्ड द्वारा ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया.

चूंकि शिवराज और मोदी दोनों तीन-तीन बार के मुख्यमंत्री हैं, लिहाज़ा रमन सिंह बीजेपी के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री होने के नाते अपना दावा पेश कर रहे हैं. इस बोर्ड का सदस्य बनने के बाद केंद्र में रमन सिंह का कद बढ़ जाएगा. रमन सिंह की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है कि वे एक छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ से आते हैं, जहां केवल 11 लोकसभा की सीटें हैं.जबकि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी दावेदारी कर रहे हैं. फडणवीस के हक़ में ये बात भी जाती है कि वे आलाकमान के निर्देशों का बखूबी पालन करते हैं.

बताया जा रहा है कि रमन सिंह इसी तर्ज पर योजनाओं का श्रेय मोदी और शाह को देकर अपना स्थान पक्का करने की जुगत में हैं. वे जानते हैं कि उनकी कुर्सी पर जो भी खतरा है वो संसदीय बोर्ड के सदस्य बनने के बाद कम हो जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू-कश्मीर में डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं महिलाएं

हारून रेशी

जम्मू-कश्मीर विशेषकर कश्मीर घाटी में पिछले 27 वर्षों से जारी हिंसक घटनाओं से सबसे ज्यादा यहां की महिलाएं प्रभावित हुई हैं. पिछले ढाई दशकों के दौरान कई स्वयंसेवक संगठनों और विश्वसनीय संगठनों की तरफ से जारी की गई रिपोर्टों में साबित किया जा चुका है कि कश्मीर के हालात में यहां की महिलाओं की एक बड़ी संख्या तरह-तरह की परेशानियों और दुखों से पीड़ित हैं. महिलाओं के साथ बलात्कार भी होता है और उनके संबंधियों की हत्याएं भी हुई हैं, टॉर्चर भी हुआ है और उन्हें मनोवैज्ञानिक आघात भी पहुंचा है. कश्मीर की हिंसक स्थिति के नतीजे में यहां हजारों महिलाओं के बच्चे मारे जा चुके हैं. उनके सुहाग लुट गए हैं. शायद सबसे ज्यादा भयानक स्थिति का सामना उन महिलाओं को करना पड़ा है, जिनके पति वर्षों से लापता हैं. मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले तटस्थ संगठनों का कहना है कि पिछले 27 साल की अवधि में आठ से दस हजार तक कश्मीरी लापता हुए हैं. सरकारी स्तर पर मात्र चार लोगों के लापता होने की पुष्टि की गई है. इन लापता लोगों के घरवालों का आरोप है कि इन्हें फोर्स ने उठाकर गायब कर दिया है. उन महिलाओं के लिए, जिनके पति लापता हुए हैं, कश्मीर में अर्धविधवा कहा जाता है. धार्मिक आधार पर उन्हें तुरंत दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है. जबतक की धार्मिक या कानूनी तौर से संबंधित संस्थान उनके पतियों को मृत घोषित न कर दें, तबतक उन्हें विधवा नहीं कहा जा सकता है. अपने पति की वापसी या उन्हें किसी न्यायालय की तरफ से मृत घोषित करने की प्रतीक्षा में सैकड़ों अर्धविधवाएं अधेड़ उम्र को पार कर जाती हैं. ऐसी महिलाओं को ससुराल में संपति से हिस्सा भी नहीं मिलता है, क्योंकि जबतक ये तय न हो जाए कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो विधवा हो चुकी हैं, तबतक उन्हें पति की सम्पति में हिस्सा नहीं मिल सकता है. केवल ये एक पहलू नहीं है, जिससे पता चलता है कि कश्मीर की हिंसक परिस्थितियों के कारण कश्मीरी महिलाओं को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वो महिलाएं भी जीते जी मर गई हैं, जिनके बच्चे, पति या माता-पिता हिंसक हालात की भेंट चढ़ चुके हैं. हर नरसंहार के नतीजे में महिलाओं को ही आहत होना पड़ता है. ये सिलसिला बिना किसी

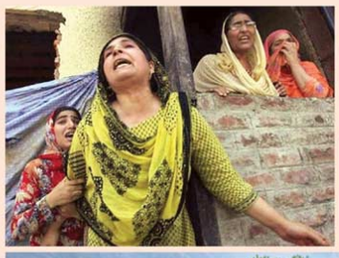

रोट-टोक के जारी है. डेढ़ वर्ष पहले विश्व स्वयंसेवी संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए ये सनसनीखेज खुलासा किया कि कश्मीर में 50 फीसदी महिलाएं डिप्रेशन की शिकार हैं. कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस के सहयोग से कश्मीर घाटी के तमाम दस जिलों के 399 गांवों में 5428 घरों में कराए गए इस सर्वे की रिपोर्ट दिसंबर 2015 में जारी की गई थी. किसी अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन की तरफ से कराया गया ये पहला सर्वे नहीं है. पिछले डेढ़ दशक के दौरान इस तरह के दर्जनों सर्वे कराए गए, जिनसे साबित होता है कि हिंसक हालात में महिलाओं की एक बड़ी संख्या शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित हो चुकी हैं.

विडंबना ये है कि न तो कश्मीर के हिंसक हालात बदलते हैं और न ही महिलाओं की दुर्दशा में कोई बेहतरी नजर आती है. इन दिनों कश्मीर घाटी में महिलाओं की चोटियां काटे जाने की रहस्यमय वारदातें हो रही हैं. पुलिस खुद स्वीकार कर चुकी है कि घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक महिलाओं के बाल कतरे गए हैं. सार्वजनिक क्षेत्रों में एक धारणा है कि सरकारी एजेंसियों ने महिलाओं की चोटियां काटे जाने का ये रहस्यमय सिलसिला शुरू किया है. एक थ्योरी ये भी फैल रही है कि सेना ने घाटी में मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किए हैं, उसे कामयाब बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे रणनीतियों में यह भी एक रणनीति का हिस्सा है. इसका मकसद जनता में रहस्यमय वारदातों का इस कदर डर बिठाना है कि वो किसी अजनबी यानी मिलिटेंट को अपने घरों में पनाह देने से इनकार कर दें. दूसरी तरफ पुलिस चोटियां काटे जाने की घटनाओं को झूठ समझती है. इंसपेक्ट जनरल ऑफ पुलिस ने हाल में यहां तक कहा है कि जिन महिलाओं ने चोटियां काटे जाने की शिकायत की है, उनका नार्को टेस्ट होगा, यानी पुलिस को उनके दावे पर भरोसा नहीं है. हालांकि चोटियां काटे जाने की घटनाएं घाटी के लगभग सारे जिलों में हुई हैं. इन सारी घटनाओं को झुठलाना एक बड़ी हिमाकत है. कुछ तो हो रहा है, ये अलग सवाल है कि ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? लेकिन ये बात निर्विवाद है कि चोटियां काटे जाने की वारदातें अब प्रतिदिन घटित हो रही हैं. इससे कश्मीरी महिलाएं सहमी हुई हैं. महिलाओं का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. छोटी-छोटी बच्चियां तक सहमी हुई हैं. सुबह सवेरे ट्यूशन के लिए जाने वाली लड़कियां अब अकेले घरों से बाहर निकलने में खौफ खा रही हैं. जाहिर है कि ये दहशत कश्मीरी महिलाओं को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर और भी कमजोर कर रही हैं. हालांकि चोटियां काटे जाने के इस रहस्यमय सिलसिले के कारण पूरी कौम भयभीत और प्रभावित हो चुकी है. लेकिन सच यही है कि सबसे अधिक असर महिलाओं पर हो रहा है. पता नहीं, कश्मीर के हालात के नतीजे में यहां की महिलाओं को कब तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? कब हालात बदलेंगे और कब यहां की महिलाएं इस दुविधा से बाहर आएंगी. सवाल ये भी है कि अगर कश्मीरी महिलाओं को इसी तरह लगातार खौफ और दहशत के और दिन गुजारने पड़ेंगे तो इसका कश्मीरियों की आने वाले नस्लों पर क्या असर पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश के प्रधानमंत्री से सार्वजनिक मंच पर नीतीश जैसे बड़े कद का मुख्यमंत्री अगर एक छोटी सी मांग करता है, तो उन्हें जर्रा बराबर भी इसका आभास नहीं होता कि पीएम उनकी मांग को ठुकरा पायेंगे. लेकिन नरेंद्र मोदी ने सलीके से उनकी मांग को ठुकरा कर उन्हें मायूस किया. हमने ऊपर जिक्र किया है कि ढाई महीने में मोदी द्वारा नीतीश को मायूस करने का यह चौथा उदाहरण है.

नीतीश की मांग पर मोदी की 'ना'

इर्शादुल हक

नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को रातोंरात बाय–बाय कह कर एनडीए के साथ सरकार बना लेने का ढाई महीने से भी कम समय गुजरा है. इन ढाई महीनों में नीतीश को पीएम मोदी से यह चौथी बड़ी मायूसी हाथ लगी है. ये तमाम मायूसियां ऐसी कि नीतीश अपने करीबियों से भी इस दर्द को शेयर करने से कतराते होंगे. हां, इतना जरूर है कि अकेले में यकीनन वे इन मायूसियों पर खुद को कोसते होंगे. बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित पटना युनिवर्सिटी शताब्दी समारोह में नीतीश कुमार, पीएम मोदी की मौजूदगी में जिस अंदाज में भाषण दे रहे थे, वह देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने से ज्यादा याचना से लबरेज था. मोदी की प्रशंसा में तारीफों के पुल बांधने के बाद नीतीश ने कहा कि पहली बार जब प्रधानमंत्री यहां आये हैं तो पटना विश्वविद्यालय और राज्य के लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे बड़ी हैं. हाथ जोड़ कर उनसे प्रार्थना करूंगा कि चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल युनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए. अगले सौ साल तक लोग याद रखेंगे कि पीयू कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और किनकी मेहरबानी से बना?

पटना युनिवर्सिटी के इस समारोह में जब नरेंद्र मोदी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने बड़े सलीके से 'ना' कह दिया. 'ना' कहने के लिए उन्होंने लम्बी भूमिका बांधी. लगभग चार मिनट तक की भूमिका में मोदी ने भी बदले में नीतीश की जमकर तारीफ की. वहां मौजूद लोगों के साथ बिहार और बिहारियों के योग्यता की प्रशंसा की और अंत में जो कहा, उसका अर्थ साफ था कि वह पीयू को सेंट्रल युनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देने वाले हैं. हां, अगर पीयू में योग्यता है तो वह उन बीस युनिवर्सिटियों से प्रतियोगिता करे और दस हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावित फंड का बड़ा हिस्सा ले सके तो ले ले.

देश के प्रधानमंत्री से सार्वजनिक मंच पर नीतीश जैसे बड़े कद का मुख्यमंत्री अगर एक छोटी सी मांग करता है, तो उन्हें जर्रा बराबर भी इसका आभास नहीं होता कि पीएम उनकी मांग को ठुकरा पायेंगे. लेकिन नरेंद्र मोदी ने सलीके से उनकी मांग को ठुकरा कर उन्हें मायूस किया. हमने ऊपर जिक्र किया है कि ढाई महीने में मोदी द्वारा नीतीश को मायूस करने का यह चौथा उदाहरण है. लेकिन इन मायूसियों की कड़ी का यह अंतिम पड़ाव है या नहीं, यह बात निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती. लेकिन इतना तय है कि इस समारोह से मायूसी हाथ लगने के बाद वे नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति अपनी कार्यशैली और रणनीति में कुछ बदलाव करने पर जरूर गौर कर रहे होंगे.

सवाल यह है कि नीतीश अब क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब खोजने से पहले यहां जरूरी है कि हम बाकी तीन मायूसियों और उसकी पृष्ठभूमि की चर्चा करें. साथ ही उन राजनीतिक हालात का पुनर्मूल्यांकन भी करें जिसके तार इन मायूसियों से जुड़े हैं.

नीतीश के लिए यह पहली मायूसी थी

वह 26 जुलाई 2017 की रात थी. जब नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों के साथ बैठक कर अचानक राजभवन कूच कर गए थे. वहां पहुंच कर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था. उस वक्त तक वह राजद–कांग्रेस वाले महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे. एक झटके में इस्तीफा देने के बाद, तयशुदा योजना के तहत उन्हें भाजपा गठबंधन के साथ आकर 27 जुलाई को नई सरकार का गठन करना था. इसी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के तहत जदयू की तरफ से यह खबर मीडिया को दी गई कि शपथग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे, लेकिन वे शरीक नहीं हुए. मोदी की तरफ से नीतीश के लिए यह पहली मायूसी थी. इसके बाद मोदी द्वारा महज 30 दिनों के बाद यानी 26 अगस्त 2017 को नीतीश कुमार को बड़ा झटका हाथ लगा. प्रधानमंत्री मोदी भयावह बाढ़ का जायजा लेने बिहार आए थे. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश

कुमार ने अपने आवास पर मोदी के लिए दोपहर के भोज का इंतजाम किया था. भोज की सारी तैयारियां मुकम्मल थीं, लेकिन अंतिम समय में मोदी ने उस भोज में शामिल होने से मना कर दिया था. यहां यह उल्लेखनीय है कि 2010 में जब भाजपा गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश ने अपने आवास पर भाजपा के दिग्गजों के लिए डिनर का आयोजन किया था, तब उसे नीतीश ने अचानक रद्द कर दिया था. नीतीश के इस फैसले से भाजपा नेताओं समेत नरेंद्र मोदी को काफी ठेस पहुंची थी. उस भोज के रद्द होने की घटना जाहिरी तौर पर भाजपा के लिए अपमानजनक थी. लेकिन जब पिछले 26 अगस्त को नरेंद्र मोदी, नीतीश के लंच में शामिल नहीं हुए तो कुछ लोगों ने इसे नीतीश से मोदी द्वारा लिए गए बदले के रूप में देखा था. स्वाभाविक तौर पर मोदी द्वारा भोज में शामिल न होना, नीतीश के लिए भारी मायूसी का कारण था. लेकिन नीतीश की मायूसियों का यह अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी.

पीयू बना राजनीति का अखाड़ा

पटना युनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को भाजपा ने जहां नीतीश कुमार को सुई चुभोने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं अपनी ही पार्टी के दो दिग्गजों को भी निशाने पर लेने के लिए चुना. यूं तो कहा जाता है कि पटना विश्वविद्यालय ने इस साल के शुरू में ही प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर दिया था और उन्होंने सहमति भी दे रखी थी. लेकिन इस दौरान जैसे–जैसे राजनीतिक हालात में परिवर्तन हुए, वैसे–वैसे पीएम मोदी और उनकी कोर टीम ने इस आयोजन को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति तैयार कर ली. आखिरकार नई रणनीति के तहत भाजपा ने अपने दो दिग्गज नेताओं को भी जख्म दिया. पटना विश्वविद्यालय ने अपने शताब्दी समारोह में अपने ऐसे तमाम पूर्ववर्ती छात्रों को भी आमंत्रित किया था जिन्होंने अलग–अलग क्षेत्रों में अपने योगदान से देश को गौरवान्वित किया था. वैसे तमाम नामों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा का है तो दूसरे यशवंत सिन्हा हैं. यशवंत सिन्हा ने हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में लिखे अपने लेख में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ाकर उनकी नींद हराम कर दी थी तो शत्रुघ्न लगातार तीन वर्षों से मोदी सरकार पर अपने तरीके से वार करते रहे हैं. इन दोनों नेताओं को इस समारोह में जगह नहीं दी गयी. माना जा रहा है कि भाजपा की कोर टीम ने एक खास रणनीति के तहत यह सब करवाया. अगर भविष्य में पटना युनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह याद किया जायेगा तो इस तथ्य को शायद ही नजरअंदाज किया जा सके कि यह आयोजन राजनीतिक बदला साधने का हथियार बन कर रह गया, जिससे पटना विश्वविद्यालय को ही इस सब की कीमत चुकानी पड़ी. इस आयोजन में पटना विश्वविद्यालय ने कितना खर्च किया, इसका सटीक आकलन तो विश्वविद्यालय प्रशासन ही कर सकता है, लेकिन आर्थिक रूप में उसने जितना खर्च किया उसकी भरपाई कहीं से और किसी तरह नहीं हुई होगी, क्योंकि इसके लिए किसी आर्थिक पैकेज की कोई घोषणा नहीं हुई, सिवा इसके कि रविशंकर प्रसाद ने अपने सांसद निधि से उसे एक करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. यह रकम तो युनिवर्सिटी के रंग रोगन, सजावट, मेहमाननवाजी और दीगर खर्च को भी शायद ही पूरी कर पाएगी.

बाढ़ राहत पर भी चढ़ा सियासी मुलम्मा

अगले चंद दिनों बाद नीतीश कुमार के लिए तीसरी मायूसी इंतजार कर रही थी. उसी दौरान जब बिहार बाढ़ की भयावह विभीषिका से जूझ रहा था, तब मोदी के साथ नीतीश ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था. नीतीश ने उन्हें दिखाया था कि कैसे यह बाढ़ 2008 की बाढ़ से भी ज्यादा विकराल है. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हवाई सर्वेक्षण के बाद बिहार को 1100 करोड़ रुपए, बाढ़ राहत के पैकेज के रूप में दिए थे. नीतीश कुछ ऐसी ही उम्मीद नरेंद्र मोदी से कर रहे थे, लेकिन हुआ एकदम इसके उलट. मोदी दिल्ली वापस गए तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर नीतीश कुमार को बुरी तरह से मायूस कर दिया. इसी क्रम में जब राजद ने पटना के गांधी मैदान में भाजपा भगाओ, देश बचाओ रैली का आयोजन किया तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये देने की खिल्ली उड़ाते हुए पूरा हिसाब–किताब समझाया था. आजाद ने कहा था कि 2008 की बाढ़ में राज्य के महज आठ जिले प्रभावित हुए थे. जबकि 2017 में 19 जिले प्रभावित हुए और राज्य को कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ. आजाद ने कहा था कि तब मनमोहन सरकार ने 1100 करोड़ दिये थे और अब मोदी सराकर ने महज 500 करोड़ देने की घोषणा की. उन्होंने 9 साल में रुपये के मूल्य में गिरावट का हिसाब भी समझाया था. निश्चित तौर पर मोदी सरकार द्वारा बिहार को महज पांच सौ करोड़ रुपये देने की घोषणा, नीतीश की उम्मीदों के एकदम विपरीत थी, जिसके कारण नीतीश कुमार बुरी तरह से मायूस हो कर रह गए थे. सच पूछिये तो मोदी द्वारा नीतीश कुमार को दी जाने वाली ये तीनों मायूसियां सिर्फ मायूसियां नहीं हैं, बल्कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला घटनाक्रम है. अब सवाल यह है कि जिस भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू का साथ छोड़ा, वही भाजपा नीतीश कुमार को ऐसा जख्म दे रही है तो इसके मायने भी नीतीश कुमार जरूर समझते होंगे.

मायूसियों का बदला चुका रहे मोदी

दरअसल यह वक्त–वक्त का फेर है. वक्त के बलवान होने की कहावत जिन्हें याद है, उन्हें पता होगा कि जब नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से बिहार की सत्ता पर काबिज थे, तब उस समय उनके सामने भाजपा कमजोर और बेबस थी. तब नरेंद्र मोदी बिहार के किसी राजनीतिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे, यह भी नीतीश कुमार तय करते थे. तब भाजपा से ज्यादा नरेंद्र मोदी, नीतीश के व्यवहार से आहत रहा करते थे. लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं था. लेकिन जब राजद के साथ मिलकर सरकार गठन के बाद महज डेढ़ साल में नीतीश ने उसे छोड़ कर फिर से भाजपा से हाथ मिलाकर सरकार बना ली, तब तक भाजपा राजनीतिक रूप से बलवान हो चुकी थी. नरेंद्र मोदी इस शक्ति का केंद्र बन चुके थे. इतना ही नहीं, केंद्र और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत देश के बड़े भू–भाग में भाजपा का झंडा लहरा रहा है. ऐसे में एक आम आदमी भी यह सोच सकता है कि मोदी रणनीतिक तौर पर नीतीश को मायूस करके अपनी एक–एक मायूसी का बदला चुका रहे हैं. तब नरेंद्र मोदी उन मायूसियों को बेबसी के साथ सहन कर रहे थे, तो अब नीतीश भी उसी तरह बेबस और मायूस हैं. भाजपा को पता है कि नीतीश बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं. संभव तो यह भी है कि अगर नीतीश भाजपा गठबंधन को छोड़ने का साहसिक ऐलान कर भी दें तो भाजपा यह मान कर चल रही है कि वे फिर से लालू से समर्थन नहीं ले सकते. अगर समर्थन लेने में सफल भी रहे तो अब लालू यादव उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले. लिहाजा बिहार का चुनाव तीनपक्षीय हो जाएगा और इसका भाजपा वैसे ही लाभ उठा लेगी, जैसा कि 2014 के चुनाव में उठा कर देख चुकी है. तब लालू और नीतीश अलग–अलग लड़े थे और बाजी भाजपा ने मार ली थी.

पिछले ढाई–तीन महीने की छोटी मुद्दत में भाजपा के टॉप लेवल के रणनीतिकारों ने नीतीश पर मायूसियों की जो लम्बी श्रृंखला शुरू की है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी वह अलग–अलग तरीके से चलती रहेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

रघुवर दास लाठी और गोली की ताक़त पर राज करना चाहते हैं: बाबूलाल मरांडी

झारखंड की राजनीति नित नई करवट ले रही है. जमीनी हकीकत रघुवर सरकार के वादों और उपलब्धियों के दावों को कठघरे में खड़ा कर रही है. सरकार के 1000 दिन की सफलता के शोर पर अब विपक्ष के सवाल हावी होने लगे हैं. विपक्ष की ऐसी ही एक आवाज हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी. झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी झारखंड की राजनीति की हर नब्ज से वाकिफ हैं. वे हर विषय पर अपनी मुखर राय रखते हैं. प्रदेश के हाल के हलचल पर उनसे बातचीत की है, *राघवेंद्र* ने. पेश हैं, बातचीत के प्रमुख अंश...

प्रश्न: राज्य की वर्तमान सरकार के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं?

उत्तर: रघुवर सरकार सिर्फ चंद व्यापारिक घरानों के लिए काम कर रही है और किसानों को बेघर करने पर तुली है. यह सरकार आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है. जो आदिवासी या किसान अपनी जमीन छीनने का विरोध करते हैं, उनपर ये गोलियां चलवा रहे हैं. चुनिंदे अपराधियों को संरक्षण दे रही है रघुवर सरकार. आदिवासी विरोधी इस सरकार ने पूरे राज्य के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया है. जनता इस सरकार से बहुत दुखी है.

प्रश्न: सीएनटी और एसपीटी के मसले पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन के समय ही इसकी रूपरेखा तय हो गई थी, आपका क्या कहना है?

उत्तर: सभी मिलकर चल रहे हैं. रघुवर दास जब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो अर्जुन मुंडा को भी दूध का दूध और पानी का पानी करने की आवश्यकता है. हेमंत सोरेन के समय में टीएसी की मीटिंग में यह मामला आया था, उनको उसी वक्त इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया. हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करें, लेकिन दोनों मिले हुए हैं. ऐसे में श्वेत पत्र सीएम क्यों जारी करेंगे. मुख्यमंत्री जबरन एक्ट में बदलाव करने पर तुले थे. लेकिन जब जनता ने पूरी ताकत से विरोध किया. हमलोगों ने और पूरे विपक्ष ने अपना आंदोलन तेज किया, तब जाकर रघुवर सरकार झुकी. दरअसल, यह सरकार न लोकतान्त्रिक तरीके में विश्वास करती है और ना ही जन भावनाओं को समझना चाहती है. इनकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन किए जाने का विरोध किया, तब भी ये नहीं सुन रहे थे. रघुवर दास लाठी और गोली की ताकत पर राज करना चाहते हैं.

प्रश्न : आपको नहीं लगता है कि कार्डिनल सीएनटी और एसपीटी एक्ट पर सियासत कर रहे थे!

उत्तर: बिल्कुल नहीं, कार्डिनल भी हमारे ही बीच से हैं. एक जागरूक आदमी को जो करना चाहिए, वही वे कर रहे हैं. कार्डिनल ने अपने दायित्व को निभाते हुए राज्यपाल से इस मसले पर सोच विचार कर निर्णय लेने का आग्रह किया था. भाजपा ने कार्डिनल को लेकर जिस तरह से हाय तौबा मचाया, उससे ही अंदाजा लगा था कि सरकार पूरी तरह से राजनीति कर रही है.

प्रश्न: झारखंड विकास मोर्चा में लोग आते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?

उत्तर: धारा के विपरीत चलना बहुतों के बूते की बात नहीं है. यह देखकर कि राह कठिन है, लोग साथ छोड़ देते हैं. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जाने वालों को मैं बड़ी आसानी से बाय-बाय करता हूं.

प्रश्न: आपकी पार्टी छोड़ कर जाने वाले लोग प्रदीप यादव को पार्टी छोड़ने का कारण बताते हैं, ऐसा क्यों?

प्रश्न: हमारी पार्टी छोड़कर नेता जाते और चुपचाप बैठ जाते, तो उनकी बातों पर मुझे भी भरोसा होता. लेकिन जो लोग गए वे सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए. उनकी दलील वहीं पर समाप्त हो जाती है. मुझे जब लगा कि भाजपा जनता के लिए बेहतर काम नहीं कर रही है, तो मैंने भी पार्टी छोड़ी. उसके बाद से आज तक कई पार्टियां मुझसे संपर्क बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया. मेरे सामने कभी इस तरीके की बातें कोई नहीं करता है. अगर करता तो उन्हें पार्टी छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जहां तक प्रदीप यादव की बात है, वे संघर्ष करने वाले नेता हैं. अभी पूरे राज्य ने देखा कि अडानी का विरोध करने पर कैसे प्रदीप यादव को गलत तरीके से जेल भेजा गया. ऐसे में कोई उनका विरोध कैसे कर सकता है.

प्रश्न: झारखंड विकास मोर्चा छोड़कर गए छह विधायक भाजपा में हैं, उन पर कोई फैसला अब तक नहीं आया है, क्यों?

उत्तर: राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधानसभा अध्यक्ष भी उन्हीं के हैं. उनको पता है कि संविधान क्या कहता है. वे जानते हैं कि अगर हमारे विरोध में फैसला देंगे, तो हम अदालत जाएंगे और उनकी दुर्गति होगी. इसलिए वे जान बूझकर फैसला टाल रहे हैं. अध्यक्ष को तो चाहिए कि चुनाव आयोग से लिखित रूप में जानकारी लें कि क्या झारखंड विकास मोर्चा ने बीजेपी में विलय किया है या नहीं. तकनीकी रूप से मामले को लटकाए रखने की कोशिश की जा रही है. यह लोकतंत्र का अपहरण करने जैसा है.

प्रश्न: आखिर अडानी को लेकर इतना विरोध क्यों है?

उत्तर: क्या अडानी चला जाएगा तो झारखंड नहीं रहेगा, जब अडानी नहीं था, तो क्या झारखंड नहीं था. यह सरकार अपने आकाओं को खुश करने के लिए जबरन किसानों की जमीन छीन कर अडानी को दे रही है. जब जन प्रतिनिधि इसका विरोध करते हैं, तो रघुवर सरकार चुने हुए जन प्रतिनिधि की आवाज़ बंद करने के लिए उन्हें जेल में डाल देती है. अडानी के पावर प्लांट से एक वाट बिजली भी झारखंड को नहीं मिलने वाली. इस प्लांट से उत्पादित बिजली बाहर भेजी जाएगी.

प्रश्न: रघुवर दास के मंत्री और विधायक उनसे नाराज हैं. आपको क्या लगता है?

उत्तर: नाराज कोई भी नहीं है. स्वार्थ और पैसे की पॉलिटिक्स में टकराव होती है, वही हो रहा है. यदि कोई नाराज होता, तो वह विरोध में खड़ा होता, बगावत करता. यह सरकार भ्रष्टाचार का संस्थाकरण कर रही है. सभी अपने-अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं. जब किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो वो नाराज़ होने का दिखावा करने लगते हैं. जनता जनार्दन बड़ी समझदार है. वह सब देख रही है और समय आने पर जनता सबका हिसाब करेगी.

प्रश्न: पलामू की एक छात्रा इशिता सिंह की मौत के बाद जब उसके परिजन मुख्यमंत्री से गुहार लगाने गए, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें ही अपमानित कर दिया. आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते?

उत्तर: यह घटना बहुत दुखद है. इससे ज्यादा बदतमीजी और कुछ नहीं हो सकती है. मैं अगर मुख्यमंत्री रहता, तो तुरंत पूरे मामले की जांच कराता. शासन का यह शिष्टाचार भी है कि आपको विक्टिम के साथ खड़ा रहना है और उसे न्याय मिले, इस हेतु प्रयास करना है. कोई मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से किसी विक्टिम को डांटे और उसे अधिकारियों के सामने अपमानित करे, इससे ज्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता. अधिकारियों ने यह समझा होगा कि मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करने का संकेत दे रहे हैं. विक्टिम को लगा होगा कि मुख्यमंत्री आरोपी को बचाना चाहते हैं. हुआ भी वही, इतने गंभीर मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

प्रश्न: 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं?

उत्तर: हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं. फैसला जनता को करना है, क्योंकि मेरी पार्टी जनता के लिए राजनीति करती है. हम हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं. किसी के साथ अन्याय होता है, तो हम उनके साथ होते हैं. आज आदिवासी किसान मजदूर सब के साथ हम खड़े हैं. राज्य सरकार के हर गलत फैसले के खिलाफ हमारी पार्टी जनता के बीच जा रही है. झाविमो हर जन आंदोलन की अगुआई कर रहा है.

प्रश्न: आगे आपकी पार्टी की रणनीति क्या है?

उत्तर: झारखंड विकास मोर्चा किसानों और युवाओं पर फोकस कर रही है. हम अलग अलग क्षेत्र में चल रहे जन आंदोलनों से जुड़ रहे हैं. हम लोगों को बता रहे हैं कि स्कूलों में बिल्डिंग है पर मास्टर नहीं, ऐसे ही अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं. जब मास्टर नहीं हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी? ये विकास का कौन सा मॉडल है? यह सरकार झारखंड के छात्रों और युवाओं का भविष्य खराब करना चाहती है. जमीन है नहीं, केवल बड़े उद्योगपतियों के साथ एमओयू कर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है. हम देशज विकास की बात कर रहे हैं, ताकि विकास भी हो और गांव के लोगों को उजड़ना भी नहीं पड़े. ■

feedback@chauthiduniya.com

हमारी पार्टी छोड़कर नेता जाते और चुपचाप बैठ जाते, तो उनकी बातों पर मुझे भी भरोसा होता. लेकिन जो लोग गए वे सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए. उनकी दलील वहीं पर समाप्त हो जाती है. मुझे जब लगा कि भाजपा जनता के लिए बेहतर काम नहीं कर रही है, तो मैंने भी पार्टी छोड़ी. उसके बाद से आज तक कई पार्टियां मुझसे संपर्क बनाना चाहती हैं, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया. मेरे सामने कभी इस तरीके की बातें कोई नहीं करता है. अगर करता तो उन्हें पार्टी छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जहां तक प्रदीप यादव की बात है, वे संघर्ष करने वाले नेता हैं. अभी पूरे राज्य ने देखा कि अडानी का विरोध करने पर कैसे प्रदीप यादव को गलत तरीके से जेल भेजा गया. ऐसे में कोई उनका विरोध कैसे कर सकता है. क्या अडानी चला जाएगा तो झारखंड नहीं रहेगा, जब अडानी नहीं था, तो क्या झारखंड नहीं था. यह सरकार अपने आकाओं को खुश करने के लिए जबरन किसानों की जमीन छीन कर अडानी को दे रही है. जब जन प्रतिनिधि इसका विरोध करते हैं, तो रघुवर सरकार चुने हुए जन प्रतिनिधि की आवाज़ बंद करने के लिए उन्हें जेल में डाल देती है.

चौथी दुनिया
चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी
पूरे हफ्ते ख़बरों का ख़ज़ाना
जुड़िए...
Editor's Take & दो-टूक
में देश के सबसे निर्भीक पत्रकार संतोष भारतीय से
Fourth Dimension में
छप क्या रहा चौथी दुनिया के नए अंक में
Crime Time में हर दिन अपराध की पड़ताल
हम ख़बरें बनाते ही नहीं दिखाते भी हैं

भाजपा के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है

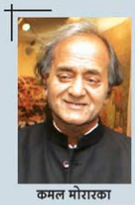

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

मेक इन इंडिया के तहत कोई बड़ी इंडस्ट्री गुजरात तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी कोने में नहीं आई है. इन सारी चीजों ने निराशा का रूप ले लिया है और सत्ता विरोधी लहर सामने आ रही है और विपक्षी नेता को अब महत्व मिल रहा है. आरएसएस ने आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसके मुताबिक भाजपा के लिए गुजरात का रास्ता आसान नहीं होगा.

गुजरात चुनाव की खबरों के अलावा देश में कोई बहुत अधिक राजनैतिक हलचल नहीं है. गुजरात में राहुल गांधी का ऐसा अभिनन्दन किया जा रहा है, जिसकी आशा उनके सबसे कट्टर समर्थक को भी नहीं रही होगी. ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई, बल्कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि भाजपा की लोकप्रियता घटी है. इसके कई कारण हैं. ये चीजें गुजरात के नेताओं के भाषण में भी नजर आ रही हैं. खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण में, इसीलिए उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है. लेकिन उनका ये कहना कि मैं विकास हूं, मैं गुजरात हूं, उनके अहंकार के अलावा कुछ नहीं दिखाता और न ही इससे कोई मकसद पूरा होता है. लोग ये देखना चाहते हैं कि कितने उद्योग आए, कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए, भविष्य की योजनाएं क्या हैं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है. मेक इन इंडिया के तहत कोई बड़ी इंडस्ट्री गुजरात तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी कोने में नहीं आई है. इन सारी चीजों ने निराशा का रूप ले लिया है और सत्ता विरोधी लहर सामने आ रही है और विपक्षी नेता को अब महत्व मिल रहा है. आरएसएस ने आंतरिक सर्वे करवाया है, जिसके मुताबिक भाजपा के लिए गुजरात का रास्ता आसान नहीं होगा. नतीजतन, आरएसएस प्रमुख ने विजयादशमी के अपने भाषण में कहा कि जब तक आप जीएसटी की वजह से छोटे और मंझोले व्यापारियों को राहत नहीं देंगे, तब तक आपकी मुश्किलें कम नहीं होंगी. उसके फौरन बाद ही सरकार ने जीएसटी में छोटे व्यापारियों को थोड़ी राहत देने की घोषणा की. ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक चीज तो तय है कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है. उन्हें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिए.

अगले कुछ हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि गुजरात में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो आसार दिख रहे हैं, वो भाजपा के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं. हाल में, राजकोट के चोटीला में नरेन्द्र मोदी के भाषण के दौरान ही लोग सभास्थल से बीच में उठ कर जाने लगे थे. योगी आदित्यनाथ सोचते हैं कि वो भी मोदी बन गए हैं और गुजरात, केरल

अगले कुछ हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि गुजरात में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो आसार दिख रहे हैं, वो भाजपा के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं. हाल में, राजकोट के चोटीला में नरेन्द्र मोदी के भाषण के दौरान ही लोग सभास्थल से बीच में उठ कर जाने लगे थे. योगी आदित्यनाथ सोचते हैं कि वो भी मोदी बन गए हैं और गुजरात, केरल आदि का दौरा कर रहे हैं. शायद वो अमित शाह के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनने या देखने के लिए जनता नहीं आ रही है. ये जान लेना उनके लिए अच्छा होगा कि आप योगी का वस्त्र पहन कर बार-बार धार्मिक जोश को भड़का नहीं सकते हैं.

आदि का दौरा कर रहे हैं. शायद वो अमित शाह के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुनने या देखने के लिए जनता नहीं आ रही है. ये जान लेना उनके लिए अच्छा होगा कि आप योगी का वस्त्र पहन कर बार-बार धार्मिक जोश को भड़का नहीं सकते हैं. हिन्दुत्व को बचाने के लिए ताजमहल गिराना, बिना ये जाने कि मुगल कौन थे, लोदी कौन थे, खिलजी कौन थे, उनके इतिहास को मिटाना, भारत इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका है. पिछले 70 सालों में भारत इतना आगे निकल चुका है कि उसे योगी जितना पीछे लाना चाहते हैं, नहीं आ सकता. मोदी ने एक अलग सुर के साथ शुरुआत की थी और देश को तीन साल पहले उनसे बहुत आशाएं थीं या तो वे आरएसएस की विचारधारा के दवाब में आ गए या फिर उन्हीं के अतिआत्मविश्वास ने उनके लिए परेशानियां खड़ी कर दी. जिस तरह नोटबन्दी लागू की गई और जिस तरह जीएसटी जैसी भारी भरकम प्रक्रिया लाई गई, जिसकी वजह से एक आम व्यापारी प्रभावित हुआ. एक अन्दाज के मुताबिक आम व्यापारी वर्ग में देश के अंदर 5 करोड यूनिट्स हैं. यदि एक यूनिट से 4 या 5 व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, तो ये संख्या 20 करोड़ हो जाती है. लिहाजा, केवल भाषणबाजी से भाजपा अगला चुनाव नहीं जीत सकती. आपको इस वर्ग के तनाव को कम करना ही पड़ेगा. भले ही यह वर्ग ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन जब वोट का सवाल आएगा तो इनकी संख्या जरूर प्रभावकारी साबित होगी. हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार को संकेत मिल रहे हैं.

दूसरी खबर ये है कि हम दुनिया के हंगर इंडेक्स में 55वें स्थान से लुढ़क कर 100वें स्थान पर पहुंच गए हैं. हम इस मामले में खराब शासन व्यवस्था वाले देश, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं. जाहिर है, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून, जो यूपीए के कार्यकाल में बना था, उस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए. आखिरकार, जीडीपी के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन देश उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है. भारत जैसे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां समृद्धि है और कुछ ऐसे हैं, जहां भयानक भूख और गरीबी है. इससे निपटना पड़ेगा. हमें नहीं मालूम है कि सरकार क्या कर रही है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि नीति आयोग क्या कर रहा है? आखिरकार, नीति आयोग एक थिंक टैंक के तौर पर स्थापित किया गया था, ताकि वो इस तरह के मामलों पर विचार कर समाधान दे, नीति तैयार करे. लेकिन, लोगों को ये नहीं मालूम कि वो कर क्या रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राजनाथ सिंह के पांच सी और हमारे पांच डब्ल्यू

शुजात बुख़ारी

एक महीने पहले, 11 सितंबर को, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर मसले से निपटने के लिए एक योजना की घोषणा की थी. वो घोषणा इस आशा के साथ की गई थी कि जमीनी सतह पर बदलावों से मसले का समाधान निकल सकता है. उन्होंने संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों की घोषणा की, जिसे उन्होंने 5-सी कहा. इसमें शामिल शब्द हैं-कम्पैशन (करुणा), कम्युनिकेशन (संचार), को-एक्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व), कॉन्फिडेंस बिल्डिंग (विश्वास-बहाली) और कंसिस्टेंसी (स्थिरता). इस मुद्दे पर राजनैतिक प्रगति को लेकर वे गंभीर दिखते हैं. एक साल पहले भी उनका यही स्टैंड था.

बुरहान वानी के मारे जाने के बाद, 2016 की गर्मियों में भड़की हिंसा जब अपने शबाब पर थी, तब राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशों पर दिल्ली में भाजपा की सरकार ने पानी फेर दिया. भाजपा सरकार ने कश्मीर पर कठोर दृष्टिकोण अपनाया था. उस समय सुरक्षा-उन्मुख दृष्टिकोण के समर्थकों के सामने राजनाथ सिंह ने खुद को अलग थलग पाया था. बहरहाल यह पहला मौक़ा नहीं है, जब राजनाथ सिंह ने मसले के स्थायी हल की बात की हो, हालांकि वे यह नहीं बताते कि हल कैसे होगा? पिछले महीने अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर से शुरू होने वाले पांच शब्दों के जरिए राजनाथ सिंह ने अपनी नीति को रेखांकित किया. यदि इस नीति को अक्षरशः लागू किया जाता है, तो यह एक उत्साहप्रद नीति है. लेकिन अभी तक इसमें कोई पहलकदमी नहीं हुई है. बहरहाल 5 सी के बारे में हम स्वयं कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं व्हाई (क्यों), व्हेयर (कहां), व्हेन (कब), व्हू (कौन) और व्हूम (किसे).

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीन साल के अनुभव बताते हैं कि गृह मंत्री द्वारा रेखांकित 5-सी में से किसी का पालन नहीं किया गया है. अभी तक का जो प्रयास है, वो कश्मीर में जारी संघर्ष के राजनैतिक संदर्भ, जो समस्या के समाधान पर केंद्रित है, को ध्वस्त करने की रही है. सबसे पहले कम्पैशन (करुणा) की बात करते हैं. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्वीकारोक्ति के मुताबिक, वर्ष 2016 के कुछ महीनों के दौरान उसने लोगों पर 1.3 मिलियन पैलेट दागे. इन पैलेटों की चोट से कई कश्मीरी युवा अंधे और अपंग हो गए. उनके नुकसान की भरपाई के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. करुणा का मतलब कश्मीरी लोगों को अपना समझना और उनका दिल जीतना होता है. लेकिन इसके बजाय अत्यधिक बल प्रयोग को उचित ठहराया गया.

कम्युनिकेशन (संवाद) की बात करें, तो इसका भी साफ़ अभाव नज़र आता है. सरकार का संवाद उन्हीं के साथ स्थापित रहा, जो कश्मीर में भारत के शासन को चुनौती नहीं देते. कश्मीर की समस्या पर बात के नाम पर बार-बार भारत-समर्थक राजनीतिक पार्टियों से बात कर, सरकार लोगों के साथ संवाद के विचार को नकारती रही है. सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ संवाद के दरवाज़े बंद करना न तो पूर्व में सहायक साबित हुआ है और न ही वर्तमान या भविष्य में साबित होगा. हुर्रियत जैसे संगठनों के साथ राजनैतिक संवाद से इनकार कर सरकार उन्हें भी अपनी ताक़त बढ़ाने का मौक़ा दे रही है. उनके साथ संवाद स्थापित करने से उनकी काबिलियत का भी अंदाज़ा होगा और लोग अपने नेताओं की सलाहियत का भी अंदाज़ा लगा लेंगे. लेकिन यह तब तक नहीं होगा, जबतक बिना शर्त उनके साथ किसी तरह का संवाद स्थापित नहीं हो जाता.

को-एक्जिस्टेंस (सह-अस्तित्व) का भी ज़मीनी स्तर पर अभाव है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान कश्मीरी समाज को अलग-थलग करने की कोशिश की गई है. यदि जम्मू और कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हैं, तो इस विचार को दिल्ली ने ही नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उसने सह-अस्तित्व के विचार को अहमियत नहीं दी. नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध सैन्य शक्ति का इस्तेमाल, लगातार 54 दिनों तक उन्हें कर्फ्यू में रखना और उन लोगों की रक्षा करना, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बताते हैं कि यहां के लोगों का एक अलग अस्तित्व है. लोगों ने हर नुक्कड़ और गली में सरकार को चुनौती पेश की है. युवाओं ने हर जगह घृणा व्यक्त किया है और हर जगह राजनीतिक समाधान की लालसा दिखाई दे रही है. हम किस सह-अस्तित्व की बात कर रहे हैं?

कॉन्फिडेंस बिल्डिंग (विश्वास-बहाली) को भी गहरा सदमा पहुंचा है. घाटी में अधिक से अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती से भी विश्वास-बहाली नहीं होती है. विश्वास बहाली उन उपायों से होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों के अस्तित्व, उनकी दिनचर्या और उनके अधिकारों से जुड़ी होती हैं. दरअसल लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है. यह सरकार सामंजस्य की किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देती. जब संस्थाएं न्याय नहीं देंगी, तो विश्वास-बहाली की कोई आशा बेकार है. 'द अदर' यानी गैर होने की भावना विश्वास बहाली को और अधिक संकुचित कर देती है. विश्वास-बहाली का बेहतरीन उदाहरण, पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के शासन काल में सामने आया था. उन्होंने 18 अप्रैल 2003 को श्रीनगर से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक मिसाल कायम किया था. इस दौरान विभाजित जम्मू-कश्मीर के बीच की सड़कों को खोला गया और नियंत्रण रेखा (एलओसी) व्यापार की शुरुआत की गई ताकि सीमा की दोनों तरफ के लोग शांति से जीवन यापन कर सकें. यही नीति मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जारी रही, लेकिन आज विश्वास-बहाली के प्रयास लाइफ सपोर्ट पर चल रहे हैं. उन्हें मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है. लिहाज़ा विश्वास-बहाली केवल खोखला नारा है.

कश्मीर जैसे मुद्दे से निपटने का एकमात्र तरीका नीतिगत एकरूपता है. हर स्थिति में विदेशी नीति को स्थिर होना चाहिए, लेकिन इसमें भी उठा पटक जारी रही.

गृह मंत्री की योजना को सिरे से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक व्यावहारिकता होनी चाहिए. सिंह अकेले नहीं हैं, जिसने ये पोजिशन लिया है. जम्मू और कश्मीर पर बीजेपी के महत्वपूर्ण आदमी राम माधव ने भी बातचीत की. 21 सितंबर को उन्होंने श्रीनगर में कहा कि हमने शुरू से कहा है और हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे दरवाजे राज्य के सभी हितधारकों के लिए खुले हैं. वे राज्य सरकार के साथ बातचीत करने या जो केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं, उनका स्वागत है. ये बयान उत्साहजनक हैं, लेकिन मूल सवाल यह है कि इस दिशा में कौन आगे बढ़ रहा है?

पूर्व-शर्त दोनों पक्षों पर लागू होनी चाहिए. यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह वार्ता की इस प्रक्रिया को शुरू करे. हालांकि इसे जमीन पर चुनौती दी गई है. माधव एजेंडा ऑफ एलायंस के वास्तुकार भी हैं, जिन्होंने बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अप्राकृतिक गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पाकिस्तान और हुर्रियत के साथ बातचीत भी एओए का हिस्सा है. जब वार्ता के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई, तब इस दिशा में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया. यही कारण है कि सिंह को पांच सी का जवाब पांच डब्ल्यू से देना पड़ रहा है.

हालांकि कुछ गैर-सरकारी पहल की गई. मोर्चे पर सबसे बड़ी सफलता पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अगुआई में कन्सर्न्ड ग्रुप ऑफ सिटिजन वाली पहल थी. एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) कपिल काक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला, पत्रकार भरत भूषण और कार्यकर्ता सुशोभा बर्वे के साथ तीन यात्राओं पर वे आए और हर यात्रा पर ग्राउंड रिपोर्ट पेश की.

यशवंत सिन्हा की अक्टूबर 2016 की कश्मीर यात्रा ने स्थिति को आसान बनाने में मदद की. लोगों ने इसे महत्व दिया था. चूंकि वे एक वरिष्ठ भाजपा सदस्य हैं, इसलिए यह धारणा थी कि सरकार उनकी बात सुनेगी. वे सैयद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक से मिले, जो इस बात पर बल देना चाहते थे कि वे बातचीत के खिलाफ नहीं हैं, अगर नई दिल्ली गंभीर है और कोई शर्त नहीं रखती. इस समूह ने अपनी रिपोर्टों में कश्मीर से निकलने वाली चिंताओं पर प्रकाश डाला. लोगों ने इसमें विश्वास जताया और उनके साथ बातचीत की. लेकिन इस यात्रा से कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि मोदी सरकार ने इस समूह के प्रयासों को महत्व नहीं दिया. यशवंत सिन्हा को सार्वजनिक रूप से बताना पड़ा कि जब वे मोदी से कश्मीर पर बात करना चाहते थे, तब उन्होंने मना कर दिया.

जम्मू और कश्मीर पर नरम होना भाजपा के लिए मुश्किल है, ऐसे में गैर-सरकारी दृष्टिकोण बातचीत के लिए कुछ रास्ता तैयार कर सकता था, जिसे राज्य तंत्र आगे उपयोग कर सकता था. लेकिन प्रतिष्ठित लोगों के प्रयासों को खारिज करते हुए कठोर नीति अपनाई जा रही है. इस पृष्ठभूमि में, राजनाथ सिंह और राम माधव द्वारा दिया गया ऑफर बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है. वार्ता से इंकार करते हुए, मोदी सरकार ने कश्मीर की स्थिति से निपटने के लिए सैन्य दृष्टिकोण की अपनी नीति को मजबूत किया है. ऐसी नीति कट्टरवाद और हिंसा के लिए अवसर प्रदान कर सकता है. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल न होना लोकतंत्र के लिए भयावह संकेत है

कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनका उत्तर कभी नहीं मिलता है. हर दिवाली पर, दिवाली से पहले प्रदूषण स्तर की बात होती है. बच्चे पटाखे न जलाएं, इसकी शिक्षा स्कूलों में दी जाती है. पर घर में मां-बाप बच्चों के लिए पटाखे खरीदते हैं और इस बार तो गजब हो गया. हालांकि, पटाखे कम चले, लेकिन प्रदूषण स्तर बढ़ गया. इसका मतलब, कई इलाकों में पटाखे बहुत जले. लेकिन इससे अलग, एक और महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे बेचने पर पाबंदी लगाई जाती है. दिवाली की रात जिस तरह से टुकड़ों-टुकड़ों में पटाखे चले, उससे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोगों के सर से गुजर गया. बहुत छोटी संख्या में लोगों ने इसे माना, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इसे नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बेचने के ऊपर पाबंदी लगा दी, इसके बावजूद पटाखे बिके. कुछ व्यापारियों के ऊपर एफआईआर भी हुई. लेकिन 30 या 35 व्यापारियों पर केस करने या पाबंदी का असर नहीं पड़ा. हर जगह पटाखे खुलेआम बिक रहे थे और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही हो रहा था. दिवाली के अगले दिन टीवी के जरिए सवेरे से जो खबरें फैलीं, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जिक्र कम, लेकिन राजधानी क्षेत्र का जिक्र ज्यादा हो रहा है. वहां प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और इसके अलग-अलग हिस्सों की रिपोर्ट दिखाई जा रही थी.

दिमाग में ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की बात लोगों ने क्यों नहीं मानी? ये सवाल जितना हमारे मन में है, उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के मन में होनी चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की बात लोग मानते क्यों नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल की जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें. राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन नहीं करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई मायने नहीं रखता है. सुप्रीम कोर्ट को इस पर इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की साख घट रही है, सुप्रीम कोर्ट का असर घट रहा है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर प्रशासन मानने से इंकार कर दे या सरकारें उसे अनदेखा कर दें तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकत है कि उनके ऊपर अमल करवा पाए. दरअसल, इसका थोड़ा बहुत दोष सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है. हम जब देखते हैं कि पिछले कितने वर्षों का समय हम परीक्षण के लिए रखें ये आप तय करें, लेकिन मान लीजिए कि हमने 20 साल का समय रखा. इस 20 साल के समय सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हुए हैं, उनमें जिनका रिश्ता केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से है, उन फैसलों में से लगभग 40 प्रतिशत फैसलों पर सरकारों ने कोई अमल नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कागज पर लिखी इबारत बनकर रह गई. उस पर अमल हुआ ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मॉनिटरिंग कभी नहीं की कि वो जो फैसले देते हैं, उनका पालन राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार कैसे करती हैं? अब राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने का असर नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था दरक रही है. अब जब मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कुछ दोष जाता है, तो उसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जितना ज्यादा राजनीतिज्ञों के साथ मित्रता करेंगे, उनके साथ दिखाई देंगे, उनके साथ पार्टियां करेंगे या अपने लिए रिटायरमेंट के बाद जगह तलाशेंगे और उन्हें प्रभावित कर अपने लिए लाभ चाहेंगे तो उसका परिणाम यही होगा, जो दिवाली पर पटाखे न बेचने के आदेश का हुआ है.

> दरअसल हमारा देश जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए है, उसमें तीनों अंगों की समान भूमिका है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका सामान्य भूमिका से थोड़ी सी ज्यादा है. न्यायपालिका को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकता है और अपना फैसला दे सकता है. जिस फैसले की काट संसद संविधान संशोधन करके ही कर सकती है. अगर संविधान संशोधन नहीं होता है या उतना बहुमत किसी सरकार के पास नहीं है जितना संविधान संशोधन के लिए चाहिए, तब तक वो फैसला प्रभावी रहता है. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पिछले 40 साल या 20 साल का समय देखें, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें आपस में द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, कुछ पर महाभियोग की कार्रवाई भी हुई. इन सारे अंतर्विरोध में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख कहीं खोता चला गया.

दरअसल हमारा देश जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाए हुए है, उसमें तीनों अंगों की समान भूमिका है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका सामान्य भूमिका से थोड़ी सी ज्यादा है. न्यायपालिका को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकता है और अपना फैसला दे सकता है. जिस फैसले की काट संसद संविधान संशोधन करके ही कर सकती है. अगर संविधान संशोधन नहीं होता है या उतना बहुमत किसी सरकार के पास नहीं है जितना संविधान संशोधन के लिए चाहिए, तब तक वो फैसला प्रभावी रहता है. लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पिछले 40 साल या 20 साल का समय देखें, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें आपस में द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, कुछ पर महाभियोग की कार्रवाई भी हुई. इन सारे अंतर्विरोध में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख कहीं खोता चला गया. सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले लोगों की नजर में ऐसे रहे, जिन फैसलों ने देश के ताने-बाने के ऊपर या जिसे हम कहें संविधान के ताने-बाने से लोगों को दूर ले जाते दिखे. शायद इसीलिए धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सरकारों ने, केन्द्र सरकारों ने और प्रशासन ने अमल करने की जगह उनकी काट के रास्ते तलाशने शुरू कर दिए. क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय है ही नहीं कि वो अपने दिए फैसलों के ऊपर अमल करवाने के तरीकों का विश्लेषण कर सके.

भारत के राजनीतिक ताने-बाने के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि न्याय कैसे सस्ता हो, इसका वो रास्ता तलाशें. सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि न्याय कैसे सस्ता हो, वो भी इसके रास्ते सुझाए. लेकिन आजादी के बाद से अबतक इसे लेकर कोई कोशिश नहीं हुई. देश में सबको मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको मुकदमा लड़ना है, तो अब वहां ऐसे वकील हैं जो जज साहब के सामने जाने के लिए पेशी के लिए 40-40 लाख रुपए ले लेते हैं. वो एकाउंटेड मनी होती है या अनएकाउंटेड होती है प्रश्न ये नहीं है? प्रश्न ये है कि वो इतने महंगे वकील हैं और अगर वो न्यायालय में न खड़े हों, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ध्यान ही नहीं देते हैं. इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों की आखिरी आशा है. लोग अपना घर, संपत्ति, गहने बेचकर भी सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय की आशा में जाते हैं. जब वो हार कर या जीतकर लौटते हैं तो उनके साथ सच्चाई तो होती है, लेकिन वो अपना सबकुछ खो चुके होते हैं. और यहां पर उनका दुख शुरू होता है कि उनके पक्ष में दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार, सरकारें या प्रशासन अमल नहीं करवा पाता है.

ये अंतर्विरोध और ये दर्द हमारी व्यवस्था का दर्द है. जो काम सरकारों को करना चाहिए, वो काम भी अब सुप्रीम कोर्ट करने लगा है. और जब मैं सुप्रीम कोर्ट कहता हूं तो आप ये मान लीजिए कि हम पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं. हाई कोर्ट फैसले दे देते हैं, लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के साधन नहीं होते, राजनीतिक लोग न्यायपालिका का इस्तेमाल अपने हित में करते हैं, जैसा कि अभी गुजरात की एक अदालत ने कहा कि मशहूर जय शाह केस की रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं हो सकती, न इलेक्ट्रॉनिक में और न प्रिंट में. वो कौन सा ऐसा मामला है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन अदालत ने फैसला दे दिया. हाई कोर्ट को उसे निरस्त करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट खामोश है. तो क्या हम ये मानें कि फैसले भी दोस्तियों के ऊपर होते हैं या राजनीतिक प्रभाव में होते हैं. शायद ये सच्चाई नहीं हो, लेकिन लोगों को तो ऐसा ही दिखाई देता है.

इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसलों के ऊपर अमल करवाना चाहता है, तो उसे सरकार और राज-नेताओं से 10 हाथ दूर रहना चाहिए. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका के शीर्षस्थ व्यक्ति यानि जज, वे लोग निष्पक्ष रहें और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर संविधान के अनुसार फैसले दें. इससे उनकी साख भी बढ़ेगी और वो सरकारों और प्रशासन से फैसले पर अमल नहीं होने के सवाल भी पूछ सकेंगे. हमारी आखिरी आशा अभी भी न्यायपालिका ही है, खासकर सर्वोच्च न्यायालय.■

editor@chauthiduniya.com

आजकल भारत में जो हो रहा है, वह ढर्रा पाकिस्तान का है

एस. इरफ़ान हबीब

ऐसी पीढ़ी तैयार करने की कोशिश हो रही है, जो नफ़रत पर आधारित हो. पहले इतिहास में दुश्मन पैदा करें, फिर उससे लड़ें. ऐसे इतिहास का असर हम पाकिस्तान को देखकर समझ सकते हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एजेंडा है, जो आजादी के बहुत पहले से चल रहा है. वे मिथ और इतिहास को मिला देते हैं. इसी वजह से वे इतिहास को नए सिरे से लिखने की बात करते हैं, क्योंकि आप अंतर ही खत्म कर दीजिए कि इतिहास और मिथ क्या है? इसके बाद इतिहास को जैसे आप चाहेंगे, वैसे लिखेंगे. यह पुराना एजेंडा है, जिसे संघ के लोग समय-समय पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. आप 1925 से अब तक देखिए, संघ ने हमेशा यह बताने की कोशिश की है कि देश में एक बहुसंख्यकवादी सोच है. एक राष्ट्रवाद ऐसा होता है, जो समावेशी होता है, जिसमें आप सबको जोड़कर रखते हैं. दूसरा राष्ट्रवाद वह होता है जिसमें आप पहले दुश्मन की पहचान करके यह बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं.

एक सांप्रदायिकता वह है, जो राष्ट्रवाद हो जाती है, एक सांप्रदायिकता अलगाववाद हो जाती है यानी एंटी-नेशनल. हैं दोनों ही सांप्रदायिकता. आजकल जो एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, खास तौर से जिसे सरकार का खास सहयोग है, ऐसी बातों से दक्षिणपंथी खेमे को मदद मिलती है. उस विचारधारा का जो पूरा एजेंडा है, एक खास तरह की सोच है, उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. बात यह है कि नेशनल और एंटी-नेशनल की स्थिति को लेकर जैसा इतिहास आप पढ़ाना चाहते हैं, वह तर्कसंगत नहीं है. मध्यकालीन और प्राचीन भारत में हीरो ढूंढने की कोशिश बहुत ही असंगत है, क्योंकि उस वक्त के हीरो एक बोझ के साथ आते हैं. उस कालखंड का बोझ, उस कालखंड की सोच. चाहे वह प्राचीन भारत हो, चाहे वह मध्यकालीन भारत हो.

कोशिश यह होनी चाहिए कि इतिहास से हीरो लाने के बजाय उससे कुछ सबक सीखने की कोशिश करें. उनकी बुराइयों से बचें. एक नायक आप ढूंढते हैं, तो उसमें बुराई तो दिखाई नहीं देती. वह तो हीरो हो गया. उसमें बुराई तो हो ही नहीं सकती. यह इतिहास का सही सबक नहीं है. इतिहास के बारे में कहा जाता है कि उससे सबक लेना चाहिए. जो इतिहास में अच्छा नहीं था, उससे बचिए, तभी तो सबक हुआ. आपने आंख बंद करके सब कुछ अपना लिया, तो फिर सबक कहां हुआ? आपने तो कुछ सीखा ही

नहीं. आज इतिहास की बात बार-बार होती है, वह यही है कि आप उस इतिहास को आंख बंद करके अपनाएं, जो आज आपको सूट करता है. वह इतिहास आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. यह ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं बन सकते. संघ का राष्ट्रवाद भी धर्म पर आधारित है जिसमें पुण्यभूमि और पितृभूमि का मुद्दा उठाया जाता है. पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था. उनका राष्ट्रवाद भी धर्म के नाम पर था, लेकिन 1971 में क्या हुआ? जो मुस्लिम राष्ट्रवाद था, जिसके नाम पर द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर पाकिस्तान बना, उसको भाषा और संस्कृति ने तोड़ दिया. धर्म तो दोनों का एक था, जिसके आधार पर वे अलग हुए थे, लेकिन वह नहीं चल पाया.

राष्ट्रवाद धर्म के आधार पर नहीं चलने वाला है. दुनिया में कहीं नहीं चल पाया है. यह भी इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत का निर्माण सिर्फ धर्म के नाम पर या एक बहुसंख्यक संस्कृति के नाम पर नहीं हो सकता. एक बहुसंख्यक संस्कृति या विचार आप सब पर थोप दें, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तब सबकल्चर, सबनेशनलिज्म सिर उठाते हैं. हमारे मुल्क में सिर्फ कुछ लोग ऐसी सोच वाले हैं, जो अपनी राजनीति के लिए अनाप-शनाप बातें बोलते हैं. जानते वे भी हैं कि वे गलत बोल रहे हैं. ये चीजें सिर्फ राजनीति के लिए की जाती हैं. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गंभीरता है और जो बोल रहा है, वह भी इसको गंभीरता से नहीं लेता है. इतिहास से सबक लेना है तो आप इतिहास से वर्तमान सुधारने के लिए और भविष्य बनाने के लिए सबक लीजिए. अगर आप इतिहास में रहना चाहते हैं, तो यह अलग बात है. इतिहास से बाहर निकलकर उससे सबक सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन दुख की बात है कि हम ऐसा नहीं करते.

> नई सरकार आने के बाद इतिहास और शिक्षा को लेकर जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, उसका आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. यह सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है. आपको कम से कम अपने पड़ोसी से सबक लेना चाहिए. जिसको आप बुरा कह रहे हैं, उसी तरह का काम खुद नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान को देखिए, वे किस तरह का इतिहास पढ़ा रहे हैं.

नई सरकार आने के बाद इतिहास और शिक्षा को लेकर जिस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, उसका आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. यह सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है. आपको कम से कम अपने पड़ोसी से सबक लेना चाहिए. जिसको आप बुरा कह रहे हैं, उसी तरह का काम खुद नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान को देखिए, वे किस तरह का इतिहास पढ़ा रहे हैं. उदाहरण के लिए, उन्होंने इतिहास के साथ क्या किया? उनका इतिहास शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम से, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उन्हीं के यहां हैं, लेकिन उनके इतिहास में उस पर बात नहीं होती. वह उनकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा नहीं है. पूरे इतिहास में जितने चरित्र हैं, उनको निकालकर इतिहास का इस्लामीकरण कर दिया, उसे अपने हिसाब से पवित्र कर दिया. अब उनके इतिहास में सारे चरित्र मुसलमान हैं, सारे मुहे इस्लामी मुहे हैं. इस तरह का समाज उन्होंने अपने यहां अपनी किताबों में पैदा किया. वही अपने बच्चों के सामने पेश किया.

पहले आप इतिहास में एक दुश्मन पैदा करें, फिर उससे लड़ें कि इतिहास में इन्होंने हमारे साथ क्या-क्या किया? इसके लिए मुसलमान और ईसाई दोनों को दुश्मन बनाया जा सकता है. इस तरह के इतिहास का आने वाले समय में कितना बुरा असर होगा, यह हम पाकिस्तान को देखकर समझ सकते हैं. अगर हम नहीं समझते तो यह हमारा दुर्भाग्य है. लेकिन हमारे यहां जो हो रहा है, वह पूरी तरह उन्हीं का ढर्रा है. हालांकि, हमारी समझ यह है कि इस अभियान का असर व्यापक हिंदुस्तान पर नहीं होगा. लेकिन जितने पर होगा, वहां पर खतरा बना रहेगा.■

(लेखक इतिहासकार हैं. साभार: द वायर)

feedback@chauthiduniya.com

रेल मंत्रालय कर रहा है उत्तर प्रदेश की उपेक्षा, यूपी सरकार पर असर नहीं

पत्ता भी नहीं हिला पा रही सत्ता

> एक अक्टूबर 2014 को गोरखपुर के नंदानगर में कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस की टक्कर में 14 लोगों की मौत हुई थी. 31 मई 2012 को हावड़ा से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी. 20 मार्च 2012 को हाथरस में रेल क्रॉसिंग पर वाहन और ट्रेन की टक्कर में 15 लोगों की मौत हुई थी. 10 जुलाई 2011 को फतेहपुर के पास कालका एक्सप्रेस हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई थी.

सूफी यायावर

पिछले सात साल में उत्तर प्रदेश में रेल हादसों की 10 घटनाएं दर्ज हुईं, लेकिन यूपी के रेल हादसों की आधिकारिक जांच का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. इसका हिसाब-किताब मांगने में उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई रुचि नहीं दिखाती. रेल हादसों के मामले लीपपोत कर किनारे रख दिए जाते हैं. कुछ मामूली कर्मचारियों पर कार्रवाई की औपचारिकता होती है, लेकिन बड़ा अधिकारी बेदाग बचा रहता है. जैसे सारी गलतियां छोटे कर्मचारी ही करते हैं, बड़े अधिकारियों से कोई गलती ही नहीं होती. एक जनवरी 2010 से 2017 (खबर लिखे जाने तक) पश्चिम रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे और पश्चिम मध्य रेल के तीन रेलवे जोन में जो रेल हादसे हुए, उनकी जांच के लिए 111 जांच समितियां बनाई गईं. लेकिन इसी दरम्यान उत्तर प्रदेश में जो 10 रेल हादसे हुए उनकी जांच का क्या हुआ, इसका कोई अता-पता नहीं है.

सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर को रेल महकमे ने जानकारी दी कि 111 जांच समितियों में 51 जांच समितियां पश्चिम रेलवे मुंबई, 37 जांच समितियां पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर और 23 जांच समितियां पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में काम कर रही हैं. पश्चिम रेलवे में 24 दुर्घटनाएं लापरवाह ड्राइविंग से हुईं, जबकि तीन मामलों में आपराधिक षड्यंत्र सामने आया. एक मामले में बादल गिरने से घटना घटी. पांच मामलों में कुल सात रेलकर्मी बर्खास्त किए गए और दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई. शेष 16 मामलों में दोषी पाए गए लोगों को लघु दंड दिया गया. पूर्वी तटीय रेल में 19 मामलों में कोई रेलकर्मी दोषी नहीं पाया गया. दो मामलों में आरोप वापस ले लिए गए. एक मामले में परामर्श दिया गया, जबकि दो मामलों में तीन रेलकर्मी बर्खास्त किए गए. कुनेरू (आंध्र प्रदेश) में हीरानंद एक्सप्रेस की दुर्घटना की एनआईए जांच कर रही है.

पश्चिम मध्य रेलवे में दो मामलों में बर्खास्तगी सहित 13 मामलों में विभिन्न दंड दिए गए जबकि 10 मामलों में रेलकर्मी दोषी नहीं पाए गए. गुर्रा स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अधजली सिगरेट को वेंटिलेटर में ठूंसने से आग लगने की घटना सामने आई. तीन मामलों में ड्राइविंग की लापरवाही और एक मामले में जानवर के पटरी पर आ जाने से दुर्घटना हुई. यह तथ्य तो बाहरी राज्यों के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले सात वर्षों में जो दस रेल हादसे हुए उनकी जांचों का क्या हुआ, उसका कोई अता-पता नहीं है. आप याद करते चलें कि अभी हाल ही 23 अगस्त 2017 को औरैया में कैफियत एक्सप्रेस के 10 कोच दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे. उसके पांच ही दिन पहले 19 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर के पास हुए कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे. 25 जुलाई 2016 को भदोही रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर में 10 बच्चों की दुखद मौत हो गई थी. 20 मार्च 2015 को रायबरेली में बछरावां के पास वाराणसी एक्सप्रेस हादसे में 32 लोगों की मौत हुई थी. एक अक्टूबर 2014 को गोरखपुर के नंदानगर में कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस की टक्कर में 14 लोगों की मौत हुई थी. 31 मई 2012 को हावड़ा से देहरादून जाने वाली दून एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी. 20 मार्च 2012 को हाथरस में रेल क्रॉसिंग पर वाहन और ट्रेन की टक्कर में 15 लोगों की मौत हुई थी. 10 जुलाई 2011 को फतेहपुर के पास कालका एक्सप्रेस हादसे में 69 लोगों की मौत हो गई थी. 7 जुलाई 2011 को रेल क्रॉसिंग पर बस की ट्रेन से टक्कर में आठ की मौत हुई और 16 जनवरी 2010 को श्रम शक्ति एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच टुंडला में हुई टक्कर में छह लोग मारे गए थे.

यह तो यूपी में हुए कुछ रेल हादसों का आंकड़ा है. लेकिन इन हादसों के जिम्मेदार कौन हैं? जांचों का क्या हुआ? जांच हुई भी कि नहीं? इन सवालों का कोई जवाब सामने नहीं है. राज्य सरकार भी केंद्र से इन मामलों पर कोई जानकारी हासिल करने की जहमत नहीं उठाती. नेताओं को देखिए तो हर कोई मुंह उठाए रेल यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा पर बड़ी-बड़ी बातें कहता हुआ नजर आता है. जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है, तो नेता कुछ अधिक ही शोर करते हैं. मीडिया भी राग हुआं-हुआं गाता है और फिर दूसरे राग में लग जाता है, रेल महकमा उच्च स्तरीय जांच की 'बतोलेबाजी' करता है और फिर लीपापोती में लग जाता है. दुर्घटनाओं के बारे में जांच समितियों की रिपोर्ट क्या आई, किसी को पता ही नहीं चलता. रेल मंत्रालय ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखता. यह जनोन्मुखी लोकतंत्र के एक मंत्रालय का हाल है, जिसकी कमाई ही आम लोगों की जेब से होती है. विशेषज्ञ कहते हैं कि रेल बजट को आम बजट में विलय कर देने से रेल मंत्रालय का दायित्व-बोध समाप्त हो गया. अब केवल औपचारिकताएं हो रही हैं. केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की सियासत करती है, लेकिन जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, वे ही ठीक से चलें, समय से चलें और सुरक्षित चलें, इसकी कोई फिक्र नहीं है. आज अधिकांश ट्रेनें लेट से चल रही हैं, लेकिन इसका कोई नैतिक दायित्व लेने को तैयार नहीं है. उत्तर प्रदेश के रेल हादसों पर रेल मंत्रालय का संवेदनहीन रुख यह बताने के लिए काफी है कि रेल मंत्रालय को आम आदमी से केवल पैसे वसूलना आता है. हादसों की भरपाई के लिए मुआवजों का खेल खेला जाता है, लेकिन भुक्तभोगी तक मुआवजे की रकम भी नहीं पहुंच पाती. कोई इसकी खोज-खबर नहीं लेता. मीडिया को भी इससे कोई लेना-देना नहीं रहता.

आज भारतीय रेल की छवि जिस तरह की बन गई है, इसे लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है. हम सामान्य गति की ट्रेनें ही ठीक से नहीं चला पा रहे और लोगों को बुलेट ट्रेन का सियासी-सपना दिखाते हैं. हकीकत और सपने में बड़ा नारकीय फर्क है. बुलेट ट्रेन की जगह आम जनता के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है. रेल यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के बावजूद कोई नई ट्रेनें नहीं चलाई जा रहीं. भीड़ जर्जर पुल से गिर कर मरती है तो मरती रहे. विशेषज्ञ लगातार झींक रहे हैं कि बढ़ते रेल हादसे गंभीर चिंता का विषय हैं. औसतन सात में से छह दुर्घटनाएं मानवीय भूल और लचर व्यवस्था के कारण हो रही हैं. लेकिन रेल प्रबंधन इन पर नियंत्रण करने में फेल है. रेल का बड़ा अधिकारी रेल संरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त है और खामियाजा छोटा कर्मचारी भुगतता है. एक सांसद ने कटाक्ष किया कि रेलवे में शक्तियां बिना किसी जिम्मेदारी के दी जाती हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को कोई शक्ति नहीं दी जाती. गैरजिम्मेदार रेल महकमे ने अपने तकनीकि-विशेषज्ञों का विकास रोक दिया है. भारतीय रेल दूसरे देशों से तकनीक आयात के भरोसे पर चल रही है. हम जापान से बुलेट ट्रेन का आयात कर रहे हैं जबकि जापान में रेल की शुरुआत भारत के बाद हुई थी. भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हुई और जापान में 1872 में. लेकिन जापान ने 1964 में बुलेट ट्रेन बना ली, हम आज तक बुलेट ट्रेन का सपना ही देखते रहे और सियासत की दुकान चमकाने के लिए उसकी तकनीक अत्यंत महंगे खर्च पर खरीद रहे हैं.

रेलवे में यात्रियों का सुरक्षा को लेकर रेल प्रबंधन और सरकार कितनी गंभीर है, इसे आपने देखा. रेल में अपराध भी बेतहाशा बढ़ा है और पुलिस की व्यवस्था पूरी तरह नाकारा साबित हो रही है. चोरी लूटपाट से लेकर ट्रेन में बलात्कार और ट्रेन से बाहर फेंक देने की घटनाएं लोग लगातार भुगत रहे हैं. यात्रियों की अन्य सुविधाएं और खान-पान की स्थिति तो और भी विचित्र है. आए दिन खाने के सामान में कीड़े, तेलचट्टे छिपकलियां निकलती हैं. तेजस जैसी ट्रेन में 60 से अधिक यात्री खाना खाकर बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. ऐसी जानलेवा हरकतों पर भी रेल प्रबंधन का बयान सुनें, तो उससे नेताओं को भी शर्म आने लगेगी. रेलवे की गलीज खान-पान व्यवस्था को लेकर महालेखाकार (कैग) भी गंभीर आपत्तियां दर्ज कर चुका है, लेकिन किसकी खाल पर असर पड़ता है!

कैग भी यह कह चुका है कि रेल में मिलने वाला खाना इंसान के खाने के लायक नहीं है. विडंबना यह है कि कैग की यह रिपोर्ट संसद में भी रखी जा चुकी है, लेकिन संसद पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा. बस, संसद का खाना दुरुस्त रहना चाहिए. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों पर जो खाने-पीने की चीजें परोसी जा रही हैं, वो इंसानों के इस्तेमाल के लायक नहीं हैं. डिब्बाबंद और बोतलबंद चीजों को एक्सपायरी डेट के बावजूद बेचा जा रहा है. दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में खाने में चूहे और तेलचट्टे विचरण करते नजर आते हैं. यात्री कटलेट ऑर्डर करता है, तो उसे लोहे की कीलें कटलेट में परोसी जाती हैं. ट्रेनों में कैटरिंग स्टाफ का सफाई से कोई लेनादेना नहीं रहता. कैग और रेलवे की साझा टीम ने देश के 74 विभिन्न स्टेशनों और 80 ट्रेनों का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट तैयार की थी. ■

जब एमपी थे तो बोले, जब सीएम हैं तो चुप

योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. वे जब गोरखपुर के सांसद थे तो रेलवे को लेकर संसद में तमाम सवाल उठाते रहते थे. आज जब वे मुख्यमंत्री हो चुके हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, तब भी वे अपने ही उठाए हुए मसलों का 'फॉलोअप' करने में कोई रुचि क्यों नहीं लेते, यह सवाल सामने है. इन्हीं स्थितियों में आम नागरिक यह समझने पर विवश होता है कि विधानसभाओं या संसद में सवाल उठाना नेताओं की केवल सियासी नौटंकी होती है, क्योंकि सत्ता में आने पर उन्हीं सवालों को वह भूल जाता है और फिर सत्ता से बाहर होने पर उन्हीं सवालों को फिर से उठाने लगता है. सारे नेताओं की दुकानदारी इन्हीं नौटंकियों पर चलती रहती है. यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सांसद थे, तब उन्होंने प्रदेश में रेल सुविधाओं को लेकर क्या-क्या सवाल उठाए थे, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं. आप यकीन मानिए कि उन सवालों को लेकर योगी ने कोई 'फॉलोअप' नहीं किया और उन सवालों को कारगर कराने में न उनकी कोई दिलचस्पी ही है.

योगी ने संसद में कहा था कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म, बाहरी स्थलों और रेलगाड़ियों की स्थिति ठीक नहीं है. रेलवे जंक्शनों पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय नहीं हैं. इन सभी समस्याओं के समाधान का कोई उपाय प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जा रहा है. रेलवे अस्पतालों की स्थिति अत्यंत खराब है. गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पटरी व्यवसायियों ने ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाकर न केवल यातायात को बाधित कर रखा है, बल्कि रेलवे स्टेशन की शोभा को भी आच्छादित कर रखा है. रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर अपार गंदगी का साम्राज्य है. इसके अलावा योगी ने गोरखपुर-नई दिल्ली के बीच तेजस रेलगाड़ी का संचालन करने की मांग की थी. योगी ने कहा था कि गोरखपुर-कोलकाता के बीच हमसफर रेलगाड़ी का संचालन किए जाने की आवश्यकता है. साथ-साथ उन्होंने कहा था कि गोरखपुर-इलाहाबाद के बीच एक उदय रेलगाड़ी का भी संचालन होना चाहिए. गोरखपुर-हरिद्वार के बीच चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस नियमित होनी चाहिए और गोरखपुर-लखनऊ रेलखंड के बीच गोरखपुर में सूरजकुंड और सहजनवां में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का निर्माण तत्काल प्रभाव से होना चाहिए. योगी ने पिपराइच, पीपीगंज और कैम्पियरगंज कस्बे में रेलवे समपार फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण तत्काल प्रभाव से कराने पर जोर दिया था और कहा था कि पिपराइच, पीपीगंज, सहजनवां डोमनीगढ़ और कैम्पियरगंज रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख यात्री गाड़ियों का ठहराव होना जरूरी है. इन सभी स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों को अपग्रेड करने पर भी योगी लगातार जोर दे रहे थे. योगी ने कहा था कि पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकतर समपार फाटकों पर रेलवे की भूमि पर स्थित मार्ग अत्यंत खराब हैं, इनका प्राथमिकता के आधार पर नवनिर्माण किया जाना चाहिए. लेकिन संसद में उठाई गई इन मांगों का क्या हुआ, योगी ने इस तरफ फिर कोई सुध नहीं ली. ■

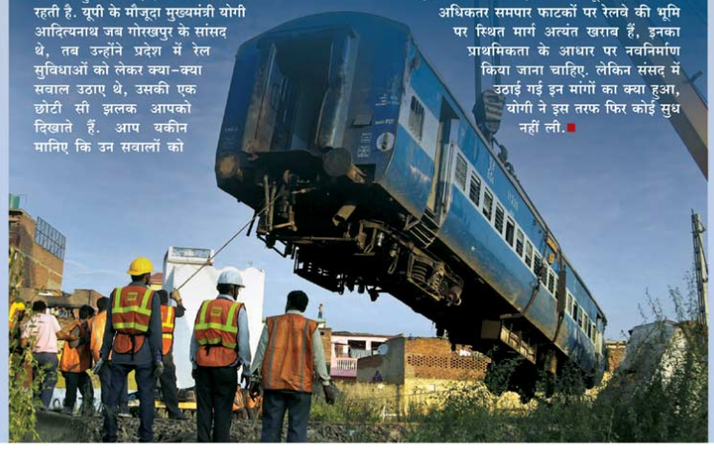

पुत्र-धर्म की आख़िरी मर्यादा भी भूल गए अखिलेश

मुलायम सपा के संरक्षक भी नहीं

रामगोपाल यादव ने ख़ुद को तरक़्क़ी देकर जारी कर दी कार्यकारिणी की लिस्ट | अलग सियासी रास्ते पर चलने के अलावा शिवपाल के पास कोई विकल्प नहीं | बड़े-बड़े घट कर रह गए सदस्य, चाटुकार खड़े-खड़े बन गए पार्टी पदाधिकारी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं होने के बारे में पूछने पर पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि सपा के संविधान में संरक्षक के पद का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह साफ कर दिया कि शिवपाल यादव को अपना अलग रास्ता चुनना ही होगा. शिवपाल उम्मीद लगाए बैठे थे कि अखिलेश आख़िरी समय में भी चाचा का ख्याल रखेंगे. इसी उम्मीद से उन्होंने अखिलेश को अग्रिम बधाई भी दी थी, लेकिन शिवपाल की सारी उम्मीदें धराशाई हो गईं.

प्रभात रंजन दीन

अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ कलयुगी पुत्र-धर्म का निर्वहन किया और रामगोपाल यादव ने कलयुगी भ्रातृ-धर्म का. लक्ष्मण जैसा भाई होने का दावा करने वाले शिवपाल यादव से धोखा कर मुलायम ने अखिलेश को उत्तराधिकार सौंपने के लिए जिस तरह का बेमानी तिकड़म किया, उसका सटीक उपहार अखिलेश और रामगोपाल ने उन्हें समाजवादी पार्टी के शामियाने से बाहर का रास्ता दिखा कर दे दिया. नरेंद्र मोदी में तो फिर भी आंख की लाज बची थी कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को भाजपा का संरक्षक घोषित कर उनका सम्मान रखा. लेकिन अखिलेश ने तो उतनी भी मर्यादा का पालन नहीं किया. अखिलेश की अध्यक्षता वाली समाजवादी पार्टी में शिवपाल को कोई जगह नहीं दी जाएगी, यह शिवपाल को छोड़ कर सबको पता था, लेकिन मुलायम को भी दूध की मक्खी बना दिया जाएगा, सियासत के इतने स्खलित होने के बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी. अब पार्टी पूरी तरह रामगोपाल यादव की मुट्ठी में है. अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मुगालता पाले रहें. आगरा सम्मेलन के बाद लोगों को दीपावली का इंतजार था. ऐसे संकेत मिले थे कि मुलायम कुछ बोलेंगे, लेकिन चालाक रामगोपाल ने उसके पहले ही कार्यकारिणी की लिस्ट जारी कर दी. अपने ही हस्ताक्षर से जारी लिस्ट में रामगोपाल ने अपनी तरक्की भी कर ली और खुद को पार्टी का प्रमुख महासचिव घोषित कर दिया. रामगोपाल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने चट्टे-बट्टे सारे इकट्ठे कर लिए. अपने नौसिखिए बेटे अक्षय यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य की हैसियत दे दी, लेकिन बदायूं से लगातार सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को कार्यकारिणी का सदस्य भी नहीं बनाया. रामगोपाल ने अपने खास लोगों को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाया और अखिलेश के खास लोगों को सदस्य-दीर्घा में रख दिया. अखिलेश-रामगोपाल ने सामाजिक नैतिकता को भी ताक पर रख कर जावेद आब्दी जैसे लोगों को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर दिया. आब्दी कुछ ही अर्सा पहले दिल्ली में वेश्यावृत्ति के इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े सरगना से नजदीकी सम्बन्धों के कारण सुर्खियों में आए थे.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट देखें, तो आपको रामगोपाल के निहित इरादे समझ में आएंगे. जया बच्चन, अहमद हसन, रामगोविंद चौधरी, अबु आसिम आजमी, चन्द्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खां, नीरज शेखर, एसआरएस यादव, अरविंद कुमार सिंह, राम आसरे विश्वकर्मा, ऊषा वर्मा, जूही सिंह, रामहरी चौहान, रमदुलार राजभर, विनोद सविता, डॉ. लाखन सिंह पाल, डॉ. सुदीप रंजन सेन, अरुण दुबे, राजीव राय, संतोष द्विवेदी, जगदीप सिंह यादव, अविनाश कुशवाहा, उज्ज्वल रमण सिंह, संजय लाठर और राजपाल कश्यप सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं. जबकि जॉय एंटोनी, रामपूजन पटेल, डॉ. मधु गुप्ता, कमाल अख्तर, अभिषेक मिश्र, राजेन्द्र चौधरी, रमेश प्रजापति, पीएन चौहान, अरुणा कोरी और जावेद आब्दी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. राष्ट्रीय महासचिव के पद पर आजम खान, नरेश अग्रवाल, रविप्रकाश वर्मा, सुरेन्द्र नागर, बलराम यादव, विशंभर प्रसाद निषाद, अवधेश प्रसाद, बसपा से आए इंद्रजीत सरोज, रामजीलाल सुमन और रमाशंकर विद्यार्थी राजभर को मनोनीत किया गया है. किरनमय नंदा को फिर से उपाध्यक्ष और धन्नासेठ संजय सेठ को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मऊ के अल्ताफ अंसारी, देवरिया के किसान सिंह सैंथवार, सोनभद्र के व्यास गौंड, फिरोजाबाद के अक्षय यादव (रामगोपाल के पुत्र), लखनऊ के मो. इकबाल कादरी और आगरा के शिव कुमार राठौर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इस तरह पार्टी में अब एक उपाध्यक्ष, एक प्रमुख महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, 10 महासचिव, 10 सचिव, 25 कार्यकारिणी-सदस्य और छह विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.

विधानसभा में विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अहमद हसन की हैसियत राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य होने की है. राष्ट्रीय सचिवों की लिस्ट देखें, तो वरिष्ठता और अनुभव किस प्राथमिकता पर आते हैं, पता चल जाएगा. सपा सरकार के पूरे कार्यकाल में अखिलेश और मुलायम का जाप करते रहे अरविंद सिंह गोप को अखिलेश ने महज इसलिए ढक्कन कर दिया कि गोप ने मुलायम का नाम क्यों लिया! अखिलेश के मुख्यमंत्रित्वकाल में अरविंद सिंह गोप काफी ताकतवर रहे, लेकिन अचानक उन्हें काट कर छोटा कर दिया गया. आगरा राष्ट्रीय अधिवेश के पहले जो प्रदेश संगठन का गठन हुआ उसमें भी गोप का नाम नदारद था. पार्टी नेताओं को लगा कि गोप का नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आ सकता है, लेकिन वहां से भी गोप का नाम गोल कर दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष बने नरेश उत्तम पटेल ने जो 70 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की थी, उसमें 23 सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 46 सदस्य शामिल किए गए, लेकिन गोप को कहीं जगह नहीं मिली. गाजीपुर के अरविंद कुमार सिंह को प्रदेश में भी सचिव बनाया गया और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य बनाया गया. इसी तरह उज्ज्वल रमण सिंह, रामहरी चौहान, रामदुलार राजभर, लाखन सिंह पाल, डॉ. राजपाल कश्यप प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्हें जगह दी गई है. लेकिन अरविंद सिंह गोप के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं होने के बारे में पूछने पर पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि सपा के संविधान में संरक्षक के पद का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह साफ कर दिया कि शिवपाल यादव को अपना अलग रास्ता चुनना ही होगा. शिवपाल उम्मीद लगाए बैठे थे कि अखिलेश आख़िरी समय में भी चाचा का ख्याल रखेंगे. इसी उम्मीद से उन्होंने अखिलेश को अग्रिम बधाई भी दी थी, लेकिन शिवपाल की सारी उम्मीदें धराशाई हो गईं. प्रदेश की कार्यकारिणी पहले ही गठित हो चुकी है और नरेश उत्तम पांच साल के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं. शिवपाल राष्ट्रीय महासचिव या प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत रखते हैं, लेकिन अब उसकी भी कोई संभावना नहीं रही. अब शिवपाल के पास नई पार्टी गठित करने या किसी अन्य पार्टी में शरीक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शिवपाल ने निर्णय लेने में देरी कर दी. सियासत के मैदान में अखिलेश और रामगोपाल ने मिल कर उन्हें चित कर दिया. मुलायम ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की. शिवपाल के नजदीकी कहते हैं कि शिवपाल शीघ्र ही नया धमाका करेंगे, लेकिन उन्हें कोई कैसे समझाए कि धमाके का भी वक्त हाथ से छूटता जा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

वरिष्ठों की उपेक्षा कर क्या हासिल कर लिया अखिलेश ने

अखिलेश का मुगालता दूर नहीं हो रहा. अखिलेश को घेरे बैठे चाटुकार उन्हें जमीनी असलियत बताते भी नहीं. पिता मुलायम, चाचा शिवपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठों की उपेक्षा कर अखिलेश क्या हासिल कर लेंगे, इसका उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव परिणामों से एहसास हो जाना चाहिए था, लेकिन अखिलेश की दृष्टि अभी भी वास्तविकताओं की तरफ नहीं जा पा रही. पिता मुलायम की उपेक्षा किए जाने की हरकत से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का परंपरावादी मध्य वर्गीय नागरिक समुदाय दुखी और नाराज हुआ. इसका नतीजा अखिलेश को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, लेकिन उनमें फिर भी कोई समझ नहीं आ रही. समाजवादी परिवार से जुड़े एक नजदीकी ने कहा कि अखिलेश सियासी फायदे के लिए मुलायम की उपेक्षा कर रहे हैं या मुलायम के किसी अंदरूनी व्यवहार से दुखी होकर अखिलेश ने ऐसा कठोर कदम उठाया, इसे गहराई से समझना पड़ेगा. समाजवादी परिवार के उस खास व्यक्ति के इस वक्तव्य में काफी दम है. लेकिन जहां तक सियासी भविष्य का ताल्लुक है, विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश को पार्टी के वरिष्ठों का सम्मान स्थापित रखने की दिशा में आगे बढ़ कर काम करना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाए. उन्हीं विश्लेषकों का कहना है कि लेकिन अखिलेश यादव इस बारे में सोचे बगैर पार्टी का लगातार नुकसान किए चले जा रहे हैं. ताजा गतिविधियों के कारण तो आम लोगों की नजर में पार्टी और भी रसातल में चली गई. पिता-पुत्र विवाद के अलावा अखिलेश ने कई ऐसे राजनीतिक फैसले भी लिए, जिसने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया. राजनीतिक विशेषज्ञ यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ होता तो सपा अपेक्षाकृत अधिक सीटें जीतती. आम नागरिक कहते हैं कि अखिलेश के विकास के सियासी-नारे को जनता ने इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि अखिलेश ने पारिवारिक मर्यादा के तकाजे को खारिज करने का काम किया. अखिलेश को यह गलतफहमी थी कि उनके नाम और चेहरे पर वे चुनाव में बाजी मार लेंगे, इसी इरादे से उन्होंने अपने पिता मुलायम का चेहरा साइड-लाइन कर दिया, इस पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने उन्हें ही साइड-लाइन कर दिया. अखिलेश यादव ने न खुद को आम लोगों से जोड़ा और न पार्टी की ऐसी छवि गढ़ी. उल्टे उन्होंने जनता में यह संदेश दिया कि पार्टी की स्थापना करने वाले मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की भी ऐसी-तैसी की जा सकती है. दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल ने मिल कर जनता के सामने राजा और प्रजा की साफ-साफ विभाजक रेखा खींच कर दिखाने की सार्वजनिक कोशिश की. अखिलेश जितना ही राजा बनने की कोशिश करते रहे, जनता उन्हें उतना ही जमीन की धूल मिट्टी चटाने में जुटी रही.■

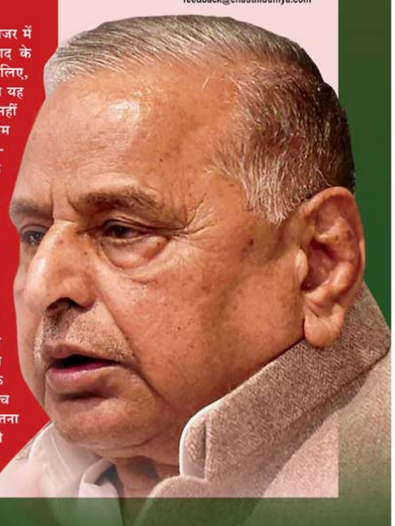

कर्मचारियों की कमी लगा रही स्मार्ट सिटी के सपने में पलीता

कहीं अधूरा न रह जाए सुंदर शहर का सपना

बेगूसराय

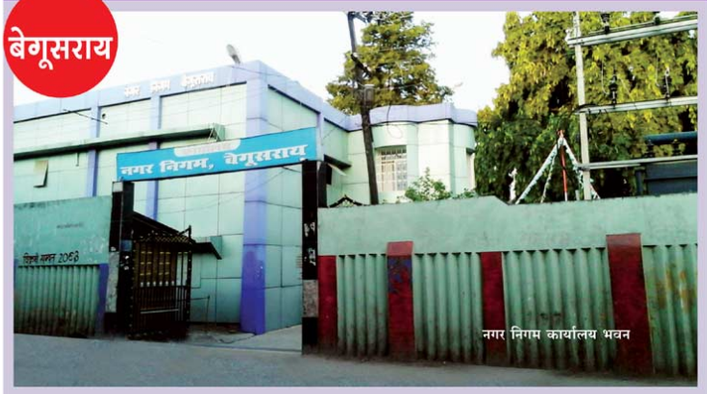

सुरेश चौहान

एक ओर केन्द्र सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर बिहार में इसकी गति धीमी दिखाई पड़ रही है. सरकार की नीतियों का अनुपालन सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है. प्रदेश के नगर निगम में नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, सफाईकर्मी, लिपिक, बिजली मिस्त्री, अभियन्ता, चालक, ऑपरेटर सहित कई महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं. एक ही पदाधिकारी को दो-तीन विभागों का प्रभारी बनाया गया है. फलतः किसी भी विभाग का कार्य गुणवत्तापूर्ण सुचारू रूप से स-समय सम्पन्न नहीं हो पाता है. इसका खामियाजा निकायों के प्रमुख को भुगतना पड़ता है.

पूर्णकालिक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सीटी मैनेजर और अभियंता के अभाव में बस स्टैंड, स्ट्रीट लाईट आदि पर नगर निगम का नियंत्रण नहीं रह पाता है. नाम मात्र के तकनीकी सेल के कारण क्वालिटी एवं क्वांटिटी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव में सौ रुपए के डस्टबिन की खरीद 800 रुपए में हुई है एवं 9000 का स्ट्रीट लाइट 34000 में खरीदा गया है.

इसकी पुष्टि के लिए प्रस्तुत है, बेगूसराय नगर निगम का लेखाजोखा. बेगूसराय नगरपालिका से नगर परिषद बना. पुनः नगर परिषद से नगर निगम बना. नगर निगम बनने से इसका क्षेत्र बढ़कर 45 वार्ड का हो गया. लेकिन नगरपालिका के समय जो स्थिति थी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ. नगरपालिका बनने पर जितने कर्मियों की नियुक्तियां हुई थी, वही संख्या नगर निगम बनने पर भी है. इस बीच जो कर्मी सेवानिवृत्त हुए उनका पद आजतक रिक्त पड़ा है. नगर निगम के महापौर उपेन्द्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि नगर निगम के सामने अनेक चुनौतियां हैं. इन चुनौतियों का सामना एवं निदान करने के लिए यहां पूर्णकालिक नगर आयुक्त नहीं हैं. नगर निगम के पास अपना अभियन्ता, जेई, लिपिक, टैक्स दारोगा, चालक आदि नहीं हैं. 1967-68 में नगरपालिका कार्यालय की जो स्थिति थी, आज तक वही है. उस समय नगरपालिका क्षेत्र की आबादी 50 हजार थी. वर्तमान में यहां 45 वार्ड में 2.75 लाख आबादी है. नगर निगम क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है पूर्णकालिक नगर आयुक्त का नहीं होना. नगर निगम बोर्ड के निर्णय को कार्यरूप देना, निगरानी एवं नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं विकास की नई योजनाओं का निर्माण आदि सारे कार्य नगर आयुक्त को ही करना होता है. लेकिन विडम्बना यह है कि जनवरी 2016 से आज तक मात्र एक पूर्णकालिक नगर आयुक्त मिले, वो भी मात्र 70 दिनों के लिए. शेष समय का कार्य उधार के पदाधिकारी (प्रभारी) से चलाया जा रहा है. जनवरी 2016 से अद्यतन तीन प्रभारी नगर आयुक्त बनाए गए. जिन्हें वित्तीय प्रभार मिलने में एक माह का समय लगा और इस बीच राशि के अभाव में विकास का कार्य अवरूद्ध रहा. वर्तमान में 25 अगस्त 2017 से डीडीसी को प्रभारी नगर आयुक्त बनाया गया है. ज्ञातव्य हो कि डीडीसी जिला परिषद के पदेन कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, साथ ही सरकारी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन इनके पास होता है. अब इन्हें नगर आयुक्त का भी प्रभार मिला है. ऐसे में डीडीसी नगर निगम के साथ कितना न्याय कर पाएंगे, इसके बारे में कल्पना की जा सकती है.

नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सिवरेज प्लान्ट, जल निकासी, कचरा प्रबंधन एवं पम्प हाउस का निर्माण. इस सम्बन्ध में महापौर उपेन्द्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि सिवरेज प्लान्ट के लिए किसानों से जमीन खरीदी गई, लेकिन क्रय मूल्य को लेकर विवाद चल रहा है. सिवरेज प्लांट के लिए शहर में तीन पम्प हाउस का निर्माण करने की योजना थी. इसके लिए नगर विकास विभाग पटना द्वारा 'ट्राइटैक' चायनीज कम्पनी को बेगूसराय भेजा गया. लेकिन वो कपनी काम शुरू करने के साथ ही यहां से चली गई. तभी से इस योजना का कार्य ठप है. जल जमाव की समस्या बनी हुई है.

उप महापौर राजीव कुमार

महापौर उपेन्द्र प्रसाद सिंह

निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप है. 75 करोड़ रुपए की लगात से पीएचईडी कैम्पस एवं हर्ख में वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट व टावर बना, जो फेल हो गया. इसके साथ ही जल निकासी, कचरा प्रबंधन आदि की व्यवस्था नहीं है. महापौर कहते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति की बात तो दूर रही, मास्टर रॉल पर भी नियुक्ति का अधिकार इन्हें नहीं है. 10 जनवरी 2017 को मुख्यमंत्री से मिलकर दिए गए पत्र में उन्होंने मांग की थी कि निगम को पूर्णकालिक नगर आयुक्त, पूर्णकालिक अपर नगर आयुक्त, दो नगर प्रबंधक, चार पूर्णकालिक अभियन्ता, पूर्णकालिक अमीन, स्थायी टैक्स दरोगा, स्थायी कार्यालीय स्टाफ, बिजली कर्मचारी, वाहन चालक आदि दिया जाय, ताकि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी एवं नियंत्रण हो सके, गड़बड़ी करने वालों के दायित्व का निर्धारण कर विभागीय कार्रवाई की जा सके, क्रय सहित अन्य कार्यों में पारदर्शिता लाया जा सके. लेकिन आज तक इस दिशा में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया.

नगर निगम के उप महापौर राजीव कुमार का कहना है कि पूर्णकालिक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सीटी मैनेजर और अभियंता के अभाव में बस स्टैंड, स्ट्रीट लाईट आदि पर नगर निगम का नियंत्रण नहीं रह पाता है. नाम मात्र के तकनीकी सेल के कारण क्वालिटी एवं क्वांटिटी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव में सौ रुपए के डस्टबिन की खरीद 800 रुपए में हुई है एवं 9000 का स्ट्रीट लाइट 34000 में खरीदा गया है. बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने उपरोक्त घोटाले सहित अन्य घोटालों की जांच कराने की मांग की, लेकिन नगर विकास विभाग इस ओर से उदासीन है. अनेक पार्षदों का कहना है कि यदि नगर निगम में व्याप्त घोटालों की सही ढंग से जांच कराई जाय, तो करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

आतंकी को पकड़ने वाले पत्रकार की मुश्किलें बढ़ीं

रोजी-रोटी पर संकट

गया

क्या यही है देशभक्ति दिखाने का परिणाम

आजकल हर बाजार, मॉल और भीड़ भरे जगहों पर पुलिस लाउड स्पीकर से मुनादी कराती है कि आपत्तिजनक वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वालों को पारितोषिक दिया जाएगा. लेकिन जब अनुराग बसु जैसे युवा देशहित ऐसे जोखिम लेते हैं, तो उन्हें ही अलग-थलग छोड़ दिया जाता है.

सुबील सौरभ

बिहार का गया शहर. दो दृश्य, लेकिन विषय एक-आतंकवाद. यहां आतंकवाद के विरोध में काम करने वाले एक जत्थे का स्वागत हो रहा है, तो दूसरे की उपेक्षा की जा रही है. यही सच है आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का. सच को सच कहने और राष्ट्रहित के लिए जान की बाजी लगाकर काम करने वाले की मदद करने से भी लोग कतरा रहे हैं. अहमदाबाद बम ब्लास्ट के आरोपी तौसीफ को पकड़ कर पुलिस के हवाले करने वाले पत्रकार और साइबर कैफे संचालक की मदद या शाबासी की बात तो छोड़िए, उल्टे उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है. 8 अक्टूबर 2017 को गया में सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकविरोधी जत्थे का जमकर स्वागत किया गया, तो वहीं 13 सितम्बर 2017 को आतंकी तौसीफ को पकड़ने वाले पत्रकार अनुराग बसु की मुश्किलें दिनों-दिनों बढ़ रही हैं. इतने बड़े आतंकी को पकड़ कर पुलिस के हवाले करने वाले को किसी तरह के सहयोग की बात तो दूर, किसी पुलिस या प्रशासन के लोगों ने उसे थैंक्स कहना भी मुनासिब नहीं समझा. कारण यह था कि आतंकी तौसीफ तथा इसके सहयोगी सन्ना खान को अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ने की बात को अनुराग बसु ने मिडिया के लोगों को बता दी, जबकि इस मामले में पुलिस खुद श्रेय लेना चाह रही थी. एफआईआर में भी पुलिस ने गुप्त सूचना पर आतंकी को पकड़ने की बात कही है. इसी बात को लेकर अंदर-ही-अंदर गया पुलिस अनुराग बसु से नाराज है कि इसने क्यों सबको सच बातें बता दी. इन दिनों आतंकवाद पर चर्चा हो रही है, तथाकथित राष्ट्रवादी नेतागण भी अपने भाषण में इस पर खूब बोल रहे हैं. लेकिन राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करने वाला संगठन आरएसएस, बजरंगदल, विश्व हिन्दू परिषद आदि के कोई भी नेता-कार्यकर्ता अनुराग बसु के साथ नहीं खड़े हैं. वोट की राजनीति करने वाले दलों और उनके नेताओं से तो कुछ उम्मीद करना भी बेकार है. समाज के लिए अच्छे काम करने वाले लोगों को समय-समय पर सम्मानित करने वाले गया शहर के तथाकथित समाजसेवी या संगठन भी न जाने एक क्यों एक युवा पत्रकार और साइबर कैफे संचालक के साहस भरे कारनामे से अनभिज्ञ हैं.

अनुराग बासु

अब तो उस युवक की रोजी-रोटी पर भी आफत आ गई है. उसके साइबर कैफे में ग्राहक भी कम आ रहे हैं और यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने भी आने से मना कर दिया है. हद स्थिति तो तब हो गई जब मकान मालिक ने वहां से साइबर कैफे हटा कर मकान खाली करने का नोटिस दे दिया. ये कितना हास्यास्पद है कि एक तरफ आतंकवाद पर भाषण देकर नेतागण नेतागीरी चमका रहे हैं और आतंकवाद की रोकथाम के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद बम ब्लास्ट के आरोपी आतंकी को पकड़ने वाले युवक के सामने अब रोजी-राटी का संकट खड़ा हो गया है. जिस काम को देश की खुफिया एजेंसिया-पुलिस नहीं कर सकी, उसे एक युवा पत्रकार ने कर दिखाया. लेकिन वाहवाही के बदले उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है. आजकल हर बाजार, मॉल और भीड़ भरे जगहों पर पुलिस लाउड स्पीकर से मुनादी कराती है कि आपत्तिजनक वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वालों को पारितोषिक दिया जाएगा. लेकिन जब अनुराग बसु जैसे युवा देशहित ऐसे जोखिम लेते हैं, तो उन्हें ही अलग-थलग छोड़ दिया जाता है. पारितोषिक तो दूर की बात, कोई उनकी सुध लेने भी नहीं जाता. ऐसा भी नहीं है कि मीडिया में इस खबर को जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी हर तरफ शांति है. अब जो स्थिति बन रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद ही कोई अब अपनी जान पर खेलकर आतंकी या आपराधिक लोगों के बारे में पुलिस को कोई सूचना देगा. ■

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम
मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....
AL अलीगढ़ लॉक्स प्रा.लि.
पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना-3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com
अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते-जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

JOHNSON PAINTS
Interior & Exterior Wall Paints
JP बड़े अच्छे लगते हैं...
PERFECT Exterior Emulsion
JOHNSON Exterior Emulsion

मोतिहारी में अपने हाल पर रो रहा रोईंग क्लब

1957 में आए नए बीडीओ पीके बनर्जी की सक्रियता से कुछ सार्थक सहयोग मिला. इसी दौरान जिले में नए डीएम के रूप में सीआर वैद्यनाथन ने कार्यभार ग्रहण किया. वैद्यनाथन कला और खेलप्रेमी थे. एक दिन प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण के दौरान उनकी नजर रोईंग क्लब में बैडमिंटन और वालीबॉल खेल रहे कुछ लोगों पर पड़ी. इन्होंने इसकी जानकारी ली, तो उन्हें रोईंग कल्ब के बारे में पता चला. उन्होंने इसके विकास का बीड़ा उठाया. डीएम सीआर वैद्यनाथन ने यहां टेबल टेनिस के लिए अपनी ओर से ग्रान्ट भी दिया.

राकेश कुमार

सियासी व सामाजिक उदासीनता किस तरह विरासत का बंटाधार करती है, इसका ताजा उदाहरण है, मोतिहारी का रोईंग कल्ब. कभी भारतीय किसानों के शोषण का केंद्र रहे निलही कोठी की जगह पर बनाया गया रोईंग क्लब आज अपने हाल पर आंसू बहा रहा है. कभी गुलजार रहने वाला रोईंग क्लब इन दिनों जुआरियों का अड्डा बना हुआ है. बिहार में शराबबंदी के पूर्व यह जगह शराबियों के लिए मुफीद स्थल हुआ करती थी. शराबबंदी के बाद अब भी यहां लोगों को छुप कर मोतीझील की सीढ़ियों पर शराब पीते देखा जा सकता है.

5 मई 1956 को रोईंग क्लब की स्थापना भवानीपुर जिरात मोतिहारी में नवसृजित प्रखंड कार्यालय के परिसर में की गई थी. तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एल एन सिंह, इनके कुछ विभागीय सहयोगियों और श्री ईश्वरी प्रसाद साहू के संयुक्त प्रयास से रोईंग क्लब स्थापित हुआ. इसके विकास कार्य चल ही रहे थे कि एल एन सिंह का चयन पुलिस विभाग में हो गया और वे नई नौकरी में चले गए. इसके साथ ही क्लब के कार्यकलापों में ठहराव सा आ गया. 1957 में आए नए बीडीओ पीके बनर्जी की सक्रियता से कुछ सार्थक सहयोग मिला. इसी दौरान जिले में नए डीएम के रूप में सीआर वैद्यनाथन ने कार्यभार ग्रहण किया. वैद्यनाथन कला और खेलप्रेमी थे. एक दिन प्रखंड कार्यालय में निरीक्षण के दौरान उनकी नजर रोईंग क्लब में बैडमिंटन और वालीबॉल खेल रहे कुछ लोगों पर पड़ी. इन्होंने इसकी जानकारी ली, तो उन्हें रोईंग कल्ब के बारे में पता चला. उन्होंने इसके विकास का बीड़ा उठाया. डीएम सीआर वैद्यनाथन ने यहां टेबल टेनिस के लिए अपनी ओर से ग्रान्ट भी दिया.

दिनोंदिन क्लब के साथ लोग जुड़ते गए और इसके क्रियाकलापों में तेजी आने लगी. इसे देखते हुए सदस्यों ने विचारोपरान्त क्लब के लिए भवन बनवाने का प्रस्ताव डीएम वैद्यनाथन के समक्ष रखा. डीएम ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मोतीझील के किनारे कोई सरकारी जमीन तलाशने को कहा. खोजबीन के उपरान्त मोतीझील के किनारे बड़े-बड़े गड्ढों से भरे एक भूखंड का चयन किया गया, जहां शहर का मैला व कचरा फेंका जाता था. वह स्थल निलही कोठी के रूप में जाना जाता था. यह वही जगह थी, जहां कभी नील तैयार की

जाती थी. बड़े-बड़े पत्थर व पक्का प्लेटफार्म निलही कोठी द्वारा चम्पारण के किसानों के शोषण की गवाही देते थे. डीएम बैद्यनाथन ने उक्त भूमि पर क्लब के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी. साथ ही भवन निर्माण के लिए पांच हजार रुपए की सरकारी राशि सहायता स्वरूप प्रदान की. 14 जनवरी 1958 को डीएम बैद्यनाथन ने रोईंग क्लब के भवन का शिलान्यास किया. सबसे बड़ी समस्या थी भूखंड के गड्ढों को भरना. इसी वर्ष प्राकृतिक आपदा से पूरा बिहार जूझ रहा था. सूखा से चारो तरफ हाहाकार मचा था. सूखा पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा काम के बदले अनाज देने की योजना लाई गई. जिलाधिकारी बैद्यनाथन के सहयोग से इसी योजना द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य पूरा कराया गया. काम के बदले अनाज योजना और पांच हजार रुपए के सरकारी सहयोग के साथ जिलावासियों से प्राप्त चन्दे की राशि से कुल 9 माह में भवन निर्माण व परिसर समतल करने का कार्य पूर्ण हुआ. इसमें कुल 9,500 रुपए की राशि व्यय हुई और इसके बाद रोईंग क्लब अपने पूर्ण अस्तित्व में आ गया. इसके बाद यहां बैडमिंटन, वालीबॉल, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस जैसे खेलों के अलावा विशेष रूप से नौकायन शुरू किया गया. प्रतिवर्ष इन खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी. यहां पर प्रखंड की ओर से एनइएस कप उच्च विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता भी कराई जाती रही. 1959 में पहली बार यहां क्लब स्तर पर क्रिकेट शुरू हुआ. रोईंग क्लब की 19 सदस्यीय क्रिकेट टीम नेपाल के निमंत्रण पर काठमांडू भी गई और विजयी होकर लौटी.

1961 में क्लब परिसर में एक औद्योगिक एवं कुटीर उद्योग पर आधारित प्रदर्शनी के आयोजन का शुभारम्भ किया गया, जो कई वर्षों तक चलता रहा. क्लब परिसर में संगीत शिक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नगर के संगीत प्रेमी बच्चे संगीत की शिक्षा लेने आते थे. संगीत शिक्षा के लिए क्लब में हारमोनियम, तबला, वायलिन, सितार आदि विभिन्न वाद्य यंत्र खरीदे गए. स्वर्गीय गजाधर प्रसाद सिंह की प्रेरणा से क्लब में गांधी स्वाध्याय केन्द्र की स्थापना हुई. जिसका उद्घाटन 30 अप्रैल 1963 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम एमएस अयंगर ने किया था. स्वाध्याय केन्द्र में गांधी जी से सम्बन्धित पुस्तकों का संग्रह किया गया था. स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्लब द्वारा कई कार्य किए गए, जिसमें मोतियाबिन्द का मुफ्त ऑपरेशन शिविर मुख्य था. समय-समय पर क्लब की ओर से देश के विशिष्ट व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता रहा. महामहिम राज्यपाल श्री अयंगर, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम, बिहार सरकार के मंत्री दीपनारायण सिंह सरीखे बड़े राजनीतिज्ञ और विद्वानों के आने से क्लब की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, कई प्रकार के लाभ भी हुए. इतनी अच्छी विरासत होने के बावजूद, रोईंग क्लब का वर्तमान दीनहीन दशा में है. हालांकि संस्था रूप में अब भी ये जीवित है, वर्तमान में विजय कुमार अग्रवाल इसके सचिव हैं, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर इसाकी स्थापना की गई थी, वो आज फलीभूत होता नहीं दिख रहा. बीते दिनों स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार और जिलाधिकारी रमण कुमार ने रोईंग क्लब और मोतिझील का निरीक्षण किया. मंत्री श्री कुमार ने रोईंग क्लब और मोतीझील दोनों के संरक्षण के लिए योजना बनाने की बात कही. अब देखने वाली बात ये होगी कि मंत्री जी का वादा रोईंग क्लब के लिए कितना कारगर होता है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में भी मची है डेरा सच्चा सौदा की अंधेरगर्दी

संजय सोनी

गुरमित राम-रहीम के डेरा सच्चा सौदा की पंथ भक्ति की आंधी न केवल हरियाणा में चल रही थी, बल्कि इसने बिहार के कई जिलों को भी अपनी जद में ले रखा है. सहरसा, मधेपुरा, घोड़ासान व सीतामढ़ी जैसे जिलों में गुरमित राम-रहीम के अनुयायियों की बड़ी तादाद है. गुरमित राम-रहीम को दो साध्वियों संग दुष्कर्म के आरोप में जब गिरफ्तार किया गया और हरियाण के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में सघन छापामारी हुई, तो यहां के अनुयायियों में भी रोष देखने को मिला.

हरियाणा में भले ही आलीशान डेरा हो. लेकिन बिहार के कोसी प्रमंडल मुख्यालय सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत दिवारी मौजा के महादलित टोला में स्थित गुरमीत राम-रहीम का डेरा उसके अनुयायियों से भरा रहता है. इसके अलावा गुरमित राम-रहीम के अनुयायी बिहार के कई जिलों में भी डेरा बनाकर अरदास करते रहते हैं. गुरमित राम-रहीम के गिरफ्तार होने से पहले तक इन डेरों में स्थानीय संसाधन से भंडारे एवं सत्संग का आयोजन होता रहा है. सहरसा जिले के कहरा प्रखंड क्षेत्र के दिवारी,

कांप व बसौना में करीब साढ़े चार सौ से अधिक महिला-पुरुष बाबा गुरमीत के अनुयायी हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां डेरे में हमेशा लोग 'मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुवर राम-रहीम तुम्हारी चरणों में' गाते रहते थे. लेकिन हरियाणा के सिरसा में छापेमारी और गुरमीत राम

रहीम की गिरफ्तारी के बाद यहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है. यहां कुछ बाबा के अनुयायी मिले, जो अब भी मानते हैं कि बाबा निर्दोष है और उसे जानबुझकर फंसाया गया है. मधुसूदन यादव, सुमन कुमार, महेंद्र राम, विजय यादव, नुनु देवी, रंजन देवी आदि लोगों ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा कि बाबा को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. हम सबों को पूर्ण विश्वास है कि वे जल्द से जल्द न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित हो जाएंगे.

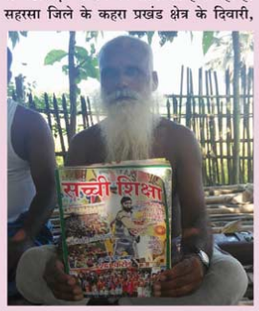

गौर करने वाली बात ये है कि बिहार में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना और इसका प्रचार-प्रसार बहुत पुराना है. जिस आदमी ने यहां डेरे की शुरुआत की, वो गुरमीत रामरहिम नहीं, बल्कि डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही मुर्शिद-ए-कामिल शाह सतनाम जी महाराज का शिष्य था. सहरसा के कहरा प्रखंड के बसौना में डेरा की स्थापना गुरमीत राम रहीम के जन्मोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2012 को हुई थी. हालांकि यहां के लोगों ने बताया कि यहां गत 40 सालों से अरदास आयोजित किया जाता रहा है. इस डेरा के कर्ता-धर्ता दिवारी गांव निवासी मधुसूदन यादव करीब 40 साल पहले अपने पुत्र कैलाश यादव के साथ मजदूरी करने हरियाणा गए थे. वहां वे डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही मुर्शिद-ए-कामिल शाह सतनाम जी महाराज के सम्पर्क में आए और उनसे बहुत प्रभावित हुए. गांव लौटने के बाद भी वे डेरा की भक्ति में डूबे रहे. मधुसुदन यादव ने बाकी गांव वालों के मन में भी डेरा सच्चा सौदा प्रति आदर जगाने का काम किया और लोग भी बाबा के भक्त बनते गए. मधुसुदन यादव के बेटा कैलाश का सिरसा स्थित डेरा आना-जाना लगा रहता है. वो वहां से जारी की जाने वाली खबरों और आदेशों को यहां के भक्तों को बताता है. पंचकुला की तरह बसौना स्थित डेरा में भी शाह सतनाम जी महाराज के पवित्र अवतार दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को सर्व धर्म संगम का आयोजन होता रहा है. हर महीने के प्रथम रविवार को यहां सत्संग का आयोजन भी होता है. लेकिन बाबा की गिरफ्तारी के बाद से सब बंद है. जब से गुरमीत राम-रहीम और हनीप्रीत पर कानूनी शिकंजों का दौर चला है, तभी से इस डेरा में भी बाबा के भक्त निराश हैं और अभी डेरा से जुड़े सभी काम बंद पड़े हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

अस्थि रोग से बचना है तो करें व्यायाम
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
R N SUPERSPECIALIY HOSPITAL
Khazpura, Near shiv mandir Pillar no 24, Patna

डॉ. अवध किशोर प्रसाद
एम.एस. ऑर्थो

पटना, खाजपुरा से ऑर्थो के कुशल चिकित्सक डॉ. अवध किशोर प्रसाद ने आज के व्यस्त लाईफ पर चर्चा की और बताया कि आजकल कामकाजी और शहरी लोगों की दिनचर्या ज्यादा व्यस्त हो गयी है. ऐसे लोग व्यायाम पर ध्यान नहीं देते है. यही वजह है कि आज के लोगों में हड्डियों से संबंधित दर्द और तकलीफ की शिकायत बढ़ती जा रही है. युवाओं में बढ़ता मोटापा, खानपान में असंतुलन और दिनचर्या से गायब होता व्यायाम ये तीन कारण हैं जो हमारे हड्डियों को कमजोर करते हैं. ऐसी समस्या पहले वृद्धों को हुआ करती थी, लेकिन कॉरपोरेट परिवेश और कम्प्युटर पर बढ़ती निर्भरता की वजह से आज 20 से 35 वर्ष के युवा भी इसके चपेट में आने लगे हैं. इससे बचने के लिये हमें शारीरिक ढांचे के अनुसार व्यायाम करना चाहिए. हफ्ते में कम से कम चार-पांच दिन सुबह में लगभग चार किलोमीटर पैदल तो अवश्य चलना चाहिए. साथ ही कैलसियम युक्त भोजन तो अवश्य लेना चाहिए. दुध, सोयाबिन और मछली का सेवन तो अवश्य करना चाहिए. डॉ. किशोर ने बताया यहां ऑर्थो से सबंधित हर रोग का इलाज है। बच्चों में होने वाले पैर दर्द के बारे में बताया कि बच्चों के विकास के साथ साथ उचित मात्रा में विटामिन युक्त भोजन नहीं मिलने से उन्हें दर्द की शिकायत होती है कमर दर्द के कुछ कारण उन्होंने बताये- बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अधिक चिंता, मानसिक दबाव और थकावट महसूस करते है उससे उनकी कमर की मांसपेशियों में खिचावट तनाव आ जाता है, जो उनकी कमर दर्द का मुख्य कारण होता है. दूसरा कमर पर अधिक बोझ लादकर चलने से या कंधो पर अदिक दबाव डालने से भी कमर दर्द में समस्या उत्पन्न होती है. तीसरा जोड़ों का घिस जाना, अधिक मोटापा और रीढ़ की हड्डी का खिसक जाना भी कमर दर्द का कारण है. चौथा व्यायाम की कमी, कमर में मोच आना या बार बार झटके महूसस कर्ण भी इस कार्ड को बुलावा देता है.घंटो तक बैठे रहना, पूर्ण आराम ना करना और संतुलित आहार का अभाव■ भारती

ACOBA CAP/SYP/INJ
Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ASRFEN-P
Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM
Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX
Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

'मैं और मेरा' के चक्रव्यूह में सृजन

अनंत विजय

आज के साहित्यिक परिदृश्य पर अगर नजर डालें तो 'मैं', 'मेरा' और 'मेरी' की ध्वनियों का कोलाहल सुनाई देता है. ज्यादातर लेखक अपनी किताब की प्रशंसा कर रहे होते हैं, कोई अपनी कहानी की तारीफ कर रहा होता है, तो कोई खुद ही सार्वजनिक रूप से अपने कविता संग्रह को बेहतरीन बताकर प्रशंसा बटोरने में लगा होता है. हिंदी साहित्य में इस तरह के माहौल को देखते हुए यह बात सहज रूप से सामने आती है कि कृति का महत्व गौण होता चला जा रहा है. वयक्ति जो कि लेखक है, वो ज्यादा प्रबल होता जा रहा है. रचना बोलेगी लेखक नहीं की प्रवृत्ति नेपथ्य में चली गई है. सृजन का महत्व या सृजनात्मकता की चर्चा कितनी और क्यों कम होती जा रही है, इसपर बात करने और गौर करने की आवश्यकता है. समकालीन साहित्यिक परिदृश्य में 'मैं' और 'मेरा' के साहित्यिक माहौल को देखते हुए मुझे नामवर सिंह जी का एक व्याख्यान याद आ रहा है, जो उन्होंने 18 अप्रैल 1982 को जबलपुर में मध्यप्रदेश साहित्य के एक आयोजन में दिया था. तब नामवर सिंह जी ने कहा था- 'शायद 1920 और 1930 के दौरान यह 'मैं' साहित्य में ज्यादा अर्थ के साथ गूंजता था. जब निराला ने 'तुम और मैं' कविता लिखी थी तो 'तुम' तो खैर रहा ही होगा, लेकिन 'मैं' जितने गर्व के साथ और गर्वीले स्वर में बोलता था, उसका अंदाजा आज भी आप उस कविता को पढ़कर लगा सकते हैं.' हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक विशेष प्रकार की कविता लिखी गई थी और वह बड़ी 'मैं' प्रधान कविता हुआ करती थी, जिसे राजनीतिक चिंतन के लोग व्यक्तिवाद का दौर कह सकते हैं. साहित्य में एक जमाने में 'मैं' की बहुत प्रधानता थी और उसमें सार था, तत्व था. व्यक्ति अपनी अस्मिता को पहली बार इस रूप में महसूस कर रहा था कि उसे व्यक्त कर सके. धीरे-धीरे असलियत का पता चला और मालूम हुआ कि 'मैं' उतना विराट हिमालय के समान नहीं है. उसके पीछे जो शक्ति थी- राष्ट्रीय शक्ति थी, सामाजिक शक्ति थी. लेकिन इस वक्त साहित्य में जो 'मैं' और 'मेरा' गूंज रहा है, उसके पीछे सिर्फ सिर्फ आत्ममुग्धता है. पिछले दिनों एक हिंदी आलोचक से इस विषय पर ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बेहद तल्ख शब्दों में हिंदी साहित्य की मौजूदा पीढ़ी को हिंदी साहित्य की 'आत्ममुग्ध पीढ़ी' तक करार दे दिया था. इसके पीछे उनके अपने तर्क थे, जिसपर बहस तो हो सकती है, पर उसको सिरे से खारिज करना मुश्किल लग रहा था.

'मैं' और 'मेरा' का नतीजा यह है कि आज के लेखक अपने वरिष्ठ लेखकों को पढ़कर उनकी रचनाओं से आगे जाने का कोई उपक्रम करते दिख नहीं रहे हैं. वो तो बस अपनी ही पीढ़ी के लेखकों के कंधों पर पांव रखकर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हैं. साहित्य की जिस परंपरा की बात लगातार होती रहती है, उस परंपरा को भी देखने समझने की कोशिश नहीं दिखाई देती है. परंपरा को रूढ़ि मानकर ग्रहण करने की बजाए त्यागने की प्रवृत्ति जोर मारती दिखाई देती है. त्यागने से ज्यादा नकारने की. लेकिन यह नकार लॉजिकल नहीं है, बल्कि सिर्फ खुद की तारीफ में किया जाने वाला है. हिंदी कहानी में अब तक तो सिर्फ परंपरा को ही समकालीन बनाकर पेश किया जाता रहा है. अगर हम निर्मल वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु को छोड़ दें, तो हिंदी कहानी की परंपरा को किसी ने भी झकझोरने की कोशिश नहीं की. लीक से हटकर चलने या फिर अपनी राह बनाने की बात करना तो दूर की बात है. आज के ज्यादातर लेखक अपने समकालीन को तो नहीं ही पढ़ते हैं, अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों की रचनाओं को भी नहीं पढ़ते हैं. उनका तर्क यह होता है कि दूसरे लेखकों की रचनाओं को पढ़ने से उनकी रचनात्मकता प्रभावित होती है. अगर एक मिनट के लिए इस तर्क को मान भी लिया जाए, तो समकालीन रचनाकारों को पढ़ने में क्या दिक्कत है.

'मैं' और 'मेरा' का नतीजा यह है कि आज के लेखक अपने वरिष्ठ लेखकों को पढ़कर उनकी रचनाओं से आगे जाने का कोई उपक्रम करते दिख नहीं रहे हैं. वो तो बस अपनी ही पीढ़ी के लेखकों के कंधों पर पांव रखकर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हैं. साहित्य की जिस परंपरा की बात लगातार होती रहती है, उस परंपरा को भी देखने समझने की कोशिश नहीं दिखाई देती है. परंपरा को रूढ़ि मानकर ग्रहण करने की बजाए त्यागने की प्रवृत्ति जोर मारती दिखाई देती है. त्यागने से ज्यादा नकारने की. लेकिन यह नकार लॉजिकल नहीं है, बल्कि सिर्फ खुद की तारीफ में किया जाने वाला है. हिंदी कहानी में अब तक तो सिर्फ परंपरा को ही समकालीन बनाकर पेश किया जाता रहा है. अगर हम निर्मल वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु को छोड़ दें, तो हिंदी कहानी की परंपरा को किसी ने भी झकझोरने की कोशिश नहीं की.

दूसरी जो प्रवृत्ति इस आत्ममुग्धता के पीछे है, वो है पुरस्कृत होने की चाहत. ज्यादातर लेखक पुरस्कृत होना चाहता है, छोटा बड़ा, मंझोला किसी भी प्रकार का कोई पुरस्कार मिल जाए. पुरस्कार के लिए जब आकांक्षा जोर मारती है, तो उसके पीछे यह मनोविज्ञान काम करता है कि वो निर्मल और रेणु या फिर निराला और दिनकर के समकक्ष हो गया है या उतना ही महान लेखन कर रहा है. पुरस्कार पाने की चाहत में सारे तरह के दंद-फंद अपनाए जाने लगते हैं और रचनात्मक कहीं पीछे छूटती चली जाती है. आज की इस 'आत्ममुग्ध पीढ़ी' के रचनाकारों में एक खास किस्म का एरोगेंस भी दिखाई देता है, बदतमीजी की हद तक. वो खुद को विद्वान ही नहीं मनाते, बल्कि यह अपेक्षा भी रखते हैं कि दूसरे भी उनको ज्ञानी मानें और उसी हिसाब से उनके साथ बर्ताव किया जाए. मन में इस तरह का भाव झूठी और प्रायोजित प्रशंसा से उपजता है और इस भाव के पैदा होते ही लेखक की रचनात्मकता बाधित होनी शुरू हो जाती है. बाधित रचनात्मकता को जब छद्म विद्वता बोध का साथ मिलता है, तब उससे जन्मती है पुरस्कृत होने की चाहत और इस चाहत के वशीभूत होकर शुरू होती है पुरस्कार पाने की गोलबंदी. तय मानिए कि जब साहित्य में गोलबंदी या घेरेबंदी शुरू हो जाए, तो उसका संक्रमण काल शुरू हो जाता है. इस संक्रमण काल को आप उस दौर की रचनाओं में आसानी से लक्षित कर सकते हैं.

जरूरत इस बात की है कि आज की आत्ममुग्ध पीढ़ी के रचनाकार अपने समकालीनों और पूर्ववर्तियों को पढ़ें और उनको रचनात्मक स्तर पर चुनौती पेश करें. अगर ऐसा हो पाता है, तो समकालीन साहित्य का परिदृश्य बदल सकता है और कुछ अच्छी रचनाएं सामने आ सकती हैं. उन्हें यह बात समझ में नहीं आती है कि साहित्य लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी साधना है, जिसमें फल कब मिलेगा यह तय नहीं होता है. इन दिनों जो लोग कहानी या उपन्यास लिख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर को साहित्य साधना से कोई लेना देना नहीं है. वो तो तप के पहले ही वरदान के आकांक्षी हुए जा रहे हैं. कुछ नए नवेले प्रकाशकों ने हल्के और लोकप्रिय विषयों पर लिखवाकर ऐसे लेखकों की आकांक्षाओं को और बढ़ावा दिया है. कुछ दिन पहले एक साहित्यिक पत्रिका में एक लेखिका ने अपने साक्षात्कार में अपनी ही रचनाओं को महान करार दिया था और अपने से वरिष्ठ और अपेक्षाकृत ज्यादा लोकप्रिय लेखक के उपन्यास को फ्लॉप तक कह डाला था. यह आत्ममुग्धता ही तो है. यही नहीं है, वल्कि साहित्य में तो अब तारीफ के लिए भी यत्न प्रयत्न किए जाते हैं. पूरा का पूरा समूह साथ होकर तारीफ के पुल बांधता चलता है. कई साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक एक पूरी पीढ़ी को आत्ममुग्ध पीढ़ी बनाने के मुजरिम भी माने जा सकते हैं.

'मैं' और 'मेरा' के चक्कर मे रचनाएं काफी कमजोर हो रही हैं. पिछले दस साल की कितनी कहानियां पाठकों को याद हैं? कहानी का स्तर कितना गिरा है. दो चार कहानीकारों को छोड़ दें, तो कहानी के नाम पर जिस तरह की सामग्री पाठको को पेश की जा रही है, इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत है. कहानी की दुनिया में कहानीकार धूमकेतु की तरह प्रकट होते है, एक दो कहानियों से चमकते हैं और फिर धूमकेतु की ही तरह साहित्यिक परिदृश्य से बिला जाते है. आज कहानियां थोक के भाव से लिखी जा रही हैं, लेकिन लगभग सभी कहानियों को पढ़ने के बाद निराशा होती है. हर युग में अच्छी कहानियां लिखी जाएं, यह आवश्यक नहीं है. लेकिन कहानी को लेकर जो विवेक है उसका बचना जरूरी है. यही विवेक आज खतरे में है. आज के कहानीकारों के अनुभव बहुत सीमित दिखाई पड़ते हैं. चालू और तुरत-फुरत लोकप्रियता हासिल करने वाली रचनाएं ज्यादा आ रही हैं. क्लासिक का फैसला तो खैर समय के साथ होता है, लेकिन कालजयी रचना के संकेत तो मिलने ही लग जाते हैं. इस तरह के संकेतों वाली रचनाओं का नहीं होना हिंदी साहित्य के लिए चिंता का सबब है. इस चिंता को दूर करने के लिए जरूरी है कि नए लेखकों और पुराने लेखकों के बीच संवाद हो. इस तरह के संवाद के लिए साहित्यिक आयोजन बेहतर मंच हो सकते हैं. संवाद से ही परंपरा को मजबूती मिलती रही है. मुझे लगता है कि अगर एक बार साहित्य में पीढ़ियों के बीच संवाद शुरू हो गया, तो तमाम तरह की बाधाएं तो दूर होंगी ही, 'मैं' और 'मेरा' से भी साहित्य को आजादी मिलेगी, क्योंकि संवाद में 'मैं' 'मैं' ज्यादा देर तक चल नहीं पाता है, उसके लिए एकालाप की आवश्यकता होती है. ■

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

आरटीआई से पाएं बीपीएल सर्वेक्षण का विवरण

चौथी दुनिया ब्यूरो

गरीबी रेखा से नीचे वाली लिस्ट यानि बीपीएल में नाम शामिल कराना गरीबों के लिए एक बड़ी समस्या है. गांवों में जहां ज्यादातर लोगों में जागरूकता का अभाव है, वहां कई लोग सिर्फ इसलिए सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बीपीएल में उनका नाम नहीं होता. वहीं ऐसे भी मामले देखने में आते हैं, जहां कई सुविधासम्पन्न लोग भी बीपीएल कार्डधारक हैं और वे खुलआम गरीबों का हक मार रहे हैं. इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि गरीबों में जागरूकता का अभाव है, बल्कि यह भी है कि बीपीएल लिस्ट में नाम शामिल करने की पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार के जाल में फंसी है. इसलिए लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते. लेकिन अगर आरटीआई का सहारा लें, तो बीपीएल में नाम शामिल कराने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जा सकती है. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के बारे में बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप बीपीएल सर्वेक्षण का विवरण प्राप्त कर सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

..... ग्राम में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

1. उपरोक्त गांव में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) के कितने कार्डधारी हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. कार्डधारक का नाम
   ख. पिता का नाम
   ग. कार्ड संख्या
   घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट)
2. उपरोक्त कार्डधारियों का 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस सम्बन्ध में कार्डधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं.
3. उपरोक्त गांव में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) के परिवारों का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं, साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बताएं?
4. 'गरीबी रेखा से नीचे' (बीपीएल) के परिवारों के सर्वेक्षण के समय परिवारों के चयन के लिए क्या मापदंड/मानक बनाए गए हैं? इस सम्बन्ध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
5. उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरान्त क्या कोई पुनः निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हां, तो समस्त दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
6. पुनः निरीक्षण (रिव्यू) के सम्बन्ध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.
7. सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाई की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.... है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

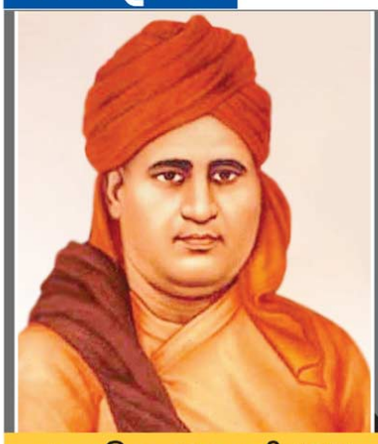

पुण्यतिथि विशेष

धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती

जन्मदिन- 12 फ़रवरी 1824
पुण्यतिथि- 30 अक्टूबर 1884

चौथी दुनिया ब्यूरो

शिवरात्रि के दिन पूरे परिवार के साथ मंदिर गया वो बालक सभी के सो जाने के बाद भी जगा रहा. वो भगवान शिव को देखना चाहता था, क्योंकि उसे बताया गया था कि भगवान की मूर्ति के सामने चढ़ाए गए प्रसादों का भोग वे स्वयं करते हैं. इसलिए वो बालक भगवान शिव द्वारा प्रसाद ग्रहण की घटना का साक्षी बनना चाहता था. लेकिन कुछ देर के बाद ही उसकी जिज्ञासा उदासीनता में बदल गई, जब उसने देखा कि भगवान शिव के सामने चढ़ाए गए प्रसाद कुछ चूहे खा रहे हैं. वो बालक सोचने लगा कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो मानवता की रक्षा कैसे करेगा. उस बालक ने इस विषय पर बहुत विचार-विमर्श किया, अपने बड़ों से बहस भी की. इस बालक का नाम था मूलशंकर, जो आगे चलकर महान समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के रूप में जाने गए.

दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फ़रवरी 1824 को मोरवी (मुम्बई की मोरवी रियासत) के पास काठियावाड़ क्षेत्र (जिला राजकोट), गुजरात में हुआ था. उनके पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था. उनके पिता एक कर-कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे. अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से दयानंद सरस्वती जीवन-मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे. ये उनके माता-पिता के लिए चिन्तित का कारण बन गया. उन्हें लगा कि शादी करा देने से वे घर-गृहस्थी के काम में व्यस्त हो जाएंगे. इसलिए किशोरावस्था के प्रारम्भ में ही उनकी शादी कराने का निर्णय लिया गया. लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और उन्होंने 1846 में घर छोड़ दिया. उनके जीवन में नया मोड़ आया जब वे गुरु विरजानन्द से मिले. गुरुवर ने उन्हें पाणिनी व्याकरण, पातंजल-योगसूत्र तथा वेद-वेदांग का अध्ययन कराया. गुरु विरजानन्दके ने उन्हें कहा कि मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा होगी कि तुम सीखी हुई विद्या को सफल करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो. महर्षि दयानन्द ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत् 1932 (10 अप्रैल 1875) को गिरगांव मुम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की. आर्यसमाज के नियम और सिद्धांत प्राणिमात्र के कल्याण के लिए हैं. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना.

महर्षि दयानन्द ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों और रूढ़ियों-बुराइयों को दूर करने के लिए निर्भय होकर उन पर आक्रमण किया. वे संन्यासी योद्धा कहलाए. उन्होंने जन्मना जाति का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्ण-निर्धारण की बात कही. वे दलितोद्धार के पक्षधर थे. उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रबल आंदोलन चलाया, बाल विवाह, सती प्रथा का निषेध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया. उन्होंने ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण तथा प्रकृति को अनादि तथा शाश्वत माना. वे तैत्रवाद के समर्थक थे. उनके दार्शनिक विचार वेदानुकूल थे. उन्होंने यह भी माना कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं तथा फल भोगने में परतंत्र हैं. महर्षि दयानन्द सभी धर्मानुयायियों को एक मंच पर लाकर एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे. उन्होंने इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) दरबार के समय 1878 में ऐसा प्रयास किया था. सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि उनके अमर ग्रंथ हैं. वे योगी थे और प्राणायाम पर उनका विशेष बल था. वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे. राष्ट्रीय जागरण की दिशा में उन्होंने सामाजिक क्रान्ति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया. उनकी शिक्षा सम्बन्धी धारणाओं में प्रदर्शित दूरदर्शिता, देशभक्ति तथा व्यवहारिकता पूर्णतया प्रासंगिक और युगानुकूल हैं. महर्षि दयानन्द समाज सुधारक तथा धार्मिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक तो थे ही, वे प्रचंड राष्ट्र वादी और राजनैतिक आदर्शवादी भी थे. उन्होंने 1875 में एक महान समाज सुधारक संगठन आर्य समाज की स्थापना की. उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना. कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा सन्यास को उन्होंने अपने दर्शन का चार स्तम्भ बनाया. उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में 'स्वराज्य' का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया.

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही है. कहा जाता है कि पराधीन आर्यावर्त (भारत) में यह कहने का साहस सम्भवत: सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ही किया था कि आर्यावर्त (भारत), आर्यावर्तियों (भारतीयों) का है. हमारे प्रथम स्वतंत्रता समर, सन 1857 की क्रान्ति की सम्पूर्ण योजना भी स्वामी जी के नेतृत्व में ही तैयार की गई थी

और वे ही उसके प्रमुख सूत्रधार भी थे. वे अपने प्रवचनों में श्रोताओं को प्राय: राष्ट्रवाद का उपदेश देते और देश के लिए मर मिटने की भावना भरते थे. 1855 में हरिद्वार में जब कुम्भ मेला लगा था तो उसमें शामिल होने के लिए स्वामी जी ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी. रास्ते में उन्होंने स्थान-स्थान पर प्रवचन किए तथा देशवासियों की नब्ज टटोली. उन्होंने यह अनुभव किया कि लोग अब अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके हैं और देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने को आतुर हो उठे हैं. हरिद्वार में उन्होंने पांच ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की, जो आगे चलकर सन 1857 की क्रान्ति के कर्णधार बने. ये पांच व्यक्ति थे नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहब, तात्या टोपे तथा बाबू कुंवर सिंह. इसी बातचीत में यह तय किया गया कि फिरंगी सरकार के विरुद्ध सम्पूर्ण देश में सशस्त्र क्रान्ति के लिए आधारभूमि तैयार की जाए और उसके बाद एक निश्चित दिन सम्पूर्ण देश में एक साथ क्रान्ति का बिगुल बजा दिया जाए. जनसाधारण तथा आर्यावर्तीय (भारतीय) सैनिकों में इस क्रान्ति की आवाज को पहुंचाने के लिए 'रोटी तथा कमल' की भी योजना यहीं तैयार की गई. इस सम्पूर्ण विचार विमर्श में प्रमुख भूमिका स्वामी दयानन्द सरस्वती की ही थी.

मार्च 1873 में एक ईसाई पादरी ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड नार्थब्रुक से कलकत्ता में स्वामी जी की मुलाकात करवाई. इधर-उधर की कुछ औपचारिक बातों के उपरान्त लॉर्ड नार्थब्रुक ने विनम्रता से अपनी बात स्वामी जी के सामने रखी. उसने कहा, अपने व्याख्यान के प्रारम्भ में आप जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्या उसमें आप अंग्रेजी सरकार के कल्याण की भी प्रार्थना कर सकेंगे. गर्वनर जनरल की बात सुनकर स्वामी जी सहज ही सब कुछ समझ गए. उन्हें अंग्रेजी सरकार की बुद्धि पर तरस भी आया, जो उन्हें ठीक तरह नहीं समझ सकी. उन्होंने निर्भीकता और दृढ़ता से गवर्नर जनरल को उत्तर दिया- मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता. मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे देशवासियों की निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य जातियों के समुदाय में आर्यावर्त (भारत) को सम्माननीय स्थान प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो. सर्वशक्तिशाली परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के जुए से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों.

स्वामी जी जोधपुर नरेश महाराज जसवन्त सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे. वहां उनके नित्य प्रवचन होते थे. कभी-कभी महाराज जसवन्त सिंह भी उनके चरणों में बैठकर उनके प्रवचन सुनते. दो-चार बार स्वामी जी भी राजमहलों में गए. वहां उन्होंने नन्हीं नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवन्त सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा. स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा. उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्हीं से सम्बन्ध तोड़ लिए. इससे नन्हीं स्वामी जी के बहुत अधिक विरुद्ध हो गई. कहा जाता है कि इसके बाद उसने स्वामी जी के रसोइए कलिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिला कर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया. इसके बाद स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहां का चिकित्सक भी शक के दायरे में रहा. उस पर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा. बाद में जब स्वामी जी की तबियत बहुत खराब होने लगी, तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया. मगर तब तक काफी विलम्ब हो चुका था. 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वामी जी ने अंतिम सांस ली. आज वे नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख युग-युगांतर तक लोगों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

ठंड के मौसम में बुज़ुर्गों की देखभाल

चौथी दुनिया ब्यूरो

ठंड का मौसम बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक होता है. सर्दी में हार्ट अटैक, हाइपोथर्मिया, फ्लू और दमे के दौरे के मामले काफी बढ़ जाते हैं, जो बुजुर्गों पर अक्सर भारी पड़ते हैं. ऐसे में हमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है. ठंड के मौसम में सामान्य रोगियों की संख्या तो घट जाती है, लेकिन गंभीर रोगियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. बुजुर्ग सर्दी में अक्सर सांस नहीं आने की शिकायत करते हैं जिसका कारण ज्यादातर दिल की समस्या या दमे का अटैक होता है. डॉक्टरों का कहना है कि सर्दियों में पड़ने वाला कोहरा दमा रोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. इस दौरान अस्पतालों में वृद्ध रोगियों की संख्या में लगभग 25 फीसदी का इजाफा हो जाता है. इस मौसम में हृदय रोग का भी खतरा होता है. साथ ही इस दौरान स्ट्रोक और निमोनिया का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है.

ऐसे मौसम में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. हृदय रोगियों खासतौर से बुजुर्गों को छाती में दर्द हो, तो डॉक्टर को दिखाएं. खानपान में सावधानी बरतें, तली चीजों का परहेज करें. हृदय रोगों के लिए नियमित जांच कराएं और नियमित दवा दें. सांस फूलने, बाएं कंधे, हाथ या सीने में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. हृदय और किडनी के रोगी तरल पदार्थों की मात्रा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें.

सर्दियों में बुजुर्गों को हाइपोथर्मिया का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिसका कारण सिर्फ सर्दी से पर्याप्त बचाव के अलावा बुजुर्गों के

सर्दियों में प्रदूषण और कोहरे के बढ़ने से दमा यानि अस्थमा के रोगियों को अटैक पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है. इससे बचने के लिए सर्दी की शुरूआत में ही अपने डॉक्टर के पास जाकर दवा की उचित मात्रा पूछ लें और सर्दी के लिहाज से क्या सावधानी और परहेज बरतना है, निश्चित कर लें. सांस के रोगी कोहरे में निकलने से बचें और विशेष रूप से एलर्जी वाली जगहों पर न जाएं. हर समय दवा या इन्हेलर अपने पास रखें. सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. बुजुर्ग हृदय रोगी सुबह की सैर एकदम बंद कर दें. ठंड में जल्दी सो जाएं और देर से उठें.

क्रियाकलापों का कम हो जाना और ली जा रही दवाओं के दुष्परिणामों की सही जानकारी न होना होता है. हाइपोथर्मिया में शरीर अचानक ठंडा पड़ जाता है और बेहोशी के साथ साथ हृदय गति धीमी हो जाती है. हाइपोथर्मिया बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो सकता है. इससे बचने के लिए वृद्धजन घर से बाहर निकलने से बचें और यदि बाहर जाना अत्यधिक आवश्यक हो तो निकलते समय कई लेयर्स में ऊनी कपड़े पहनें. धूप निकलने के बाद ही धीरे-धीरे सैर करें. इसके अलावा गर्म पेय का अधिक सेवन करें.

कई बार तेज ठंड के कारण पैरों और हाथों की अंगुलियां नीली पड़ जाती हैं और उनमें दर्द और खुजली होती है. इससे बचने के लिए मोजे और दस्ताने पहनने बेहद जरूरी होते हैं. समस्या बढ़ने पर गर्म पानी से सिकाई करें लेकिन ध्यान रहे कि पानी अत्यधिक गर्म न हो, नहीं तो यह समस्या घटने के बजाय बढ़ जाती है.

सर्दियों में प्रदूषण और कोहरे के बढ़ने से दमा यानि अस्थमा के रोगियों को अटैक पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है. इससे बचने के लिए सर्दी की शुरूआत में ही अपने डॉक्टर के पास जाकर दवा की उचित मात्रा पूछ लें और सर्दी के लिहाज से क्या सावधानी और परहेज बरतना है, निश्चित कर लें. सांस के रोगी कोहरे में निकलने से बचें और विशेष रूप से एलर्जी वाली जगहों पर न जाएं. हर समय दवा या इन्हेलर अपने पास रखें. सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. बुजुर्ग हृदय रोगी सुबह की सैर एकदम बंद कर दें. ठंड में जल्दी सो जाएं और देर से उठें. गर्म कपड़े पहनें और कानों को अवश्य ढक कर रखें. बुजुर्गों की दवा के बारे में घर में रहने वाले सभी सदस्यों को पता होना चाहिए. खाने में हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च और केसर जैसी गर्म चीजों का अधिक प्रयोग करें.

इसके अलावा सामान्य रूप से भी बुजुर्गों को सर्दियों से बचाने के लिए कमरे का तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखें. इसके लिए हीटर में या दीवार पर थर्मामीटर का होना जरूरी है. अगर बिजली चली गई है, तो किसी अन्य तरीके से कमरे को गर्म रखें. साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि अगर आपने कमरे को अंगीठी या किसी ऐसे ईंधन से गर्म किया है, जिसमें धुआं होता हो तो धुएं को बाहर निकालने के लिए खिड़की या दरवाजा हल्का सा खुला रखा जाए और ड्रायनेस न हो, इसके लिए किसी चौड़े, खुले बर्तन में पानी भरकर वहां रखें. कमरे को गर्म करना बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य का मामला मानकर चलें न कि लग्जरी यानी आराम का मामला. फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार व्यायाम करें. बुजुर्गों को फ्लू और निमोनिया का टीका लगवाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

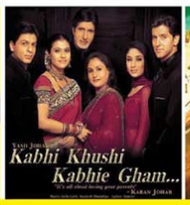

सिल्वर स्क्रिन पर शाहरुख़ और काजोल की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है

यह बाज़ीगर आज भी बॉलीवुड का किंग खान है

इस साल जनवरी में शाहरुख़ की फिल्म रईस ने जब बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और फिल्म सुपरहिट रही, तो उनके विरोधियों के मुंह बंद हो गए. इसके बाद किंग खान ने सभी को ये बता दिया कि उनको बॉलीवुड का किंग खान कोई ऐसे ही नहीं कहा जाता. हांलाकि उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा सकी जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. उनके फैंस आज भी उनसे उतना ही प्यार करते है जितना पहले करते थे. शाहरुख़ खान अपने करियर में लगभग हर तरह के किरदार निभा चुके हैं. फिर वह चाहे रोमांटिक किरदार हो या फिर विलेन, वे सभी किरदारों को बखूबी निभा लेने में माहिर हैं.

प्रवीण कुमार

जन्मदिन विशेष
2 नवंबर 1965

बॉलीवुड के किंग खान का जलवा आज भी करोड़ो लोगों में बरकरार हैं. अगर उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न भी चले तो भी उनकी दीवानगी लोगों के दिलों से कम नहीं होती है. शायद यही वजह है कि शाहरुख़ खान 2 नंवबर 2017 को 52 साल के होने जा रहे हैं और बढ़ती उम्र के बावजूद उनके फैंस की संख्या दिनों दिन बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही है. इतना ही नहीं, उनके फैंस हर साल शाहरुख़ के जन्मदिन का बड़ा बेसबी से इंतजार करते हैं. शाहरुख़ का जन्मदिन उनके लाखों-करोड़ों फैंस देश-विदेशों में अपने तरीके से मनाते हैं. इतना ही नहीं मुंबई में स्थित उनके घर मन्नत पर उनकी एक झलक पाने के लिए भी उनके फैंस हर दिन बड़ी संख्या में उनका इंतजार करते हैं.

शाहरुख़ खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था. उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्माद खान है. उनके पिता पेशावर, पाकिस्तान से थे. उनकी मां का नाम लतीफ फ़ातिमा है. उनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम शहनाज लालारूख है और वे भी शाहरुख़ के साथ मुंबई में ही रहती हैं. शाहरुख़ ने एक बार ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया था कि उनके पिता पठानी और मां हैदराबादी हैं.

शाहरुख़ खान की शुरूआती पढ़ाई सेंट कोलम्बस स्कूल, दिल्ली से हुई है. उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया लेकिन उनका ज्यादातर समय दिल्ली थियेटर एक्शन ग्रुप में बीतता था जहां से उन्होंने थियेटर निर्देशक बैरी जॉन के सानिध्य में अभिनय के गुर सीखे. इसके बाद उन्होंने जामिया मीलिया इस्लामिया से जनसंचार में स्नाकोत्तर की पढ़ाई शुरू तो की लेकिन अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह छोड़ दिया.

शाहरुख़ खान को उनके 52वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई

शाहरुख़ एक ऐसे अभिनेता रहें हैं जिनके प्रशंसक हर उम्र और हर वर्ग के लोग हैं. ख़ासकर, लड़कियां उनकी ख़ासी दीवानी हैं. बावजूद इसके शाहरुख़ का किसी के साथ अफेयर या प्रेम संबंध नहीं रहा है. वे अपनी पत्नी के लिए हमेशा से वफादार रहे हैं और अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं. शाहरुख़ ने गौरी से शादी की है जो हिन्दू-पंजाबी परिवार से आती हैं. उनके 3 बच्चे हैं-आर्यन, सुहाना और अबराम. फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सबसे अच्छा पिता भी माना जाता है क्योंकि वे अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और उनके साथ अच्छा समय भी व्यतीत करते हैं.

शाहरुख़ खान हिन्दी फिल्मों के अभिनेता होने के साथ-साथ निर्माता और टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं. उन्हें लोग प्यार से बॉलीवुड का बादशाह, किंग खान के अलावा कई अलग अलग नामों से भी उन्हें पुकारते हैं. शाहरुख़ ने अपने करियर में सिल्वर स्क्रिन पर लगभग सभी तरह के किरदारों को जिया है. साल 2014 में एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख़ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर हैं. लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी वैक्सक की मूर्ति भी स्थापित है.

शाहरुख़ ने अपने जीवने में इस मुकाम तक पहुंचने में बड़ी मेहनत की है. ये बात कम लोगों को ही पता होगी कि साल 1992 में शाहरुख़ की फिल्म *दीवाना* से पहले *दिल आशना है* को रिलीज होना था लेकिन किसी वजह से यह फिल्म समय पर रिलीज ना हो सकी और उनकी फिल्म दीवाना पहले रिलीज हो गई. फिल्म हिट रही, शाहरुख़ के साथ ऋषि कपूर और दिव्या भारती मुख्य भूमिका में थी. इसके बाद अक्टूबर माह में उनकी फिल्म *दिल आशना है* रिलीज हुई. लेकिन अफसोस की बात है कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औंधे मुंह गिरी. इस फिल्म को ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था. साल 1992 में किंग खान की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें दो हिट और दो फिल्में फ्लॉप रहीं.

इसके बाद शाहरुख़ की फिल्में कुछ समय तक लगातार बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन करती जा रही थी. ऐसे में शाहरुख़ की फिल्म *बाज़ीगर* ने बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी. एंट्री भी ऐसी कि बस सब देखते ही रह गए. किसी ने सोचा भी नहीं था कि शाहरुख़ फिल्म में विलेन की भूमिका में जबरदस्त तरीके से छा जाएंगे. बाज़ीगर एक थ्रिलर-सस्पेंस फिल्म थी जिसमें शाहरुख़ ने एक अभिनेता होने के साथ-साथ ख़तरनाक आशिक विलेन की भूमिका को भी बख़ूबी निभाया. फिल्म सुपरहिट रही और शाहरुख़ की एक अलग इमेज भी बॉलीवुड में स्थापित हो गई. इसी साल उनकी दूसरी फिल्म डर भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. इस फिल्म में भी शाहरुख़ ने नेगाटिव भूमिका निभाकर सनी देओल को कड़ी टक्कर दी. अब शाहरुख़ निर्माताओं के लिए विलेन की भूमिका के लिए पहली पसंद बनते जा रहें थे. आगे चलकर उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें उन्होंने विलेन की भूमिका अदा करते हुए मारे गए. ये सभी फिल्में बॉक्स आफिस पर ख़ूब चली.

इसके अलावा शाहरुख़ को उनके फैंस रोमेंटिक फिल्मों में ज्यादा पसंद करते हैं. शाहरुख़ ने जब भी बॉक्स ऑफिस पर रोमांस का तड़का बिखेरा, तब तब बॉक्स ऑफिस मालामाल हुआ. सिल्वर स्क्रिन पर अगर रोमांस के मामले में किंग खान की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई है तो वह सिर्फ अभिनेत्री काजोल के साथ. इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड में ख़ूब याद किया जाता है. इन दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है. लेकिन अब यह जोड़ी कम ही दिखाई देती है. अब हालिया दौर में शाहरुख़ ने दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा आदि अभिनेत्रियों के साथ फिल्मों में जोड़ी बनाई है.

इसमें किसी को कोई शक नहीं कि किंग खान का फिल्मी करियर सफल रहा है. वह बॉलीवुड में पिछले दो दशक से भी ज्यादा का समय बिता चुके है. शाहरुख़ ने अपने सफल करियर में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी है जिनमें *दीवाना, बाज़ीगर, डर, कभी हां कभी ना, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, करण अर्जुन, परदेश, कोयला, दिल तो पागल है, यस बॉस, कुछ कुछ होता है, बादशाह, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, चलते चलते, कल हो ना हो, मैं हूं ना, वीर-जारा, कभी अलविदा ना कहना, डॉन, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, माई नेम इज खान, रा-वन, डॉन-2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले, डियर जिंदगी* और *रईस* फिल्में प्रमुख हैं.

इस साल किंग खान की दो फिल्में रिलीज हो चुकी है *रईस* और *जब हैरी मेट सेजल*. लेकिन उनकी फिल्म रईस ही हिट रही. शाहरुख़ इस समय अपने नए प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं. आनंद एल राय ने शाहरुख़ खान के साथ अपने आगामी फिल्म की घोषणा की है. सूत्रों की मानें तो शाहरुख खान की इस फिल्म का नाम होगा- बटला. जिसका मतलब होता है छोटा. फिल्म में शाहरुख खान एक बौने आदमी का किरदार निभा रहे हैं. जबकि उनके साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की फिल्म में होने की आशंका है. शाहरुख़ खान की इस फिल्म का बजट 150-160 करोड़ बताया जा रहा है. माना जा रहा है, यह बॉलीवुड की सबसे मंहगी फिल्मों में शामिल हो सकती है. वैसे भी किंग खान को एक अरसा हो गया है बॉलीवुड में तहलका मचाए. अगर उनकी पिछली फिल्मों में रईस को छोड़ दिया जाए तो उनकी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में एकदम ठंडी रही हैं. वे चेन्नै एक्सप्रेस या हैप्पी न्यू ईयर जैसा हंगामा करने में पूरी तरह रहे हैं.

इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि शाहरुख़ खान सलमान की तरह ही रिमेक फिल्में की ओर रूख करने जा रहे हैं. ख़बरों की माने तो वे तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में काम कर सकते हैं. ख़बरें आ रही थीं कि उन्होंने इसके हिंदी राइट्स ख़रीद लिए हैं. लेकिन विक्रम वेधा बनाने वाले स्टूडियो ने ट्वीट करके इसका खंडन किया है: हमने विक्रम वेधा के किसी भी भाषा के अधिकार किसी को भी नहीं बेचे हैं. हम ख़ुद इसे प्रोड्यूस करेंगे. आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी. वैसे बता दें कि एक समय अपने करियर में हिचकोले खा रहे सलमान खान को भी संकट से निकालने का श्रेय साउथ की रीमेक वॉन्टेड को ही जाता है. वॉन्टेड के बाद सलमान खान को पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिला. उम्मीद करते हैं, शाहरुख को विक्रम वेधा करने के लिए मिल जाए.■

शाहरुख़ बॉक्स ऑफिस के ही नहीं, अवाइर्स के भी बादशाह है. यहां देखें किंग की अवाइर्स लिस्ट, जो उन्होंने जीते हैं.

- शाहरुख़ खान ने 9 स्टार स्क्रिन अवॉर्ड्स जीते हैं.
- शाहरुख़ ने रिकॉर्ड 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी जीते हैं.
- इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवाइर्स की ओर से शाहरुख़ ने 4 अवॉर्ड्स जीते हैं.
- जी सिने अवॉर्ड्स की ओर से 12 और एक स्पेशल अवॉर्ड्स किंग खान ने अपने नाम किए.
- शाहरुख़ के खाते में 5 बॉलीवुड मूवी अवॉर्ड्स भी शामिल
- ग्लोबल इंडियन फिल्म अवॉर्ड्स की ओर से शाहरुख़ ने 2 अवॉर्ड्स अपनी झोली में डाले

● *इसके अलावा शाहरुख़ के खाते में कई ऐसे अवार्ड है, जिसकी एक लंबी लिस्ट तैयार की जा सकती है.*

feedback@chauthiduniya.com